SHRI BAKAR ALI MIRZA (Secondrabad): I want to oppose the motion for extension of time. The Deputy Prime Minister who was Chairman of the Administrative Reforms Commission submitted a special report with a special plea that it should be taken up immediately. Three years have passed and even the preliminary stages have not passed. If the Government can give an assurance that this will be taken up in this session, I have no objection for the extension of time. Since no such assurance is given, I want to oppose this motion. So much mudslinging is going on and it should be brought to an end.

MR. SPEAKER : The question is :

"That this House do further extend the time appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill to make provision for the appointment and functions of certain authorities for the investigation of administrative action taken by or on behalf of the Government or certain public authorities in certain cases and for matters connected therewith, upto the 29th March, 1969."

The motion was adopted

12.24 hrs.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

MR. SPEAKER: We take up further consideration of the motion of thinks on the President's Address.

I would like to bring to the notice of the hon. Members that we have 4 hours and 50 minutes—the whole of today—for the debate on the president's Address. The Prime Minister will reply tomorrow. But, in the meanwhile, I will have to tell the hon. Members that some parties have still time, 20 to 25 minutes each. Swatantra party has got 23 minutes; Jan Sangh, 24 minutes; DMK, 27 minutes; PSP, 16 minutes, and unattached Members, nearly an hours—57 minutes. Two or three Members came and complained to me that they are not at all getting any chance to speak and some parties, every time, in the name of unattached Members, take up the time. Therefore, I propose to give their due time to the unattached Members and also call the back-benchers who have not spoken at all.

I would also like to appeal to the Congress Members. They have got only one hour and within that one hour, if the hon. Minister wants to intervene, I will not be in a position to provide time separately for him. Kindly excuse the Chair. Do not put the Chair in an embarrassing position. If the Congress party has got one hour and if the Ministers are intervening, you will have to provide a place for them.

श्री रामजी राम (अकबरपुर) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा को मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। अभिभाषण के आखिर में पैरा 35 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें यह कहा गया है कि गांधी जी के सपनों के भारत का निर्माण करें और हर आदमी का दुख दूर करने, हर आंख का आंसू पोंछने की भी कोशिश करें। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहां पर महात्मा गांधी का नाम लिया गया है लेकिन महात्मा गांधी जो चाहते थे, जिस तबके के उद्धार के सिलसिले में उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया उसके बारे में यहां इस अभिभाषण में कहीं कोई तस्किरा नहीं है जैसे अछूतों का उद्धार। मैंने देखा यहां दिल्ली में वाल्मीकि मन्दिर है और हरिजन कालोनी है उस वाल्मीकि मन्दिर में जहां महात्मा गांधी रहा करते थे, उसके बगल में ठीक एक तरफ तो यह हिन्दुस्तान जहां सवर्ण हिन्दू रहते हैं और ठीक उसके दूसरी ओर जहां वाल्मीकि निवास करते हैं वह पाकिस्तान सा बना हुआ है। यानी वहां बिलकुल किसी भी ढंग से कहीं भी उसमें न कोई विकास का कार्यक्रम है और न उनको इन्सान बनाने के लिए कोई भी कार्यक्रम वहां लागू किया गया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अछूतोद्धार की

बात तो दूर रही, इन बीस सालों में छुआछूत जो एक जघन्य अपराध घोषित हुआ है उसको दूर करने के लिए न तो इस तरफ के हमारे माननीय सदस्य-गण और न उस तरफ के माननीय सदस्य-गण ने कोई सक्रिय कदम उठाया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके ऊपर कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। इसका साफ अर्थ है कि वह तबका हिन्दुस्तान का जो आज भी 17 करोड़ है और जो आज समाज में सभी स्तर पर अछूता छोड़ दिया गया है, जिनकी जिन्दगी आज भी जानवर से भी बदतर है, उसके ऊपर कहीं भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनके विकास के सिलसिले में कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि उनमें अधिकतर खेत मजदूर हैं। इसमें खेत मजदूरों की समस्याओं के ऊपर तो कुछ नहीं कहा गया। उसमें यह भी कहा गया है कि 1968-69 में 61 लाख एकड़ और जमीन पर खेती की जायेगी। लेकिन उस जमीन पर खेती करने वाले कौन लोग होंगे? खेती में विकास की बात कही जाती है, उत्पादन की बात कही जाती है। लेकिन मूल रूप में जो खेती में लगे हुए हैं खेत मजदूर उनके विकास की बात और उनको जमीन देने की बात नहीं कही गई है। मैं यह चाहूंगा कि अगर वाकई हमारी यह सरकार और वह माननीय कैबिनेट के हमारे साथी जो हरिजनों का प्रतिनिधित्व करने वाले उसमें मौजूद हैं अगर वाकई में वह इस चीज को चाहते हैं तो यह जरूरी है कि इन चीजों को वह रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में पेश करने के लिए सरकार को बाध्य करें वरना वहां से कुर्सी छोड़ कर हट जायं। जैसे हम लोग यहां पर अछूतों की जिन्दगी बिता रहे हैं उनको भी इसी तरह से बिताना चाहिए। यह नहीं हो सकता है कि एक तरफ तो यह 17 करोड़ इन्सान जिनकी हिमायत करने वाले लोग वहां मौजूद हैं, वह सिर्फ यह करके टाल जाते हैं कि उन्हें कुर्सी मिली हुई है और दूसरी तरफ यह 17 करोड़ इन्सान जानवर की जिन्दगी बिता रहे हैं। उनके लिए वर्तमान कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं। उनको खेती करने के लिए जमीन देने की कोई व्यवस्था नहीं। आज गांवों में जायं, आप देखेंगे कि सत्तर-सत्तर, अस्सी-अस्सी साल के पेड़ मौजूद हैं। अछूतों की कदीम बस्ती है मगर उनकी आबादी कागजात में दर्ज नहीं की जाती है बल्कि बड़े लोगों की उसमें फसलें दर्ज कर दी जाती हैं और गांव में इस तरह उनका सारा हक छीन लिया गया है। वे आवाज उठाते हैं लेकिन उनकी आवाजों की कोई सुनवाई नहीं है। वे असहाय और निहत्थे इन्सान वहां के बड़े लोगों के ऊपर ज़िन्दा हैं, न उनके पास खेत हैं और न उनके विकास के लिये कोई कार्यक्रम है। इनकी समस्याओं पर खास तौर पर ख्याल किया जाना चाहिये।

परिवार नियोजन की बात कही गई है और बड़े जोर शोर से ढिंढोरा पीटा गया है कि इसमें बड़ी सफलता मिली है। अध्यक्ष महोदय, आप किसी भी एक जिले को ले लीजिये और वहां जो नसबन्दी हुई है, उसके आंकड़े देखिये। जो ज्यादा उम्र के बुढ्ढे हैं, जो उपज कर नहीं सकते, उन्हीं की नसबन्दियां की गई हैं और यहां यह ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि नसबन्दी बड़ी कामयाब हुई है। मैं इस बात को चेलेंज करता हूं, आप किसी भी जगह के आंकड़े उठाकर देख लीजिए।

जहां तक भाषा की बात है—उर्दू के बारे में हमारे उस तरफ के कांग्रेसी भाई भी बड़े जोर शोर से बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय का ध्यान इस बात की तरफ खींचना चाहता हूं कि जब वह राष्ट्रपति नहीं थे, उर्दू के मसले को लेकर 22 लाख दस्खतों को लेकर वह आये थे और कहा था कि उर्दू को इलाकाई ज़ुबान घोषित किया जाय, उसको मान्यता दी जाय और उसकी तरक्की के लिये साधन मुहिया किये जांय। लेकिन मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कांग्रेसी भाइयों से कहना पड़ता है, खास कर उस

[श्री रामजी राम]

तरफ बैठने वाले मुसलमान भाइयों से कहना पड़ता है कि जब डा० फरीदी जैसे आदमी मुस्लिम मजलिस जैसी जमायत की नींव डालते हैं तो यहां से लोग उसको तोड़ने के लिये क्यों जाते हैं, लेकिन 22 लाख दस्खतों को लेकर उर्दू को इलाकाई जुवान घोषित कराने की कोशिश करने वाले राष्ट्रपति महोदय ने संविधान की धारा 347 के तहत आज तक उसका कोई एलान क्यों नही किया ? यह बड़े अफसोस की बात है। हाथी के दांत दिखाने के और, खाने के और हैं। सिर्फ हरिजनों के वोट लेकर और मुसलमानों के वोट लेकर, उनको इस्तेमाल करके कांग्रेसी सरकार को बचाये रखने की कोशिश करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बौद्धों की समस्या की ओर भी आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। आज अगर कोई अछूत इसाई बनता है तो उसको वही मान्यता मिलती है, अगर कोई रामदासी सिख बनता है तो उसको वही मान्यता मिलती है, लेकिन आज अगर कोई अछूत इन्सान बनने को नया बौद्ध बनता है तो उसको वे सुविधायें नहीं मिलती हैं—मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है ?

अध्यक्ष महोदय, आज बेरोज़गारी, जात-पात और भ्रष्टाचार का बड़ा बोलबाला है। आज चौधरी चरण सिंह का नाम लिया जाता है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछड़े वर्ग कमीशन की रिपोर्ट अभी भी रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई है, जिस पर आज कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, लेकिन आज चौधरी चरणसिंह अगर पिछड़े वर्ग का नाम लेकर उत्तर प्रदेश में हावी होने का नाम लेते हैं तो उसको ये लोग फूटी आंखों देखने की कोशिश नहीं करते हैं। यह चौधरी चरण सिंह का सवाल नहीं है, यह पूरे पिछड़े वर्ग का सवाल है और 17 करोड़ इन्सानों का सवाल है जो अछूतों के रूप में जानवरों से बदतर जिन्दगी बिता रहे हैं। पूरा हिन्दुस्तान अब उनके हाथ में जाने वाला है, उनकी हुकूमत कायम होने वाली है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कायम होकर रहेगी।

किसी भी देश की उन्नति में सड़कों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज ऐसी बहुत सी पुरानी सड़कें हैं जो गांवों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, लेकिन बहुत खराब हालत में पड़ी हुई हैं। मेरे इलाके फैज़ाबाद में बहुत सी शाही सड़कें हैं जो बहुत खराब हालत में हैं और जिनके बनाये जाने के लिए बहुत जोरदार मांग की जा रही है, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। जब मैंने यह सवाल उठाया तो कहा गया कि वह चीन के करीब है, अगर चीन ने हमला किया तो क्या हश्र होगा। अगर ऐसी बात है तो आप सड़कें बनाना छोड़ दीजिये, अगर चीन और पाकिस्तान का इतना डर है तो सड़कें मत बनाइये। अध्यक्ष महोदय, ये सड़कें बहुत जरूरी हैं, उस इलाके के विकास के लिए इनका बनाया जाना बहुत जरूरी है। गांव के छोटे-छोटे काश्तकार रोज़ी-रोज़गार के लिए इनके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे, आज इन सड़कों के न होने से वे अपनी जगह पर ही बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनका कोई विकास नहीं हो रहा है।

आज हिन्दुस्तान के विकास के आंकड़े यह सरकार पेश करती है, प्रति व्यक्ति आय और खर्च के आंकड़े यह सरकार देती है और कहा जाता है कि हिन्दुस्तान की आबादी 51 करोड़ है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की आबादी 51 करोड़ नहीं है, हिन्दुस्तान की आबादी सिर्फ 20 करोड़ है और बाकी 31 करोड़ इन्सान जानवरों की तरह से रहते हैं, ये आंकड़े सिर्फ उन्हीं 20 करोड़ लोगों से ताल्लुक रखते हैं, इसलिये मैं इस बात को मानने के लिये

तैयार नहीं हूं कि हिन्दुस्तान की आवादी 51 करोड़ है । यह वेरोज़गारी और मंहगाई, जातिवाद किस की वजह से है, यह सरकार इसकी ज़िम्मेदार है, अगर ये चाहें तो हालात बदल सकते हैं, लेकिन यहां तो सिर्फ फ़र्ज़ अदायगी की बातें होती हैं । फर्ज़ अदायगी की बातें नहीं होनी चाहिये, इनको कार्य रूप में परिणत करने की बातें होनी चाहियें । आज जितनी बातें राष्ट्रपति के अभिभाषण में कही गई हैं, कम से कम उसका आधा तो कार्यरूप में चरितार्थ हो तो भारत का नक्शा बदल सकता है ।

हम समझते हैं कि हिन्दुस्तान की तरक्की हो रही है, हिन्दुस्तान आगे बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया के तमाम मुल्कों की तुलना में हिन्दुस्तान इतना बड़ा मुल्क होते हुए भी अभी बहुत पीछे है, ऐसा क्यों हैं ? आज जात-पात की बात कही जाती है, हिन्दू राष्ट्र की बात कही जाती है, हिन्दू-संस्कृति की बात कही जाती है, लेकिन इस हिन्दू संस्कृति, भारतीय संस्कृति की परम्पराओंने इस मुल्क के 17 करोड़ इन्सानों को जानवर बना दिया है, अब आगे यह चीज़ नहीं चल सकती, निकट भविष्य में बहुत जल्दी इसका पर्दा फ़ाश होगा, एक विस्फ़ोट होने वाला है जो इन चीजों को आगे नहीं चलने देगा । बाबा साहब अम्बेडकर का स्वप्न साकार होकर रहेगा ।

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, प्रेसिडेन्ट महोदय ने जो भाषण दिया है, उसके लिये धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं समर्थन करना चाहती हूं । बहुत ज़ोर से इस बात की टीका की गई है कि कुछ भी अच्छा होता है तो सरकार उसका श्रेय अपने ऊपर लेती है और यदि कुछ खराब हो जाता है तो दूसरों को उसका दोष देती है । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, प्रेज़िडेन्ट महोदय ने अपने भाषण के शुरू में ही कहा है कि जो कुछ भी अच्छा हुआ है, उसका श्रेय जनता को है, बड़ी बहादुरी के साथ लोगों ने काम किया है—

"The manner in which our people faced the difficulties with courage and fortitude is a matter for pride. Without their sacrifice and cooperation, their hard work, their basic good sense and patriotism, the plans and programmes of the Central and State Governments could not have borne fruit."

अध्यक्ष महोदय, किसी ने भी जनता की मेहनत का श्रेय सरकार को देने की कोशिश नहीं की है, इसलिए जनता का जो श्रेय है, वह तो है ही, लेकिन इसके साथ यह भी मानना पड़ेगा कि सरकार की भी ज़िम्मेदारी होती है और सरकार की मदद के बग़ैर जनता का काम कठिन हो जाता है । सरकार ने कुछ काम किया है, कुछ सरकारी नीतियां खेती वगैरह के बारे में, सफल हुई हैं, इस बात को स्वीकार करना होगा । बड़ी खुशी की बात है कि उत्पादन बढ़ा है, नये बीज किसानों को मिले हैं, जिनसे उत्पादन अधिक होता है, किसानों ने भी उन बीजों का इस्तेमाल किया और कर रहे हैं । लेकिन इसके साथ-साथ अगर सरकार थोड़ी और दृढ़ता से, मजबूती से फर्टिलाइज़र और पानी का इन्तज़ाम सबके लिए कर सके तो यह उत्पादन और भी तेज़ी से बढ़ सकता है और जहां आज हम बाहर से गल्ला लाते हैं, हम बहुत जल्दी बाहर गल्ला भेजने वाला देश बन सकते हैं । ऐसा मेरा विश्वास है । इसकी तरफ पूरा ध्यान होना चाहिए । इससे भी ज्यादा मुझे इस बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना है कि तीन मिलियन टन का बफर स्टाक जल्दी ही बन जायेगा, यह प्रेज़ीडेन्ट साहब ने कहा है । यह बड़ी खुशी की बात है लेकिन जो बफर स्टाक होगा क्या उसको कोई ध्यान से देखेगा भी कि जो पिछले साल का गल्ला हो वह पहले खर्च हो जाये और इस साल का गल्ला पीछे में खर्च हो । यदि नया गल्ला जो आयेगा वही खर्च होता जायेगा तो पुराना गल्ला सड़ता रहेगा । ऐसा हुआ है, इसलिए मैं यह बात कह रही हूं । बफर स्टाक का फायदा हमें तभी मिलेगा जबकि उसको उसी

[डा० सुशीला नैय्यर]

प्रकार से रखा जाये जैसा कि अपने घर में अनाज की देखभाल घर की मालकिन करती है। उसी तरह से कोई मालिक बनकर बफर स्टाक का संग्रह करे और उसका ठीक-ठीक इस्तेमाल हो ताकि जनता को सड़ा हुआ अनाज खाने के लिए मजबूर न होना पड़े। यह आवश्यक है। जैसे कि पहले कई दफा हो चुका है, उस तरह से गल्ला सड़ने न पाये, किसान की यह मेहनत बर्बाद न हो।

मैं एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहती हूं। हमारे देश की आमदनी बढ़ी है। यह कहा गया है कि पिछले साल 1393 करोड़ आमदनी बढ़ी है। यह अच्छी बात है लेकिन यह आमदनी कैसे बढ़ी है, इसका क्या इस्तेमाल हुआ है, उसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। किसान की भी कुछ आमदनी जरूर बढ़ी है क्योंकि अनाज के दाम सुधरे हैं। लेकिन अनाज से किसान की जो आमदनी बढ़ी है, उसका क्या इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से उसका सदुपयोग होना चाहिए, यह देखने की जरूरत है। प्रेजीडेन्ट महोदय ने कहा है :

> "The new prosperity in the rural areas will have to be harnessed to promote further growth, particularly among the smaller farmers and in the relatively backward regions. While encouraging a greater flow of genuine savings to sustain larger investment both in the public and the private sectors, the situation will have to be utilised to strengthen the financial position of both the Centre and the States."

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब से सरकार की तवज्जह आपके द्वारा इस बात की ओर दिलाना चाहती हूं कि देहातों में जो पैसा किसानों की जेब में गया है, वह किसान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिये। डिसेन्ट्रलाइज्ड तरीके से प्लानिंग करके उस पैसे से उन लोगों का जीवन सुधारने की कोशिश की जाये। वहां पर खेती-बाड़ी, सड़कों और स्कूलों को सुधारने की कोशिश की जाये तो किसान खुशी से और पैसा देने के लिए तैयार होगा। लेकिन अगर उस पैसे को उससे खींचकर केन्द्रीय और राज्य सरकारों के खाते में जमा करने की कोशिश की जायेगी तो उससे बड़ा रिजेन्टमेन्ट और विरोध होगा और बहुत पैसा आपको मिलेगा भी नहीं। मिसाल के तौर पर मैंने देखा है कि महाराष्ट्र सरकार ने जिला परिषदों से कहा कि सबके लिए पीने के पानी का इन्तजाम करना है लेकिन हमारे पास जितना पैसा है उसमें से हर एक जिले को इतना-इतना ही मिल सकता है। जिला परिषदों ने, जो टैक्स वे लेते थे, उससे दुगुना टैक्स लेकर, दुगुना पैसा वसूल करके लोगों को पानी पिलाया, क्योंकि उनकी समझ में यह बात आ गई कि हमको जनता के लिए यह काम करना है, इतना पैसा सरकार से मिलेगा, इतना पैसा हम लगा दें। अगर सरकार टैक्स दुगना करना चाहती तो इन्कलाब हो जाता। इसलिए जब लोग खुद समझ लेते हैं कि उनके अपने फायदे की चीज़ है तो वे उसे खुद करते हैं। ऐसी हालत में जो किसान का पैसा है वह किसान की ही बहबूदी, किसान की खुशहाली, किसान का देहात का जो जीवन है, उसको सुधारने में लगाया जाये, और अगर यह काम उसके सलाह मश्विरे से किया जाये तो और भी अच्छा काम हो सकेगा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज किसानों की जेब में जो पैसा गया है वह बुरी तरह से बह रहा है, बर्बाद हो रहा है। बहुत सारा पैसा तो शराब में बह रहा है। आप पंजाब, हरियाणा और दूसरी कई जगहों पर देखिये। आज दिल्ली में अशोका होटल वगैरह में वे लोग दो-दो, तीन-तीन दिन रहकर अपना पैसा खराब करते हैं। इसलिए बहुत जरूरत है इस बात की कि पूरी कोशिश की जाये कि उचित तरीके से उनके पैसे का इस्तेमाल हो। वह पैसा उनके बच्चों का जीवन सुधारने के लिए, उनका सामाजिक जीवन

सुधारने के लिए और उनका अपना जीवन सुधारने के लिए इस्तेमाल करना वे सीखें।

श्री रामगोपाल शालवाले (चान्दनी चौक): शराब बन्दी के लिए सरकार क्या कर रही है?

डा० सुशीला नैयर: शराब बन्दी के लिए जितना हमसे हो सकता है, वह कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपकी भी पूरी मदद और पूरे साथ की आवश्यकता है। जब हम और आप साथ मिलकर करेंगे तभी यह हो सकेगा, केवल एक तरफ से नहीं हो सकेगा। सरकार से भी हमें मिलकर यह काम कराना होगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां एक तरफ हमें खाद्यान्न बढ़ाने की आवश्यकता है, वहां दूसरी तरफ पापुलेशन की बढ़ोत्तरी को रोकने की भी आवश्यकता है। प्रेजीडेन्ट महोदय ने कहा है कि इस सिलसिले में काफी काम का फैलाव हुआ है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस चुनाव के सिलसिले में कई जगहों पर कई जिलों में मैं गई तो जो प्लान-पब्लिसिटी के लोग थे उन्होंने हमको बतलाया कि जब वे गांवों में जाते हैं तो गांव वाले उनको मार भगाते हैं और कहते हैं कि तुम तो फैमिली प्लानिंग वाले हो चले जाओ। उन लोगों को बतलाने पर और बहुत समझाने पर कि वे फेमिली-प्लानिंग वाले नहीं हैं, प्लान पब्लिसिटी वाले हैं, उनको गांवों में जाने दिया जाता है। ऐसा क्यों हुआ? मैं जानती हूं कि गांवों में परिवार नियोजन का इस किस्म का विरोध पहले नहीं था। मैं एक डाक्टर की हैसियत से गांवों में जाती थी तो बहनें घेर लेती थीं और पूछती थीं "हमें बताइये, कैसे और ज्यादा बच्चे न हों।" अब हमारे काम करने के तरीके में क्या गलती हुई हैं, जिससे यह विरोध खड़ा हुआ है? यह देखने की जरूरत है। आज इस प्रकार का विरोध क्यों होने लगा है? आज प्लान पब्लिसिटी वालों को कहना पड़ता है कि हम फेमिली-प्लानिंग वाले नहीं हैं, तभी उनको गांवों में घुसने दिया जाता है यह क्यों हुआ? कहा जायेगा कि कुछ विरोधियों ने फेमिली-प्लानिंग के खिलाफ बहुत प्रचार किया है। मैं जानती हूं कि जनसंघ ने ऐसा बहुत प्रचार किया है, लेकिन उनके प्रचार से ही इतना विरोध नहीं हो सकता। जरूर कोई न कोई गलती हमारे इस कार्यक्रम इम्प्लीमेन्टेशन में हुई है, हमारे काम करने के तरीके में हुई है। इस चीज को हमें देखना चाहिए, तभी परिवार नियोजन सफल हो सकता है। जो जनता के लीडर्स हैं, जो लोकल लीडरशिप है, अगर उनको साथ लेकर सरकार इस काम को करेगी तब जनता यह समझेगी कि यह उनके घर और परिवार को सुखी बनाने का तरीका है, इसमें उनका अपना ही लाभ है किसी और का नहीं। केवल सरकारी कर्मचारियों से यह काम नहीं हो सकता।

पब्लिक सेक्टर के सम्बन्ध में बहुत सारी बातें कही गईं। पब्लिक सेक्टर में बहुत कुछ अच्छा काम हुआ है, और आगे और भी अच्छा करने की आवश्यकता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट हैं उनका लाभ हमें तभी मिलेगा जबकि हम उनको फुल कैपेसिटी पर चलायेंगे। इस बात की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी कल ही यहां पर फर्टिलाइजर्स की बात हो रही थी। बहुत मेहनत करने के बाद, जो हमारा ट्रावनकोर वाला प्लान्ट है, उसकी 60 परसेन्ट कैपेसिटी इस्तेमाल हो रही है। और प्लान्ट्स में तो इतना भी नहीं हो रहा। तो फुल कैपेसिटी पर उनको कैसे चलाया जाये, इसको देखना होगा। दूसरे यह कि इन पब्लिक सेक्टर प्लान्ट्स में जो टेक्निकल लोग हैं उनको महत्व देने की आवश्यकता है। अगर वे लोग सारा समय, जो आई०ए०एस०एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, उन्हीं के नीचे दबे रहेंगे, उनको कोई स्वतन्त्रता नये विचारों को प्रयोग में लाने और योजनाओं को कार्यान्वित करने की नहीं रहेगी

[डा० सुशीला नैयर]

तो टेक्निकल लोगों को जो उत्साह होना चाहिये, प्रेरणा होनी चाहिए वह उन्हें मिल नहीं सकेगी। इस दृष्टि से एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है।

यहां पर टूरिज्म और टूरिस्ट्स की बात भी कही गई। इस बारे में मुझे इतना ही कहना है कि हम टूरिस्ट्स जो अपने यहां बुलायें लेकिन जो टूरिस्ट्स हमारे यहां आते हैं वे हिन्दुस्तान को, हिन्दुस्तान की संस्कृति देखने के लिए आते हैं परन्तु हम उनके लिए जहां-तहां विलायत का नमूना बनाने की कोशिश में हैं। यहां तक कि हम यह समझते हैं कि हम शराब पिलायेंगे तभी टूरिस्ट्स यहां आयेंगे। अगर उनको शराब ही पीनी होगी तो अपने घर पर ही पी लेंगे। यहां पर तो वे हिन्दुस्तानियत देखने के लिए आते हैं, यहां की सभ्यता और तौर-तरीका देखने के लिए आते हैं। आप उनको रहने के लिए साफ जगह दो, साफ पानी दो, साफ खाना दो। यह सब चीजें तो हों, लेकिन उसको शराब में बहा देना, गलत है। वे स्वयं भी इस चीज़ को महसूस करते हैं, खास तौर पर जब वे देखते हैं कि उनके साथ जो हिन्दुस्तानी बैठता है उसको शराब नहीं मिलती है, जबकि उनको स्वयं मिलती है। इसमें वे इम्बैरेस्ड फील करते हैं, शर्मिन्दा होते हैं।

अन्त में प्रेजीडेन्ट महोदय ने गांधी जन्म शताब्दी का जिक्र किया है, उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहती हूं। इस अवसर का लाभ उठाकर हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपनी पिछली 20-21 साल की गल्तियों को सुधार सकते हैं अगर हम अन्तर्मुख होकर देखें कि कौन सी गलती की हमने और कहां सही रास्ता छोड़ा। कैसे उसे दुरुस्त करें, इस बात को भी हम देखने की कोशिश करें। शांति की बातें होती हैं लेकिन शांति तो तभी स्थापित हो सकती है जब हम दृढ़ता से फैसला करलें कि अशांति के कारणों को हमें दूर करना है। अशांति के कारणों में जाति-पांति, भाषा वगैरह की समस्यायें हैं। इनको दूर करना कोई मुश्किल नहीं है अगर हम निश्चयपूर्वक, दृढ़ता से काम करें। मैं जानना चाहती हूं कि बम्बई में शांति भंग हुई इसमें क्या हमारा कुसूर नहीं है। हमें जहां फैसला करना चाहिए, वहां फैसला जल्दी क्यों नहीं करते हैं? अगर मैसूर और महाराष्ट्र का बार्डर है तो वह चीन और हिन्दुस्तान का तो बार्डर नहीं है या पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का बार्डर नहीं है इतना झगड़ने की, मारपीट करने की क्या जरूरत है? मैं नम्रता से कहना चाहती हूं कि जब आप एक जज को नियुक्त करते हैं फैसला देने के लिए उसके बाद क्या यह उचित है कि आप अपील करें कि दोनों तरफ के नेता बैठकर फैसला करें, शान्ति से झगड़ा निपटायें, इत्यादि। जब आप फैसला देने के लिए एक जज नियुक्त करते हैं तो उस फैसले को स्वीकार क्यों नहीं करते? सरकार का धर्म है कि जो इस प्रकार का जो फैसला हो उसको तुरन्त मंजूर किया जाये।

इसी प्रकार से चंडीगढ़ का सवाल है। इसका फैसला प्राइम मिनिस्टर पर छोड़ा गया है। मैं पूछती हूं कि इसको क्यों लम्बा किया जा रहा है? जो भी फैसला देना हो वह दे दिया जाय अर्थात् यह नगर एक को देना है, दूसरे को देना है या किसी को भी नहीं देना है अविलम्ब तय कर दिया जाना चाहिये। जाहिर है कि वक्त पर फैसला होने से शांति क़ायम रहेगी और जनता को भी पता हो जायेगा कि एक मापदंड से हम सब नापे जाते हैं। अलग-अलग गज से नहीं मापा जायगा। जनता को ऐसा यक़ीन होने से ही शांति बनी रहेगी। हमको गरीब, पिछड़े, दबे हुए और कुचले हुए इंसानों की तरफ़ पूरी तवज्जह देनी होगी। दादा कृपालानी ने ठीक ही कहा है कि क़ानून के ऊपर चल कर ही हम शान्ति कायम रख सकते हैं। इंसान की तरफ़ ध्यान देकर अगर हम अपना निज़ाम चलायेंगे तो हम अवश्य सफल होंगे और देश तेजी से और आगे बढ़ेगा।

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी (श्रीनगर) : जनाब सदर, मैं ऐवान का ज्यादा वक्त न लेते हुए राष्ट्रपति साहब के एड्रेस में जो जो बातें कही गयी हैं उनके मुताबिक सिर्फ इतना कहूंगा कि खुदा करे ऐसा हो ही हो। हिन्दुस्तान तरक्की कर रहा है खुदा करे तरक्की करे। हिन्दुस्तान में अमनोअमान हो और खुशहाली हो, खुदा करे ऐसा हो। बहरहाल मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। गल्ला ज्यादा पैदा हुआ अच्छा हुआ। अब तिजारत में हम आगे बढ़ रहे हैं अच्छा है। लेकिन दो, तीन बातों की तरफ मैं जनाब की तवज्जह और ऐवान की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। जाहिर है कि यह सब बातें तभी हो सकती हैं जबकि मुल्क की इंटेग्रेटी को किसी तरफ से खतरा न हो। न भारत को बाहर से खतरा हो, न पाकिस्तान से हो, न चीन से हो और न ही किसी और बाहर के मुल्क से हो। न ही उसे अन्दरूनी खतरा हो लेकिन अंदरूनी तौर पर हम देख रहे हैं कि बदकिस्मती से पिछले साल में सीमाओं के झगड़े, पानी के झगड़े, सेंट्रल-स्टेट रिलेशनशिप के झगड़े और दूसरे ऐसे झगड़े इतने बढ़ गये कि अगर उनको वक्त पर न रोका जाय और उनको बढ़ने दिया जाय तो हिन्दुस्तान की सालमियत और इंटेग्रेटी को सबसे बड़ा खतरा साबित होगा।

आज कल कुछ ऐसा हो गया है कि प्राबलम्स सामने हैं, हल भी मालूम है लेकिन हिम्मत से काम नहीं लिया जाता है और प्राबलम्स को प्रोलोंग किया जाता है। अगर आज एक प्राबलम है तो कल वही एक प्राबलम दस गुना बढ़ जाती है।

राष्ट्रपति ने इर्शाद फरमाया कि इस साल देश में 4 प्रांतों में मिडटर्म एलेक्शंस हुए। अच्छा हुआ, मिडटर्म एलेक्शंस होने थे। इसका कारण क्या है ? उन्होंने खुद बतला दिया कि यह डिफैक्शंस और गवर्नर्स हैं। अब अगर कांग्रेस पार्टी बरसरे इक्तदार हो और उसके बीस आदमी दूसरी तरफ चले जायें अथवा अपनी कोई दूसरी पार्टी बना लें या युनाइटेड फ्रन्ट पार्टी बरसरे इक्तदार हो और 20 आदमी उसके दूसरी तरफ चले जांय, कहने का मतलब यह है कि इस तरह से पार्टी डिफैक्शंस चलते रहने से किसी भी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है और हमने देखा कि इस कारण कई राज्यों में सरकारें खत्म हो गयीं। इसमें गवर्नर एक बड़ा कारण रहा है। अब अगर कहीं का गवर्नर अच्छा है तो उसने ऐसा नहीं होने दिया है लेकिन अगर गवर्नर इस किस्म का आदमी है कि वह एक पार्टीकुलर पार्टी को पसन्द करता है या वह उसकी मदद करना चाहता है तो उसका मेंटल एप्रोच भी कुछ ऐसा ही हो जाता है कि वह हर्डलस क्रीएट करके स्टेट को तबाह करता है, डेमोक्रेसी को तबाह करता है और लेजिस्लेचर को तबाह करता है। गवर्नर उसके लिए राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट भेजता है कि यहां राष्ट्रपति राज्य लागू करो। हरियाणा, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में इस तरह से डेमोक्रेसी को खत्म करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। करीब आधे हिन्दुस्तान को रूल कौन करते थे वह 6 आदमी ही उन पर रूल करते थे। इसलिए मैं आप से अर्ज करूंगा कि यह एक बहुत कंट्रोवर्शियल इश्यू रहा है कि यह गवर्नरों के ओहदे क्या हों। आप देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, पार्लियामेंट का चुनाव होता है और स्टेट लेजिस्लेचर्स का चुनाव होता है और हालांकि राज्यों में गवर्नमेंट्स चलाने के लिए ऐसे आदमियों को लगाया जाता है जिनकी कि काबलियत में मुझे कोई ऐतराज नहीं या जिनकी इंटेग्रेटी या दयानतदारी में मुझे कोई ऐतराज नहीं लेकिन सिस्टम ऐसा है और वक्त आया है जबकि इस सिस्टम को बदल दिया जाय। यह न कहा जाय कि रूलिंग पार्टी किसी एक शख्स को फेवर किया चाहती थी। जनता को यह कहने का

मौका न दिया जाय कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि एलैक्शन में हारा, जिसे कि लोगों ने रिजैक्ट कर दिया उसे रूलिंग पार्टी ने गवर्नर बना दिया। **ही वाज मेड गवर्नर ऑफ सच एंड सच स्टेट**। इस चीज को रोकने के लिए मैं जनाब की वसातत से ऐवान में एक सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरीके से राष्ट्रपति का इन्तखाब होता है, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का इन्तखाब होता है उसी तरीके से स्टेट्स के गवर्नर्स का भी इन्तखाब हो। उनका भी एलैक्शन हो और एलैक्टोरल कालिज वही हो जो कि उपराष्ट्रपति के हैं या राष्ट्रपति के हैं। उसमें दिक्कतें कोई न होंगी, उसमें पैसा नहीं पड़ेगा, उसमें खर्चा कुछ नहीं लगेगा सिर्फ इतना होगा कि बजाय दो वोट के शायद 14 वोट एक एक लेजिस्लेचर के मैम्बर को डालने पड़ेंगे। मेरा कहना है कि जब तक यह गवर्नर की पोस्ट कायम रखी जाती है तब तक यह राष्ट्रपति की पोस्ट की तरह से एलैक्टेड हो।

जहां तक यह डिफैक्शंस का ताल्लुक है राष्ट्रपति ने अपने एड्रैस में कहा है कि एक कमेटी बनी है। मुबारक हो लेकिन कमेटी बनाने की एक लम्बी चौड़ी हिस्ट्री है। अंग्रेजों के जमाने से हमने यह देखा है कि सरकार अगर किसी चीज को नहीं करना चाहती है तो वह एक कमेटी बना दिया करती है। फिर वह कमेटी रिपोर्ट देगी और उसके बाद गवर्नमेंट द्वारा उसको स्टडी किया जायगा। इस तरह से उस मामले को लटका दिया जाता है। लटका देने के लिटरल मतलब है **एंड इट**, खत्म कर दो। कहने का मकसद यह है कि इस तरह से मामले को लटकाया जाता है और लम्बा किया जाता है।

रूलिंग पार्टी का यह दावा है कि वह डिफैक्शंस के खिलाफ हैं। मैं उनके इस दावे को सही मानता हूँ लेकिन मेरा कहना है कि वह एक बिल लेकर यहां पर आयें और उसमें यह प्रोवाइड कर दें कि जो शख्स किसी पार्टी से कांग्रेस पार्टी में डिफैक्ट करता है तो उसी वक्त उसकी सीट खाली हो जाय और वह रीएलैक्शन सीक करे। अगर वह ऐसा न करे तो वोटर्स को राइट ऑफ रिकॉल दिया जाय और वह उस शख्स को जोकि एक अमुक पार्टी के मैनीफैस्टो और प्रोग्राम पर लेजिस्लेचर में चुनकर आया है और वह उस पार्टी को छोड़ता है तो उसके लिए यह ला बना दिया जाय कि उसी वक्त उसकी सीट खाली हो जायगी और उसे रीएलैक्शन सीक करना पड़ेगा। ऐसा ला न बनाने के लिए फंडामैंटल राइट्स की बात की जा सकती है तो मेरा कहना है कि वह फंडामैंटल राइट्स आपने 10 साल दबा कर रखे लेकिन उससे कोई हैरानी नही हुई। मैं आप से यह अर्ज करूंगा कि वक्त आया है कि डिफैक्शंस को एलैक्शन ला के तहत करप्ट प्रैक्टिस करार देकर डिफैक्टर को फौरी तौर पर मजबूर किया जाय कि वह अपनी सीट रिजाइन करे।

13 hrs.

आखिरी बात जो मैं एक मिनट में अर्ज करना चाहता हूं वह यह कि राष्ट्रपति ने अपने एड्रैस में मुल्क की तमाम आर्म्ड फोर्सेज के लिए कहा है कि वह प्रौपर ट्रिम में हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मौरेल उनका बहुत ऊंचा रहा है।

राष्ट्रपति ने जो कहा है कि हमने उनकी सर्विसेज की कंडिशन्स में इम्प्रूवमेंट किया है, इससे मुझे इत्तफाक नहीं है। हमारी आर्म्ड फोर्सेज, चाहे लेंड आर्मी हो, चाहे एअर हो या नेवी हो, अपनी जानें मुल्क पर कुर्बान करने के लिये, मुल्क के बचाव के लिए, अपनी-अपनी जगह खड़ी हैं, लेकिन उनके जो इमाल्युमेंट्स हैं जो उनके पेंशन रूल्स हैं, जो उनकी बाकी कंडि-शन्स आफ सर्विस हैं, वह पुलिस, होम गार्ड्स, बार्डर सिक्योरिटी फोर्स और दूसरे लोगों के मुकाबले में खराब हैं। मैं चाहता हूं कि पुलिस को और भी दिया जाये, बार्डर

सिक्योरिटी फोर्स को खुश रखा जाये, दूसरी जो ऐसी फोर्सेज हैं उनको भी खुश रक्खा जाये, लेकिन जहां आर्म्ड फोर्सेज का ताल्लुक है, उनकी तरफ तवज्जह देना भी जरूरी है। पता नहीं कल क्या होता है, कैसी डेवेलप हो रही हैं ईस्ट और वेस्ट में सिचुएशन, चीन क्या करेगा। जब तक हमारी आर्म्ड फोर्सेज प्रापर ट्रिम में नहीं होगी, उनका मोराल ऊंचा नहीं होगा और वह खुश नहीं। मैंने राइट फ्राम 1947 उनको ऐक्शन में देखा है, उनको मरते हुए देखा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि **वे आर नाट हैपी** क्योंकि उनकी कंडिशन्स आफ़ सर्विस, उनके सारे इमाल्युमेंट्स और बाकी बातें जो हैं दिल्ली की पुलिस से भी खराब हैं। दिल्ली पुलिस का आदमी चुशूल में लड़ने वाले एक सिपाही से तन्ख्वाह भी ज्यादा लेता है, राशन भी ज्यादा लेता है, वर्दी भी उस को ज्यादा अच्छी मिलती है, हर एक चीज ज्यादा अच्छी मिलती है, और उसको मरने का भी खतरा नहीं है। इसलिये मैं इस ऐवान से आपके जरिये से प्रार्थना करूंगा कि अगर असल में आप चाहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेज खुश रहे तो उनकी तरफ आपको तवज्जह देनी चाहिए, उनके इमाल्युमेंट्स बढ़ाये जायें। मैं नहीं चाहता कि दिल्ली के कांस्टेबल को कुछ न मिले, उनको और भी ज्यादा मिलना चाहिये, लेकिन इस महंगाई के जमाने में आर्म्ड फोर्सेज की तरफ भी आपको देखना चाहिये। पुलिस के लिए तो यह है कि अगर यहां पर उनकी फैमिली है तो मकान गवर्नमेंट को देना होता है, लेकिन आर्मी वालों के बारे में मैंने देखा है कि उनकी फैमिलीज हजारों की तादाद में दरबदर फिर रही हैं, उनको कहीं पर भी ठिकाना नहीं मिल रहा है।

[شری غلام محمد بخشی : (شری نگر)] جناب صدر- میں ایوان کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے راشٹرپتی کے ایڈریس میں جو جو باتیں کہی گئی ہیں ان کے متعلق صرف اتنا کہوں گا کہ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ہندوستان ترقی کر رہا ہے خدا کرے ترقی کرے۔ ہندوستان میں امن و امان ہو اور خوشحالی ہو خدا کرے ایسا ہو۔ بہر حال میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ غلہ زیادہ پیدا ہوا اچھا ہوا۔ اب تجارت میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اچھا ہے۔ لیکن دو تین باتوں کی طرف میں جناب کی توجہ اور ایوان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں تبھی ہو سکتی ہیں جبکہ ملک کی انٹیگریٹی کو کسی طرف سے خطرہ نہ ہو۔ نہ بھارت کو باہر سے خطرہ ہو نہ پاکستان سے ہو نہ چین سے ہو اور نہ کسی اور باہر کے ملک سے ہو۔ نہ ہی اسے اندرونی خطرہ ہو۔ لیکن اندرونی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے پچھلے سال میں سیماؤں کے جھگڑے۔ پانی کے جھگڑے سنٹرل اسٹیٹ ریلیشنشپ کے جھگڑے اور دوسرے ایسے جھگڑے اتنے بڑھ گئے کہ اگر ان کو وقت پر نہ روکا جائے اور ان کو بڑھنے دیا جائے تو ہندوستان کی سالمیت اور انٹیگریٹی کو سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوگا۔

آجکل کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ پرابلمس سامنے ہیں۔ حل بھی معلوم ہے لیکن ہمت سے کام نہیں لیا جاتا ہے اور پرابلمس کا پرولونگ کیا جاتا ہے۔ اگر آج ایک پرابلم ہے تو کل وہی پرابلم دس گنا بڑھ جاتی ہے۔

[شری غلام محمد بخشی]

راشٹرپتی نے فرمایا کہ اس سال دیش میں ۴ پرانتوں میں مڈٹرم الیکشن ہوئے۔ اچھا ہوا۔ مڈٹرم الیکشن ہونے تھے۔ اس کا کارن کیا ہے۔ انہیں نے خود بتلایا کہ وہ ڈیفکشنس اور گورنرز ہیں۔ اب اگر کانگریس پارٹی برسر اقتدار ہو اور اس کے بیس آدمی دوسری طرف چلے جائیں [اتھوا] اپنی کوئی دوسری ایک پارٹی بنالیں یا یونائٹڈ فرنٹ پارٹی برسر اقتدار ہو اور ۲ آدمی اس کے دوسری طرف چلے جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے پارٹی ڈیفکشنس چلتے رہنے سے کسی بھی گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس کارن کئی راجیوں میں سرکاریں ختم ہو گئیں۔ اس میں گورنر ایک بڑا کارن رہا ہے۔ اب اگر کہیں کا گورنر اچھا ہے تو اس نے ایسا نہیں ہونے دیا ہے۔ لیکن اگر گورنر اس قسم کا آدمی ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر پارٹی کو پسند کرتا ہے یا وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کا مینٹل اپروچ بھی کچھ ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ وہ ہرڈلس کریئیٹ کر کے اسٹیٹ کو تباہ کرتا ہے۔ ڈیموکریسی کو تباہ کرتا ہے اور لیجسلیچر کو تباہ کرتا ہے۔ گورنر اس کے لئے راشٹرپتی کے پاس رپورٹ بھیجتا ہے کہ یہاں راشٹرپتی راج لاگو کرو۔ ہریانہ۔ پچھمی بنگال۔ پنجاب۔ اتر پردیش اور بہار کے راجیوں میں اس طرح سے ڈیموکریسی کو ختم کر کے راشٹرپتی شاسن لاگو کیا گیا اور آپ دیکھئے ہمیشہ سے ان کو رول کون کرتے تھے۔ وہ ۶ آدمی ہی ان پر رول کرتے تھے۔ اس لئے میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ ایک بہت کنٹروورشیل ایشو رہا ہے کہ یہ گورنروں کے عہدے کیا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ راشٹرپتی کا چناؤ ہوتا ہے اپ راشٹرپتی کا چناؤ ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کا چناؤ ہوتا ہے اور اسٹیٹ لیجسلیچرس کا چناؤ ہوتا ہے اور حالانکہ راجیوں میں گورنمنٹس چلانے کے لئے ایسے آدمیوں کو لگایا جاتا ہے جن کی قابلیت میں مجھے کوئی اعتراض نہیں یا جن کی انٹیگریٹی یا دیانتداری میں مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن سسٹم ایسا ہے اور وقت آیا ہے جبکہ اس سسٹم کو بدل دیا جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ رولنگ پارٹی کسی ایک شخص کو فیور کیا چاہتی تھی۔ جنتا کو یہ کہنے کا موقع نہ دیا جائے کہ ایک ایسا ویکتی جو کہ الیکشن میں ہارا جسے کہ لوگوں نے ریجکٹ کر دیا اسے رولنگ پارٹی نے گورنر بنا دیا۔ <u>ہی واز میڈ گورنر آف رچ اینڈ بگ اسٹیٹ</u>۔ اس چیز کو رکنے کے لئے میں جناب کی وساطت سے ایوان میں ایک سجھاؤ دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے راشٹرپتی کا انتخاب ہوتا ہے۔ جس طریقہ سے اپ راشٹرپتی کا انتخاب ہوتا ہے اسی طریقہ سے اسٹیٹ گورنرس کا بھی انتخاب ہو۔ ان کا بھی الیکشن ہو اور الیکٹرل کالج وہی ہو جو کہ اپ راشٹرپتی کے ہیں یا راشٹرپتی کے ہیں۔ اس ہمارے دقتیں کوئی نہ ہوں گی اس میں پیسہ نہیں پڑیگا اس میں خرچہ کچھ نہیں لگے گا صرف اتنا ہوگا کہ بجائے دو ووٹ کے شاید ۱۴ ووٹ ایک ایک لیجسلیچر کے ممبر کو ڈالنے پڑینگے۔ میرا کہنا ہے

کہ جب تک یہ گورنر کی پوسٹ قائم رکھی جاتی ہے تب تک یہ راشٹرپتی کی پوسٹ کی طرح ایلیکیٹڈ ہو

جہاں تک ڈیفکشنس کا تعلق ہے راشٹرپتی نے اپنے ایڈریس میں کہا ہے کہ ایک کمیٹی بنی ہے۔ مبارک ہو لیکن کمیٹی بنانے کی ایک لمبی چوڑی ہسٹری ہے انگریزوں کے زمانے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سرکار اگر کسی چیز کو نہیں کرنا چاہتی ہے تو وہ ایک کمیٹی بنا دیا کرتی۔ پھر وہ کمیٹی رپورٹ دیگی اور اس کے بعد گورنمنٹ دوارا اس کو امنڈ کیا جائیگا۔ اس طرح سے اس معاملہ کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ لٹکا دینے کا لٹرل مطلب ہے کہ اینڈ اٹ ختم کردو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے معاملے کو لٹکا یا جاتا ہے اور لمبا کیا جاتا ہے۔

رولنگ پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ڈیفکٹنز کے خلاف ہیں۔ میں ان کے اس دعوے کو صحیح مانتا ہوں لیکن میرا کہنا ہے کہ وہ ایک بل لیکر یہاں پر آئیں اور اس میں یہ پرووائڈ کردیں کہ جو شخص کسی پارٹی سے کانگریس پارٹی میں ڈیفکٹ کرتا ہے تو اسی وقت اس کی سیٹ خالی ہوجائے اور وہ ری الیکشن سیک کرے اگر وہ ایسا نہ کرے تو ووٹرس کو رائٹ آف ریکول دیا جائے اور وہ اس شخص کو جو کہ ایک نامور پارٹی کے مینی فیسٹو اور پروگرام پر لیجسلیچر میں چن کر آیا ہے اور وہ اس پارٹی کو چھوڑتا ہے تو اس کے لئے یہ لاء بنا دیا جائے کہ اس وقت اس کی سیٹ خالی ہو جائیگی اور اسے ری الیکشن سیک کرنا پڑیگا۔ یہ بات نہ

کے لئے فنڈامینٹل رائٹس کی بات کی جاسکتی ہے تو میرا کہنا ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس آپ نے ایک سال دبا کر رکھے لیکن اس سے کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ وقت آیا ہے کہ ڈیفکشنس کو الیکشن لاء کے تحت کرپٹ پریکٹس قرار دیکر ڈیفکٹر کو فوری طور پر مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی سیٹ ریزائن کرے۔

آخری بات جو ایک منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ راشٹرپتی نے اپنے ایڈریس میں ملک کی تمام آرمڈ فورسیس کے لئے کہا ہے کہ وہ برابر ٹرم میں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مورل ان کا بہت اونچا رہا ہے۔

راشٹرپتی نے جو کہا ہے کہ ہم نے ان کی سروسیز کی کنڈیشن میں امپرومینٹ کیا ہے۔ اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ ہماری آرمڈ فورسیز۔ چاہے لینڈ آرمی ہو۔ چاہے ایئر ہو یا نیوی ہو۔ اپنی جانیں ملک پر قربان کرنے کے لئے۔ ملک کے بچاؤ کے لئے اپنی اپنی جگہ کھڑی ہیں لیکن ان کے جو امالیومینٹس ہیں جو ان کے پنشن رولس ہیں۔ جو ان کی باقی کنڈیشنس آف سروس ہیں۔ وہ پولیس۔ ہوم گارڈ۔ بارڈر سکیورٹی فورس اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں خراب ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پولیس کو اور بھی دیا جائے بارڈر سکیورٹی فورس کو خوش رکھا جائے۔ دوسری جو ایسی فورسیز ہیں ان کو بھی خوش رکھا جائے۔ لیکن جہاں تک آرمڈ فورسیز کا تعلق ہے ان کی طرف توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ پتہ نہیں کل کیسا

[شری غلام محمد بخشی]

ہوتا ہے۔ کیسی ڈیولپ ہو رہی ہے ایسٹ اور ویسٹ میں سچویشن۔ چین کیا کرے گا۔ جب تک ہماری آرمڈ فورسیز برابر ٹرم میں نہیں ہوں گی۔ ان کا مورل اونچا نہیں ہوگا اور وہ خوش نہیں ہوں گی۔ میں نے رائٹ فرام ۱۹۴۷ ان کو ایکشن میں دیکھا ہے۔ ان کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دے آر ناٹ ہیپی۔ کیونکہ ان کی کنڈیشن آف سروس ان کے سارے املیومینٹس اور باقی باتیں جو ہیں دہلی کی پولیس سے بھی خراب ہیں۔ دہلی پولیس کا آدمی جو شول میں لڑنے والے ایک سپاہی سے تنخواہ بھی زیادہ لیتا ہے۔ راشن بھی زیادہ لیتا ہے۔ وردی بھی اس کو زیادہ اچھی ملتی ہے۔ ہر ایک چیز زیادہ اچھی ملتی ہے اور اس کو مرنے کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ اس لئے میں اس ایوان سے آپ کے ذریعہ سے پرارتھنا کروں گا کہ اگر اصل میں آپ چاہتے ہیں کہ آرمڈ فورسیز خوش رہیں تو آپ کو توجہ دینی چاہئیے ان کے املیومینٹس بڑھانے چاہئیں۔ میں نہیں چاہتا کہ دہلی کے ایک کانسٹبل کو کچھ نہ ملے۔ ان کو اور بھی زیادہ ملنا چاہئیے۔ لیکن اس مہنگائی کے زمانہ میں آرمڈ فورسیز کی طرف بھی آپ کو دیکھنا چاہئیے۔ پولیس کے لئے تو یہ ہے کہ اگر یہاں پر ان کی فیملی ہے تو مکان گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے۔ لیکن آرمی کے بارے میں میں نے دیکھا کہ ان کی فیملیز ہزاروں کی تعداد میں دہلی میں دربدر پھر رہی ہیں۔ ان کو کہیں پر بھی ٹھکانہ نہیں مل رہا ہے۔

13.03 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[SHRI VASUDEVAN NAIR *in the Chair*]

MOTIN OF THANKS ON THEPRESIDENTS ADDRESS—*Contd.*

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): While supporting the various amendments so eloquently moved by my leader Shri Ranga to the motion of thanks to the President, I should like to make a few observations. In dealing with the foreign affairs of our country, the President reiterated the soundness of the Government's foreign policy "consistent with our sovereignty and territorial integrity on the basis of absolute non interference in each other's internal affairs."

Sir, this myth has been exploded when we find that India, which has championed the cause of others in their struggle for freedom and had the unique distinction of presenting the modern world with a leader no less than Mahatma Gandhi. was a silent spectator in the rape of Czechoslovakia by Russia and in throttling the democracy and freedom in that country. The way the interference has been going on day in day out in this country's domestic affairs by Radio Peace and Progress could not be tolerated by any self-respecting nation except probably by this country. Still, 15,000 square miles of Indian territory are in the forcible occupation of Red China. We hear every day armed and trained guerillas being infiltrated into Nagaland and Mizo area on a massive scale and up till now no action has been taken to stop this unlawful infiltration creating hostility inside our country. No action has been taken to oust the intruders from the sacred Indian soil, and still the pledge given to the nation in this House by Pandit Jawaharlal Nehru on the 14th of November, 1962 has yet remained unredeemed.

Still, we boast of the success of India's foreign policy. The President opened his speech with an optimistic note of the so-called economic recovery. His optimistic expectation is obviously based upon the upswing of production in the agricultural

sector, in 1967-68. In 1968-69 the Production has remained static. There has been no improvement in this field. The reason given is, the visitation of flood and drought.

Agriculture is India's basic industry. It provides food to our people, the raw material to our industries, gives employment to a vast section of the people and earns foreign exchange. Even after 22 years of Independence, India's agriculture is dependent on the vagaries of the monsoon. We have been chanting in this House, the mantram *"Kale Varshatu Parjanyaha,"* If credit has to go to anybody for the good performance in 1967-68, it must go to Providence for the good monsoon, and then to the hard-working kisans, whose new awareness of responsibiliry and adaptability to new and scientifice techniques and eagerness for more production are responsible for this performance.

The kisan has been shouting for water and if the kisans are kept assured of water-supply they can create a miracle and can easily wipe out the deficit in our food. The State Governments, with their limited resources, have been trying hard to provide irrigation facilities but it is the Centre's apathy, lack of appreciation, fixation of wrong priorities and indecision regarding the water disputes that are responsible for bringing in this setback. Water disputes like the Narmada, Krishna and Godavari have been hanging fire since so many years. Instead of any solution, they brought in politics to such disputes, and the impression has been created that the States with a stronger pull over the Centre get a lion's share whereas the other States get a raw deal. The Centre's action or inaction, instead of helping the food production, has put spokes in the wheel of this country's progress.

The President's Address has been conspicuous in the sense that there has been no indication that priorities will be given to agriculture in the next Plan. Though we have been told parrot-like since the last so many years that there would be self-sufficiency and self-sufficiency is round the corner, it has remained a moonshine. It will remain so unless and until the Government fully appraise the realities and take a bold decision and give priority in their expenditure so far as agriculture is concerned.

Is it not a fact that the Indian kisan has to buy fertilisers, diesel engines, pumps and sprayers at double the price if not more than double the price, than what is available outside the country ? It is a pity that this morning's newspaper has brought the news that agriculture is going to be taxed even more. These prerequisites are going to cost more to the agriculturists. What impetus is going to be given for more production ? Is it not that he has to pay his electric bill at a much higher rate than the industrialists for energising the pumps to lift water for his parched fields ? How can you expect him to grow food at a cheaper rate and provide raw material for industry ? In their 49th report, the Estimates Committee have criticised the lack of a sense of urgency in planning and development of fertilisers and said that that is causing very heavy drainage of precious foreign exchange to the tune of Rs. 225 crores, and up till now, as Shrimati Vijaylakshmi Pandit had pointed out once, this Government has been a prisoner of indecision, and no decision has been taken regarding the Mithapur Plant or the installation of the urea plant in the Talcher complex in Orissa. Even the Central Power and Research Station had made a recommendation that the cost-based Talcher complex would be the best and the cheapest and the most profitable one.

Just as we find that the agricultural sector has been shamefully neglected, we find that the tempo of industrial and commercial activity is at the lowest ebb. Prices have been sky-rocketing. The recent phenomenon of price stability of a few months back, which has been gloated over in the President's Address is a temporary phase, because only last week the President had suggested that the index of wholesale prices was at 205 and after a week it is now 207. So, there has been an increase in that regard.

[Shri P.K. Deo]

So, unless there is a basic shift in the thinking and action of Government, there is little hope of tiding over the various economic crises which have been harassing us so far and finding a solution thereto.

The purchasing power of the rupee has been going down with inflation, and it is extremely difficult for the low and fixed income group to have a bare subsistence. In twenty years the rich have been growing richer, but grinding poverty is the daily lot of the millions of Indians. The economic or socio-economic climate is more of concern and less of hope. Unending deficit financing has become the order of the day. No indication has been given that in the coming budget we would not resort to the printing press finance and no indication is there in the Address to put a stop to it. On the other hand, there has been this motivation when one says that inflation must go with development. We have seen in most countries that where there has been no inflation there has been more rapid development. The exceptions, of course, are France and Israel where the safety valve is provided namely that the flexible exchange rate has been allowed to adjust to the policy of inflation. But in a regulated economy like that in India, this inflation does more harm than good. It leads to stagnation. Export goes short and the balance of payments position cannot be solved by taking recourse to the printing press finance.

Purchasing power generated through the printing press as against the earning by the sweat of the brow makes the economic growth still worse.

The licence-permit-quota, import restrictions and export control do not add a single paisa to the stream of national production but.brings colossal income transfer and ill-get income to some persons. So, the capitalists, the beneficiaries of this licence-permit-quota *raj* are much more happy today than at any other time. Never had they so much profit in such a short time, and that too at such a fantastic rate. Take the case of any upstart like Biju or Teja or Mundhra. They have become millionaries in no time, surely not by the sweat of the brow. Before the war, the grain-dealer used to make a very marginal profit; that was only the gunny bag, but today he is a monopolist, and he has become a monopolist with all the accompanying defects of monopoly, because we have fabricated controls. Unless and until we remove these controls, the Chinese walls *i.e.* the territorial barriers, I am afraid this artificial shortage will continue. I request Government to have the boldness of late Shri Rafi Ahmed Kidwai to do away with all these controls, licences and permits. These import licences though technically non-transferable are actually transferable at a price in the black market. Legal dodges are perfected and even prices of import licences are published and sold at 35 to 500 per cent profit. These fundamentally damage the economic growth of the country.

Prof. Shenoy has rightly pointed out that every year there has been a shift of Rs. 1300 crores due to inflation, import restrictions and export control. If this is not social injustice, what else is it ? It perverts the social structure......

SHRI DHIRESHWAR KALITA (Gauhati) : A fundamental right.

SHRI P. K. DEO : It increases the gap between the rich and the poor. This leads to extravagance and it eats away all the savings. The savings in India have declined, in spite of 18 per cent increase in national income. Since a decade there has been stagnation in the saving at about 7.5 per cent, and after 1965-66 this has further declined. We know that it is difficult for the common man to provide a glass of milk to his children or pay their school fees. While that is the position on the one hand, on the other we find that there is a long queue in the air-conditioned reservations or in jet flights. This is the paradox of our planning.

No indication is there in the President's Address to do away with these controls.

This leads to stagnation. The creation of employment opportunities has been put to a stop. That is why there is so much of unemployment among engineers and technicians, and many of them have been going outside the country. The horizon for the new generation is absolutely dark without any ray of hope. Frustration is occasionally manifested in the convocation addresses and elsewhere.

Further, the burden of internal loan and external debt which are to the tune of Rs. 5800 crores have brought the economy to ruin. More foreign loans are incurred for the debt service charges of the previous external loans. Devaluation which is the proof of insolvency in external finance has made the situation still worse because of the failure to take up follow-up action. Deficit financing has been the proof of insolvency in our internal finance. This has been the result of the persistent pursuit of wrong ideologies and policies since the last 22 years and it is because of the uninterrupted one-party rule at the Centre for such a long period. In spite of the reverses at the polls, which have been re-echoed in the mid-term election results, there has been no re-thinking and no indication of the reversal of policy in the President's Address.

Out of despair, people talk of more concentration of power in State hands, more expropriatory measures, more curtailment of Fundamental Rights in the direction of dictatorship in the name of the catchy slogan of socialism. If socialism means raising the living standards of the people, if socialism means uplift of the downtrodden, if socialism means the provision of two square meals a day to the people, if socialism more employment opportunities and more production, if socialism means removal of regional disparities, if socialism means social justice, if socialism means an insurance against old age unemployment, ignorance and disease, I welcome it. But if socialism means Statism, if socialism means State control, if socialism means licence-permit-quota *raj*, if socialism means expropriation, if socialism means distribution of poverty, if socialism means class struggle as a stepping-stone for power, if socialism means nationalisation where the Hindustan Steels could afford to have the luxury of having a loss of Rs. 40 crores a year and the dividend in the huge investment could be absolutely nominal and the tax-payers' money could be squandered away for rehabilitating defeated politicians, if socialism means the denial of the fundamental right of collective bargaining to the labourer, then I reject it. According to us, the solution lies when the creative potential of the individual endeavour and enterprise is fully released and harnessed for the common good, within the restrictive framework of a good Government. I would like to quote the instance of post war West Germany, which has created an economic miracle in such a short time.

Added to this, Government patronage of class conflict is responsible for releasing the forces of disintegration. We belong to that order who surrendered everything they had in the cause of national integration, laying everything at the feet of Mother India to build a more united India. We shudder at the sight of fissiparous tendencies raising their heads. The national unity achieved in 1947 is fast disappearing. We find language controversies, water disputes, territorial claims and counter-claims, inter-State rivalries, Centre's discrimination in the distribution of patronage in the location of central industrial projects, in the process of issue of industrial licences, indecision in the matter of inter-State disputes—all these are responsible for creating fissiparous tendencies in the country. Dispute between the landholder and the tenant, between the student and the teacher and between the employer and the employee have become the order of the day.

Against this background, there is tall talk of removing regional disparities. We got a very distressing picture. Take Orissa. The difference between the State's per capita income and the national per capita income, which was only Rs. 100 in the fifties is now Rs. 200 in the sixties. In 1951-52, the per capita income of Orissa was 169.78 against India's 266.50.

[Shri P. K. Deo]

In 1966-67, the per capita income of Orissa was only Rs. 278.80 against India's Rs. 481.50. In spite of its vast natural resources—mineral and forest, surplus in food, manpower, enormous electric and water potential—Orissa has remained the epitome of poverty. Mahatma Gandhi said, "I saw Daridra Narayan in Orissa." For this state of affairs, I squarely place the responsibility on the follies of the past Governments and the Centre's step-motherly treatment. The strength of the chain lies in the weakest link. Similarly, if you want the country to progress, all units must be fully developed. Paradip is getting silted up. The Centre is not reimbursing the Rs. 15 crores and odd spent by Orissa on Paradip even after taking over the port. The Talcher industrial complex is not given the green signal. The construction of the missing link between Talchar and Bimlagarh rail link is being intentionally delayed. Clearance is not given to the Indravati multipurpose project, even though the State is going to utilise only 40 per cent of Orissa's total contribution to the water resources of the surplus Godavari basin. Unnecessarily interriparian disputes are raised by the Centre when this water is utilised for the chronically drought-affected areas of Orissa. All these are a few instances of the grand design to discredit non-Congress States in this country.

I would like to point out that Orissa has made a very modest fourth plan of Rs. 321 crores. The standard of living of the people of Orissa is so low that as much as 35 per cent of the population has an income of less than Rs. 10 per head per month. To have a modest target of assuring a minimum income of only Rs. 20 per head per month and to raise the per capita income of the State to the all-India level by the end of the fourth plan, it would involve an outlay of Rs. 1220 crores in the public and private sector. But this order of investment is not likely to materialise. What is worse is that an outlay of even Rs. 321 crores on the fourth plan of the State proposed by the State Government is perhaps going to be reduced substantially at the instance of the Central Government and the Planning Commission. This is, Sir, adding salt to the injury. Besides Rs. 321 crores the Government of Orissa will have to pay dearness allowance to the tune of Rs. 18 crores a year which amounts to Rs. 90 crores in five years. The Government of Orissa is going to be penalised for conditions in the creation of which the State has no control. For this deteriorating economic condition why is the State going to be penalised ? Sir, we are on the threshold of the Fourth Plan. I request this House, and through this House the Government, that they should fully support the Orissa Government's modest Rs. 321 crore Plan and go in a big way to render assistance.

With these words, Sir, I say that the President's Address is unrealistic, disappointing and an empty ritual.

श्री यज्ञदत्त शर्मा (अमृतसर) : सभापति महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन कायम होने के बावजूद भी और पेरूमल कमेटी की रिपोर्ट भी जो हरिजनों की वर्तमान स्थिति के संबंध में अभी 26 जनवरी को अखबारों में आई है, इन दोनों कमीशनों और कमेटियों की रिपोर्ट के अन्दर एक प्रकार की बात कही गई है और सरकार का रवैया दूसरे प्रकार का है । आदरणीय राष्ट्रपति महोदय के इस अभिभाषण में शायद जरूरत भी महसूस नहीं की गई...इस विषय को जोड़ने की और चुनाव की सभाओं के अन्दर कांग्रेस ने बहुत कुछ बढ़ बढ़ कर बातें कहीं, माननीय मंत्रियों ने, प्रधान मंत्री से लेकर के नीचे तक के सब महानुभावों ने बहुत कुछ हरिजनों के संबंध में कहा है । लेकिन बड़े खेद का विषय है कि इस महत्वपूर्ण अभिभाषण के अन्दर उस विषय को जोड़ने की आवश्यकता भी अनुभव नहीं की गई... (**व्यवधान**)...

श्री शिव नारायण (बस्ती) : वहां तो आप ने भी बहुत कुछ कहा है, सबकी तरफ से बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं ।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : मैं आपके पक्ष में कह रहा हूं। आपके दर्द को यहां पर रख रहा हूं। . . .(**व्यवधान**). . .

तो मैं अर्ज कर रहा था कि उस विषय को इसमें जोड़ने की कोशिश भी नहीं की गई। यह बड़े खेद का विषय है। सरकार ने सभाओं के अन्दर तो वहुत लम्बे चौड़े हरिजनों के लिए अपने दावे रखे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ उनके लिए किया लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि उनकी जनसंख्या 22 प्रतिशत है और अभी तक 2 प्रतिशत भी इनको स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इस देश के अन्दर जहां तक छूतछात का सवाल है वह एक बहुत वड़ा अभिशाप है जिसके कारण से वह आज सामाजिक प्रतिष्ठा का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। उस संबंध में भी जो कुछ हुआ है वह नगण्य है। वह कुछ नहीं के बराबर है। आज छूतछात की स्थिति यह है कि हमारे इस केन्द्रीय सचिवालय के अन्दर भी हरिजनों के लिए अलग प्रकार की पानी पीने की सुराहियां रखी हुई हैं। प्रयाग में एक होस्टल के अन्दर एक विद्यार्थी को आज भी इसी कारण से दाखिला प्राप्त नहीं हो रहा है। जालंधर का एक असिस्टेंट स्टेशन मास्टर नौकरी में टिक नहीं पा रहा है और उसे कठिनाइयां आ रही हैं क्योंकि वह हरिजन है। ऐसे किस्से अनेक हैं। मैं कुछ बातें ही आपके ध्यान में लाया हूं। जहां तक नौकरियों का सवाल है बहुत ही खेद की बात है, पब्लिक सेक्टर के अन्दर भी आज हिन्दुस्तान स्टील और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अन्दर .01 परसेंट भी हरिजन नहीं ऐडजस्ट हो पाये हैं। इसी तरीके से रिजर्व बैंक में भी एक भी हरिजन नहीं है। सवाल आज इस बात का नहीं है कि उनके नाम के ऊपर सरकार अपने राजनैतिक स्वार्थों की सारी की सारी गाड़ी को चलाती रही है। सवाल इस चीज का है कि उनको सामाजिक अभिशाप से निकाल कर, छुआछूत के इस अभिशाप से निकाल कर एक योग्य प्रकार का जीवन निर्वाह करने के लिए सम्मानपूर्ण रोजी प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए और इस प्रकार उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इन दोनों मुद्दों पर सरकार विफल रही है और मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के अन्दर इस विषय की ओर सरकार का ध्यान नहीं खींचा गया या इस विषय को उठाया तक नहीं गया। यह बड़े ही दुख की बात है और हमारे देश की राजनैतिक अशांति का यह भी एक कारण है।

एक बात की ओर मुझे आपका ध्यान और खींचना है। कुछ समय पहले की चर्चा के अन्दर इसी विषय को लेकर देश के एक श्रेष्ठ पुरुष श्रीमान् गोलवलकर का नाम लिया गया कि वह इस प्रकार की वर्ण-व्यवस्था के पक्षपाती हैं जिसमें छूतछात को मान्यता दी गई है। मैं बड़े बल के साथ कहना चाहूंगा, मेरा उनके साथ संबंध है, मैं उनका आदर करता हूं और बड़े आदर और आत्मीयता के साथ मैं उन्हें गुरु जी के रूप में पुकारता हूं। मेरी उनसे बातचीत हुई है। वह इस प्रकार की विकृत वर्ण-व्यवस्था के बिलकुल पक्षपाती नहीं है बल्कि उसके घोर विरोधी हैं।

मैं, सभापति महोदय, सदन के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूँ कि वे अपने कार्य क्षेत्र के अन्दर संघ की शाखाओं और संघ के कार्य को अपने जीवन का मिशन बनाकर जो कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र में से इस अभिशाप को समाप्त कर दिया गया है। मैं महात्मा गांधी के जीवन का हवाला दे सकता हूं। 35 वर्ष पूर्व नागपुर के एक कैम्प के अन्दर महात्मा गांधी पधारे थे और उन्होंने स्वयं देखकर उस समय यह बात कही थी कि मैं यह देखकर दंग रह गया हूं कि

[श्री यज्ञदत्त शर्मा]

कि यहां के लोगों के रहन-सहन और बैठने उठने के अन्दर छूआछूतपन कहीं दिखाई नहीं देता है—यह रिकार्ड की चीज़ है। परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बम्बई के एक मराठी दैनिक "नवाकाल" का हवाला देकर ये सारी बातें यहां पर उठाई गई हैं। आज देश के अन्दर कुछ इस प्रकार विभूतियां हैं जिनको राष्ट्र की प्रेरणा को जाग्रत करने के लिए और इस देश की समस्याओं पर काबू पाने के लिए हमें उचित रीति से उनकी शक्ति का उपयोग करना है, इस प्रकार गाली देकर या घूंसेबाज़ी से हम देश को गति नहीं दे सकते, देश की पूंजी का उपयोग नहीं कर सकते। मैं इस विषय पर खेद प्रकट करता हूं।

जहां तक साम्प्रदायिकता का सवाल है—साम्प्रदायिकता की यहां बड़ी चर्चा होती है। हमने दलगत स्वार्थों से सजाई हुई शब्दावली का एक एक शब्दकोष अपने-अपने पास रखा हुआ है और उसी के अनुसार साम्प्रदायिकता का अर्थ लगाया जाता है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि आज केरल के अन्दर एक मल्लपुरम् नाम का नया ज़िला बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से कोरे साम्प्रदायिक आधार पर उस ज़िले का गठन किया जा रहा है जो, मैं समझता हूँ, हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिये भी बहुत बड़ा संकट सिद्ध होगा। उसको एक नया नाम दिया जा रहा है—मल्लपुरम्। मल्लपुरम् नाम नया है, परन्तु मांग पुरानी है। यह वही मालाबार मुस्लिम लीग की पुरानी मांग है, जिसके लिए जिन्ना ने किसी समय दक्षिण के मुसलमानों को इस प्रकार की सलाह दी थी कि वे इस प्रकार की मोपलिस्तान की मांग करें, जिसमें लक्ष द्वीप और लकाद्वीप को भी शामिल किया जाय ताकि समुद्र तट के इस स्थान पर उचित समय पर प्रभाव डाल कर पाकिस्तान में जोड़ने के लिए हालात पैदा कर सकें... (**व्यवधान**)...

SHRI E. K. NAYANAR (Palghat) : Then why do you not object to the proposal for the formation of a Malnad district ?

श्री यज्ञदत्त शर्मा : इस सवाल पर आपके सैक्यूलरिज्म को सांप सूंघ गया है। सैक्यूलरिज्म के पक्षपाती मेरे ये कम्यूनिस्ट भाई रोज़ सैक्यूलरिज्म का ढोल पीटते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं इस मामले में इन्होंने क्लोरोफार्म सूंघ लिया है, क्योंकि वहां के मंत्री कोया साहब ने, जो संयुक्त मंत्री मंडल के सदस्य हैं, उन्होंने इनकी फूंक खिसका दी है, अगर तुमने इस मांग को नहीं माना तो हम इस सरकार का विरोध करेंगे।... (**व्यवधान**)... शोर करने से मैं समझता हूँ किसी व्यवस्था तक नहीं पहुँचा जा सकता। प्रश्न बिलकुल सीधा है—यह मांग साम्प्रदायिक है या नहीं ? मेरा यह कहना है कि मोपलिस्तान की मांग बहुत पुरानी है। मेरा यह भी कहना है कि केरल के एक माननीय संसद सदस्य, जो मुस्लिम लीग के सदस्य हैं, ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि केरल के अन्दर मोपलिस्तान का बनाना सारे देश के मुसलमानों के अन्दर उत्साह पैदा करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के लिए या और किसी सहूलियत के लिए एक प्रदेश के अन्दर दूर कोने में यदि एक ज़िला बनाया जा रहा है तो सारे देश के लोगों के लिए यह टौनिक कैसे होगा, जबकि उसमें साम्प्रदायिकता की किसी प्रकार की कोई गंध नहीं है। ये लोग चिल्ला-चिल्ला कर अपने फेफड़े दुखा सकते हैं, लेकिन मेरे तर्क को कभी नहीं गिरा सकते।

मुझे अपने कम्यूनिस्ट भाइयों के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। मैं जानता हूँ कि वे इस देश के अन्दर दूसरे देशों की पोलिटी-

कल-प्रोजेक्शन हैं, मैं जानता हूं कि तारें मास्को और पीकिंग से हिलती हैं और पुतलियां यहां नाचती हैं। मुझे इसमें रत्ती भर भी भ्रान्ति नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने वाणी गिरवी रख दी है, जिन्होंने दिमाग को ताला लगाकर चाबियां चाऊ-माऊ की जेबों में डाल दी हैं, वे यहां पर खुले मस्तिष्क से तथ्यों पर विचार नहीं कर सकते। वे बेचारे इस मामले में असहाय हैं, मेरी दया के पात्र हैं, मुझे उनसे बड़ी सहानुभूति है। जहां तक इस साम्प्रदायिक मांग का सवाल है, इस पर अवश्य विचार होना चाहिए। मैं गृह मंत्री महोदय का ध्यान, यद्यपि वे इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, इस विषय की ओर खींचना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस पर विचार करें।

साम्प्रदायिकता के विरुद्ध बोलने वालों का ध्यान मैं विनम्रतापूर्वक इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि कल एक माननीय सदस्य यहां बोल रहे थे। वे पहले कांग्रेस के थे, लेकिन आज किसी और दल के अन्दर हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता था, लेकिन मुझे बताया गया है कि वह मंडल महोदय है। कल वह हरिजनों के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने कहा—"तथाकथित तुलसीदास"। मुझे पता नहीं भाषा की उनकी कितनी जानकारी है, तथाकथित मुहावरे का ठीक अर्थ भी वह जानते हैं या नहीं, यह अनादर सूचक मुहावरा है। मैं साम्प्रदायिकता के विरोधी सभी लोगों से पूछना चाहता हूं —किसी अन्य सम्प्रदाय के किसी महापुरुष के प्रति यदि इस प्रकार का शब्द कहा होता तो उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ती। तुलसीदास जी इस देश के लोगों के लिये आज मानस देवता हैं, भारतीय मनिषी मंदाकिनी की एक चमकदार किरण हैं। इस प्रकार के व्यक्ति इस सदन में अगर भाषा की दरिद्रता को दूर नहीं कर सकते तो कृपया अपने मुंह को जरूर बन्द रखें। इस प्रकार के शब्द हमारे देश के महापुरुषों के प्रति बोले जायें तो इससे राष्ट्र-भाव को चोट लगनी चाहिये, ठेस लगनी चाहिये। मैं मांग करता हूं कि इस प्रकार के शब्द जो तुलसीदास जी के प्रति प्रयुक्त किये गये हैं, इस सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। प्रधान मंत्री महोदया ने इन दिनों चुनावों के सम्बन्ध में बहुत दौरा किया है। मैं समझता हूं कि उन्हें काफ़ी थकावट होगी, इस दृष्टि से उनके प्रति मुझे बहुत गहरी सहानुभूति है। लेकिन कुछ समाचार-पत्रों में चर्चा छपी है, उनमें कहा गया है कि 14 लाख रुपये का बिल बिहार के राज्यपाल ने उनको दिया है। यह एक सच्चाई है—तथ्य तो वे जानती हैं। इस 14 लाख रुपये की मद में केवल सिक्योरिटी का खर्च नहीं है, कुछ अन्य मदों पर भी खर्च हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं—सरकारी खज़ाने से इतना पैसा कैसे दिया जायेगा, जबकि चुनाव अभियान में सिक्योरिटी को छोड़ कर अन्य मदों पर खर्च किया गया है। क्या यहां के चुनाव कानून के अनुसार इससे चुनाव अवैध नहीं हो जाता। अगर कोई उम्मीदवार अपना एजेन्ट किसी सरकारी आदमी को रख ले, तो उसका चुनाव अवैध हो जाता है, यहां तो सरकार का सारा खज़ाना ही उण्डेला जा रहा है। इस सम्बन्ध में और भी कई कहानियां प्रचलित हैं। यह भी कहा गया है कि बम्बई के एक सेठ ने तीन लाख रुपये का चेक दिया है। लोग यह भी कहते हैं कि सौदा किसी होटल में बैठ कर किसी व्यक्ति ने पटाया। मैं इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं रखता, जानकारी तो प्रधान मंत्री जी को होगी, क्योंकि उनके द्वारा ही ये सब बातें हुई होंगी। प्रधान मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करना चाहता हूं—उन्होंने सरमन के रूप में बहुत सी बातें यहां पर कही हैं—इस देश की राजनीतिक

[श्री यज्ञदत्त शर्मा]

मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए यह उनका पहला कदम होगा, यदि वह सदन के सामने आयें और बतायें कि उन्हें कितनी रकम कहां-कहां से और किस रूप में, चैक की शक्ल में या नकद, किस तरह से प्राप्त हुई है। यदि वह ऐसी पहल करेंगी तो देश के अन्दर इस दृष्टि से एक अच्छी परम्परा का सूत्रपात होगा। मुझे यह भी पता लगा है कि बिरला जी के खिलाफ़, जिनके बारे में हमारे यहां के यंगस्टर्स की यह मांग थी कि उनके खिलाफ़ एन्कवायरी कराई जाये, बहुत दिनों से यह मांग चल रही थी और आपने वायदा भी किया था, इस चुनाव के दौरान इस विषय पर भी पानी डाल दिया गया है। एक अफसर को उनके खिलाफ़ एन्कवायरी करने के लिये मुकर्रिर करके आपने उनके आंसू पोंछ दिये, चुनाव के लिए उनसे पैसा ले लिया गया और समाचार-पत्रों को भी तश्तरी में रखकर पेश कर दिया। इस मामले में क्या क्या हुआ, भगवान जानते हैं या वह जानते हैं या उनका घर जानता है, लेकिन यह चीज़ सामने आनी चाहिए।

आज अमृतसर के व्यापारियों के आर्ट-सिल्क के कारखाने बन्द हो रहे हैं, इसलिये कि उनमें काम आने वाले 70 प्रतिशत रा-मैटीरियल पर बिरला मनोपली बनाकर बैठा हुआ है। हमने दिनेश सिंह का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उस मगर-मच्छ से बात करने के लिये आज कोई तैयार नहीं है, यह बड़े खेद का विषय है।

श्री जगजीवन राम के पुत्र की कहानी भी इसी प्रकार की है। सभापति महोदय, इस समय 18 पुराण हैं, लेकिन अब एक 19वां पुराण—पुत्र-पुराण भी लिखा जाने वाला है—जिसमें लिखा जायेगा कि मंत्रियों के पुत्रों ने क्या-क्या किया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कभी कोई ऐसा काल आयेगा, जब धृतराष्ट्र संजय से पूछेगा कि हे संजय बताओ, 20वीं सदी में कांग्रेस का अन्त कैसे हुआ? मंत्रियों के पुत्रों ने किस-किस मंत्री को कलंकित किया? उस समय वह कहेंगे—जगजीवन राम के पुत्र श्री सुरेश कुमार के बारे में समाचार-पत्रों के अन्दर—मेरे पास यह समाचार पत्र है—यह कहानी छपी है कि नैशनल ग्रिंडले बैंक के मैनेजर की ओर से एक नोट छपा है। इस में कहा गया है-वेस्ट-जर्मनी की किसी फर्म के द्वारा उनको 1250 रु० या 1247 रु० प्रतिमास मिलते रहे, कितने वर्षों तक मिलते रहे। समाचार पत्र में यह भी कहा गया है कि वह केवल मैट्री-कुलेट हैं।

इस प्रकार के किसी बड़े पद पर काम करने की योग्यता या क्षमता उनमें नहीं है सिवाय इसके कि वे एक मन्त्री के पुत्र हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि श्री जगजीवन राम जी जरा स्पष्ट करेंगे कि यह कहानी क्या है। क्योंकि इस प्रकार से जब मंत्रियों की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है तो हमको भी धक्का लगता है। इसलिए सत्य सामने आना चाहिए ताकि हम लोग भी बाहर जकर लोगों का मुंह बन्द कर सकें।

अन्त में एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। यह गांधी जयन्ती का मौका है। हमने यह रंग कलेन्डर और डायरीज़ में देखा है जो कि सदस्यों को बांटी गई हैं लेकिन बाकी तो सब रंग-भंग हो रहा है, सारा रंग समाप्त हो रहा है। बड़े दुख की बात है कि गांधीजी के ऊपर "हन्ड्रेड ईयर्स आफ गांधी" पुस्तक से श्री ट्रोयम्बे के लेख को पी० आई० बी० ने 26 जनवरी के समाचारपत्रों के विशेषांकों के लिए छपने को दिया था। उसमें मुहम्मद साहब या ऐसे किसी महापुरुष का जिक्र भी था तो किसी सम्प्रदाय ने आपत्ति की और वह लेख वापिस ले लिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि गांधी शताब्दी में सरकार गांधीजी को श्रद्धांजली देने

जा रही है या तिलांजलि देने जा रही है, इसपर विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उस पर देश को विचार करने की जरूरत है। श्री मोरारजी देसाई या इस सरकार के दूसरे नेता यहां पर तो जवाब दे ही सकते हैं लेकिन बाहर जो हवा बह रही है उसको वे रोक नही सकते हैं।

श्री अ० सिं० सहगल (बिलासपुर) : सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन के समक्ष जो अपना अभिभाषण दिया है, उसपर मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने अपने भाषण में अनाज के उत्पादन के बारे में कहा है कि 1967-68 में 9 करोड़ 56 लाख मीट्रिक टन अनाज पैदा हुआ। यह बहुत अच्छी बात हुई है। लेकिन खेती की और पैदावार को बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए हम बहुत से कल-कारखानों को भी बढ़ा सकते हैं। आज हमारे देश में फर्टिलाइजर प्लान्ट्स बहुत कम हैं। हमारे यहां खाद की बहुत कमी है। उसको बढ़ाने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा आज हमारी सबसे बड़ी समस्या पानी की है। नर्मदा का जो पानी है वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को बराबर-बराबर देना है। आज यदि मध्य प्रदेश की हालत सुधरती है, वहां पर आप बांध बनाते हैं तो मैं समझता हूं मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रान्त है जोकि दूसरे प्रान्तों को भी अनाज देने में सक्षम होगा। इसके साथ ही मुझे यह भी कहना है कि आज विदेशी सहायता के सम्बन्ध में जो अनिश्चितता आ गई है उसको देखते हुए हमें अब अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। इसके अलावा 51 करोड़ 40 लाख डालर का कर्ज जो आज हमारे ऊपर लदा हुआ है, उसको कैसे साफ किया जाये इसपर भी हमें विचार करना होगा। मैं समझता हूँ कि हमारे जो बड़े-बड़े डिपार्ट्मेन्ट्स हैं, उनमें हमको कमी करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो हम खर्च करते हैं, जो हम खुद खर्च करते हैं उसमें भी कमी करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो हमारे सरकारी मुहकमे हैं, जिनमें आज बहुत ही फुजूलखर्ची हो रही है, उसको भी बन्द करना चाहिए। इसके साथ ही मैं कहूंगा कि जो सेक्रेटेरियट है, यह जो हमने एक हाथी पाल रखा है, उसमें भी कमी करने की जरूरत है। आज वहां पर जो सेक्रेटरी, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, एडीशनल सेक्रेटरी, ये सारे बना रखे हैं, उनके सम्बन्ध में भी सोचने विचारने की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के पेज 8 पर कहा है—"तब इससे सांप्रदायिकता की बुराइयों को मिटाने में सरकार के हाथ मजबूत हो सकेंगे। हालांकि कानूनी और इंतजामी तरीके बरतने जरूरी हैं, फिर भी हमारे सभी लोगों को इन बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। सफलता इसी में है कि लोगों के दिल और दिमाग में नेशनलिज्म और सैक्युलेरिज़म का जज़बा पैदा किया जाये।" अब मैं आपके सामने कुछ कोटेशन्स देना चाहता हूं। वर्ल्ड पीस थ्रू लव, इसके बारे में कुछ कहूंगा :

"Human ty is not going to be saved by any material power, nuclear or otherwise. It can be saved only through divine intervention. God has never failed humanity in its dark and critical periods. The greatest danger to man today is not from any natural catastrophe but from himself.

"It is not possible to realise human brotherhood merely by appealing to high ideals or to a sense of duty. Something more than that is essential to release human consciousness from the clutches of selfishness and greed.

"Today the urgent need of the mankind is not sects or organized religions but love. Divine love will conquer hate and

[श्री अ० सि० सहगल]

fear. It will not depend on other justifications but will justify itself."

अब मेहर बाबा ने जो कहा है, वह कोटेशन भी आपकी इजाजत से देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है :

"The greatest law of God is love which holds the key to all problems."

(Meher Baba)

ट्रुथ के बारे में कहा है :

"The Truth of Divine life is not hope but reality. It is the only reality and all else is illusion. Have faith and you will be redeemed."

तो मेरा कहना यह है कि जो समय आ रहा है उसको अगर आप रियलाइज़ नहीं करेंगे तो सारी दुनिया और यह सरकार ही क्या, और सरकारें भी टिक नहीं सकेंगी। मेहर बाबा ने यह भी कहा है :

"Words that proceed from the source of truth have real meaning, but when men speak these words as their own, the words become meaningless."

(Meher Baba)

इसके साथ-साथ मैं आपसे कहूं कि हमारे प्रेसीडेन्ट साहब ने अपने भाषण में यह कहा है कि "हम अपने समाज का पुनर्निर्माण करने के लिए अच्छे साधनों और तरीकों पर तर्क और समझदारी की सीमा में रहकर एक दूसरे के साथ बहस तो कर सकते हैं पर हम सब इसमें एक हैं कि मिलकर गांधी जी के सपनों के भारत का निर्माण करें और हर आदमी का दुख दूर करने, हर आंख का आंसू पोंछने की भी कोशिश करें।"

मैं कहता हूं कि यह ठीक है। सी० वी० पुडंम ने लिखा है—गाड टु मैन, मैन टु गाड। मैं बताना चाहता हूं कि वे क्या कहते हैं इस सम्बन्ध में :

"To understand the problem of humanity as merely the problem of bread is to reduce humanity to the level of animality. Even when man sets himself to the task of securing the material satisfaction, he can succeed in that attempt only if he has spiritual understanding. Economic adjustment is impossible unless people realise that there can be no effectively planned and co-operative action in economic matters until self-interest gives place to self-giving love; otherwise, with the best of equipment and efficiency in material spheres, conflict and insufficiency cannot be avoided."

अब मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि होम मिनिस्ट्री पर बहुत बौछार की गई है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि असल बात तो यह है कि वे लोग भी अपने दिल पर हाथ रखकर यह देखने की कोशिश करें कि उनमें कितनी प्योरिटी है। है। यदि उनमें प्योरिटी है तभी वे कह सकते हैं कि होम मिनिस्टर में प्योरिटी नहीं है। लेकिन मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि होम मिनिस्टर में प्योरिटी है। असल बात यह है कि हुकूमत का काम जो किया जाता है वह दूसरे तरीके से किया जाता है। इस तरह से अगर कोई चीज़ की जाती है तो फिर उस पर नाराज नहीं होना चाहिए। इस बात को आप अपने हृदय से सोचिये।

उसके साथ-साथ यह कहा जाता है कि गवर्नर्स को यहां पर खत्म करना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि वह आपकी उन दोनों चीज़ों को जोड़ने के लिए हैं याने इन्टेग्रेशन के लिए। गवर्नर के ओहदे का आज के हालात में एक महत्वपूर्ण स्थान है और अगर समय होता तो मैं उसके महत्व के बारे में सदन को विस्तार से बतलाता।

मैं यह निवेदन करूंगा कि आप पूरे देश को 4 या 5 हिस्सों में बांट दीजिये। उन हिस्सों में जो भी लोग रहें वह सब लोग वहां की प्रादेशिक भाषा को बोलें। यह देखना हमारा फर्ज हो जाता है कि हम बराबर एक-दूसरे की भाषा की इज्जत करें और हम उनको भी उसी उच्चकोटि पर ले जायं। तथा खर्च में भी कमी होगी।

आज यह कह देना कि हम गवर्नर्स को यहां से निकाल देंगे तो मैं आपसे बड़ी नम्रता के साथ पूछना चाहता हूं कि अगर आप गवर्नर का पद नहीं रखियेगा तो फिर यह कोआरडिनेशन, इन्टेग्रेशन का काम कौन अंजाम देने वाला है? अब कोई गवर्नर अगर खराब काम करता है तो उसे बेशक आप अलग कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

SHRI G. KUCHELAR (Vellore): I rise to take part in the debate on the President's Address on behalf of my party, and I shall confine myself to a few points which I would like to bring to the notice of the House.

First, the Address was delivered by the President in Hindi and we were unable to understand it. Since he is the President he should have understood the difficulties of the non-Hindi-speaking Members, and he should have satisfied them by making a speech in English. However, we find that he has delivered the Address in Hindi in order to show preference to the people who speak Hindi, but we on our part were unable to avail ourselves of the advantage of understanding the suggestions made by the President.

The President has referred to the increase in agricultural production and he has expressed his happiness over that. If production has increased I do not understand how the dearness allowance has been increasing gradually right from 1960 up to January, 1969, how the cost of living index has been increasing and how the agricultural industry has been unable to meet the increased cost of cultivation. The President was stressing about the help given by Government to the farmers in the form of fertilisers, improved seeds, improved ploughing material etc. But I would submit that Government have failed to take into consideration the needs of the people who are primarily engaged in the agricultural industry. I charge this Government that they have failed to look into the grievances of the people and the workers engaged in the agricultural industry which is a basic industry for our nation. Government have not yet fixed any minimum wage for the agricultural workers, even though we are mainly dependent on the benefits flowing out of that industry. No measure has been enacted by a central Act so far to safeguard the interests of the agricultural workers.

For more than twenty years, they have not thought of the welfare of the workers. I am really sorry at their indifference. They should have taken some interest in the workers and then the agricultural sector will move smoothly. There is no use of talking about fertilisers alone. Farmers alone cannot bring in more production. Workers who are engaged in the industry should be well looked after.

Tamil Nadu was all along bringing to the attention of the Central Government the agitation against the imposition of Hindi by the radio programmes. Our late Chief Minister and the Information Minister brought this to the notice of the Prime Minister as also Mr. Shah who was the Minister of Information and Broadcasting. I had also written to Mr. Chavan and the Information Minister. They have changed the timings of the English news and cut down the preference shown by the people who do not know Hindi at all. The people there were getting the English news earlier. We do not mind if Tamil is given a regional preference. But they have changed it to Hindi and that has caused a lot of disturbance in our State. Students protested and held demonstra-

[Shri G. Kuchelar]

tion; they were agitated. This matter was also taken up by responsible people in the Government. I cannot understand how the Minister who has taken charge of this portfolio, Mr. Sinha, says that there is no protest at all from the State Government. I wrote a personal letter and sent a telegram also; I received a reply two months later in which they have clearly accepted the new change as their policy.

They wanted to give precedence to Hindi over English. Why should they do so when non-Hindi people do not accept Hindi ? The Hindi-speaking persons do not accept English. There was a great controversy going on in this House and in the nation and there was talk of the three-language formula in connection with the official language. I am sorry that the President did not mention this. The country is facing so many other problems also—unemployment, food problem. There is no need to create problems on the lauguage front when we are faced with so many other difficult and complex problems. The dispute is still there and it has not been settled. What is the hurry in these circumstances to change the timing of the English and Hindi broadcasts in Tamil Nadu ? They cannot change a policy like that.

I therefore strongly oppose this, and the people of Tamil Nadu want this Government to bring in the original position, that is, the 8 O'clock news in the morning should be in English only. Let them have their policy after the consideration of the dispute which is now pending in respect of the problem of language and a satisfactory settlement thereof.

15 hrs.

I just wanted to mention another point. There is no indication at all in the Address of the President of the harassment of the Harijans in the country. It was mentioned last year. We have been noticing several atrocities committed in this direction, but no action has been taken promptly. Since this Government has ruled this country for over 20 years, there is absolutely no reason why they should not have erased such a disparity, such a distinction between one caste and another and between one community and another in the nation itself. The Government should take some steps to safeguard the interests of the Harijans in the country.

I also want to point out the problem posed by the Shiv Sena. Particularly the people of Tamil Nadu, if they wear dhoties, used to be attacked by those people in Bombay. It has been pointed out and brought to the notice of the House earlier when this House was discussing the motion of no-confidence in the Government last week. Then, we found that neither the Home Minister Mr. Chavan, nor the Prime Minister, Mrs Indira Gandhi, had any firmness in dealing with this question, and taking action against Shiv Sena and to face the facts. In Tamil Nadu, our late Chief Minister, Arignar Anna, was able to tackle such a sort of an organisation in the name of Tamil Sena which had been formed earlier, to counteract the Shiv Sena at Bombay. We were able to prevent such things not by force or any such forceful action but merely by advising the people. By means of good advice, he was able to control and prevent such an organisation in the south. I do not understand why the Home Minister has not been able to do so. He comes from Bombay. He and the Prime Minister should have come forward readily to arrest such tendencies. Especially when they are praying for the co-operation of all parties to arrest such atrocities in Bombay, why should they hesitate to take action ? Are they not able to control the Shiv Sena ? If they are not able to control it, let them leave it. There are people to look after these things; they can face it and take similar action as they took in such matters earlier, and stop such things happening in the country. So, what I say is, the Central Government should take some action. They should at least persuade the Chief of the State Government; they can at least go and visit such places, call the organisation's leaders and advise them and come

to a compromise. As it is, it is not a happy affair. If they say, "*Idli, Samhhar,* go go", similarly, they can pronounce in the South, "*roti sabji* go go." So, that should not be the policy of this country or this Government. I therefore strongly oppose such activities and such atrocities which have been committed in Bombay. It was denied in this House that such things ever happened, and it was said that no houses were burnt. It was not a fact. There are papers which have been published, with radio photographs and other things which are enough evidence to show that there were some such atrocities which had been committed against the Tamilians in Bombay.

I would tell the Government that the Government should bear in mind certain disciplines and principles and follow good conduct, and see that the Government is run with the nice and smooth co-operation of the people. For example, a very great Saint, Thiruvalluvar, has put these qualities in one small sentence or verse: *Ozhukkathil eithuvar menmai, Izhukkathin eithuvar Eithal pazhi.* That means, the people should be disciplined and there should be discipline, whether it is individual or society or any form of organisation. They should have certain discipline and principles. If they do not go according to those principles, they have to come down; they will come down; their dignity will come down and their position will go down. Similarly, the nation's position should not be brought down by this Government.

SHRI S. KUNDU (Balasore) : Sir, I was amazed to read the President's Address where he has said that there is a "decisive upward turn." It is nice to gloat over 6 million tonnes more of agricultural production or recovery from recession, but it would be an unpardonable crime not to represent correctly the people's agony, anger and despair at the present political and economic situation. Some upper class peasants might have taken the lead and some big businessmen might have switched over to agriculture, using modern implements and machinery, but the poor people have been left as they are. If the rain gods fail us in the coming years, we will again fall back in agricultural production.

I feel there has been an under-assessment of the political and economic situation. If we look at the political arena, there is a holocaust from Bombay to Kohima, may be due to Shiv Sena or Lachit Sena. The values for which we stood, all that we cherished to build within our lifetime, are under a serious threat of extinction. We must try to find out the genesis of the problem of violence. We are not doing that.

There is huge unemployment. 40,000 engineers are unemployed in a country at a time when many steel mills, bridges and roads are to be built. Have you heard of such a thing anywhere else? Young engineers write to me that unless they get some jobs, they will commit suicide. Some have actually committed suicide. A doctor can set up private practice, but for an engineer, unless he gets a job, he cannot maintain himself.

Registered unemployment also has grown tremendously during the last few years. From 88,000 in 1952 it has grown to more than 3 lakhs in 1968. The total unemployed in both rural and urban areas number about 2 crores.

Earlier we knew of quarrel between a State and another State but fight within a State is a new phenomenon which we have seen in Telengana. Such phenomena will not stop unless we make realistic appraisal of the whole thing, which the President has failed to do.

Under these circumstances, I would like to go into the results of the last mid-term elections. In 1967 and in 1969, in quick succession, we had two general elections. I am happy, firstly, that for the first time in these twenty years in the last mid-term elections the voters had a sense of confidence. It was to some

[Shri S. Kundu]

extent a day of the voters and not of the money bags, not so much of the people who went in the name of castes or religions, Secondly, we had for the first time a real test of democracy. For twenty-one years there was a monolithic power at the Centre and the Congress Party enjoyed the monopoly for 21 years. This vital change has been brought about by the younger generation, by the younger people between the ages of 18 to 23 who had not seen Gandhiji, many of whom were not born in 1947. They actually acted as an active catalyser in the crucible of political change that brought about this transformation. I welcome wholeheartedly this political shift as it was done in country where 80 per cent of the people are illiterate. In such a country if democracy has to survive it has to survive on what we do actually and not on what we actually say. It is the process of experimentation which will give a sense of confidence in the people. From that confidence it will take us towards a positive polarisation for which there has been so much demand for which we were waiting for the right time to come.

In a country where 90 per cent of the people are poor and hungry, where millions go without any clothes and without any shelter it is a tragedy to find that this class is not represented in this democracy. I think if we have another general election all over India, which the Congress Party and their leader ought to welcome since 20 crores of people have rejected them in all the four States, there Congress Party will be completely routed. To honour the tenets of democracy the leader of the Congress Party in Parliament should go and seek a fresh mandate from the people. I am sure, if she does it, it will give a fatal blow to the Congress. Once the Congress breaks into pieces the process of political polarisation will start. This will generate a process to unify the groups and forces who stand for secularism, for nationalism, for democracy and socialism.

The Congress Benches now represent a *khichdi.* All sorts of views and persons are present in that *khichdi.* From this *khichdi* they must be separated into positive elements of definite political views. Therefore, I welcome the change as a result of the mid term elections and my sympathies go to those young people who have brought about this process of change.

I would demand that this right to vote should be given to people aged at 18 years and it should not be limited to people who are 21. When more and more younger people will assert themselves there will be a dynamic change in our political activities, economic planning, administration and other matters.

The other day I read in the *Hindustan Times* that the British people have ranked our Prime Minister on a higher place than the Queen of England. All the queens have the same way but the British people have special regard for such queens. Whatever that may be, the ages of kings and queens and their masaldars are coming to an end, or it has almost come to an end.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, he is calling Shri Randhir Singh a masaldar.

SHRI S. KUNDU : Sometimes I am sorry and sick to find that our Prime Minister, unfortunately, is thinking the way of the former kings and queens. I am referring to the Rs. 25 lakhs mansion which she is thinking of building for herself. In a poor country like ours Rs. 25 lakhs is a big amount. I find that Shri Poonacha is nodding his head. I am sure that he will agree with me that with Rs. 25 lakhs we can build 50,000 tube wells throughout the country for drinking water; or we can repair thousands of primary schools with this amount. It is a shocking thing to find the young boys and girls, the future of India, do not find a place to sit in their schools and have to carry their small mats from their homes. These are also published in foreign papers. At least in this Gandhi Centenary Year I hope she will be wise enongh to say that she has nothing to do with it. The other day she mentioned that some people have requested her to occupy a big mansion. Delhi is a city of mansions and palaces, hovels and huts. She can choose one of

the mansions and palaces that are there already. I agree that it is not a very important matter, but it is an important question of principle. We should not preach some thing and practise something else.

The youths of the country are alert today. They are not going to be bullied. They know and they have realised how the future destiny of the country is to be moulded. The more I think of our national movement *i.e.*, national struggle for freedom, the more betrayed I feel. In 1947 when our national flag was unfurled in Lal-Kila I felt that we have betrayed our national movement, because the objective of our movement was something quite different. It is a different thing to say that it does not matter if Jawaharlal Nehru, who was at that time the darling of India's nationalism, youth, democracy and secularism, walked into a house which was used by the British Commanders-in-Chief or Shri Rajagopalachari, now champion of the Swatantra Party, walks into the palatial Rashtrapati Bhavan from where the British ruled India for many years. I am only trying to describe the contrast between what was preached and what was practised. When Gandhiji walked into the Bhangi Colony, these people stayed in big palaces and mansions. Even after 21 years to make the Birla House, where Gandhiji was shot dead, a national property one had to launch a movement.

We have been speaking about industries taking some sort of a stride. I would like to ask, if it takes its stride forward or backward, right or left, what advantage or enthusiasm this industry gives to the younger people who would like to build up small-scale industries. If we analyse the structure of industries, we will find that the big monopolists who build big industries also build and control small-scale industries. If a young man, who comes out of the university today, wants to build a small-scale industry, the officer would say, "Please do not try; you cannot build the industry". One does not know from where technical know-how will come, from where credit will come, from where to find market. The only way left for our youngmen is to read British history and join the IAS and some other allied services. It is shocking that even after 21 years of independence we find from the Public Service Commission's report that 80 per cent of our young people, who are supposed to give a new leadership to the teeming millions, take British history as a subject pass the IAS and other examination and get into the services. There is no opportunity and incentive created whatsoever to build small-scale industry for our young people.

After shouting for years and years together, last year the Government decided upon building some sort of an engineering entrepreneur scheme. When the loan will come, you will see that it will also go to the relations of the big industrialists; these people will not get it.

SHRI SHEO NARAIN : Say something about corruption also.

SHRI S. KUNDU : What to say about corruption ? You yourself are an example of corruption in one State. In every State they have left some people or the other. In my State Patnaik is there. In spite of the Khanna Commission he has been absolved of it. The less spoken, much better it is.

I want to raise a word of caution today. It is quite possible that the way you are going you may have more agricultural production and a surplus in five or six years but I would like to tell you that within 22 years our population will double to 100 crores of people and population per acre of land will also go up by two to three times. Rich peasants are going in for tractors and modern agricultural implements like pump sets. Most of them are from a wealthy class and they are throwing out people from employment, in a short time in the rural side; more people will be unemployed. So, there will be surplus food but there will be hungry people because there will be no capacity to buy and there will be rioting in the streets. Please remember this.

Therefore today let there be new thinking as to how we are going to take the

[Shri S. Kundu]

new scientific inventions to the doors of the real people, the landless people, the small peasants and the small owners.

You were there, Mr. Chairman, the other day when Shri Morarji Desai in a very cavalier fashion answered two important questions which were raised. One question raised was, "Why do you not give amenities to the poorer class of employees ?" and he said, "If you give amenities, it will be inflationary." Another friend asked, "Why do you not look into the price which is falling very much ?"—the price had fallen by 30 per cent of a particular agricultural product. There also, he was pooh-poohed and Shri Morarji Desai said, "You want that the price should rise and you also say that the price should fall; what can we do ?"

MR. CHAIRMAN : You can take up this at the time of the Budget debate. Please conclude now. Your time is up.

SHRI S. KUNDU : So, unless you give the minimum benefit to the people, unless you give them a house, education and such other things, production is not going to rise. Even the capitalist countries who have found that when they give a better deal to the worker, production rises.

That has happened in Japan; that has happened in Israel but that is not going to happen here as long as Shri Morarji Desai is there.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमैन महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्या, श्रीमती सुशीला रोहतगी, ने राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा करने के बारे में हाउस के सामने रखा है, मैं उसकी पुरजोर ताईद करता हूं। मैं आपकी मार्फत दो-चार जरूरी बातें सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

एक बड़ी तगड़ी और नखरेदार चौधरन थी। चौधरी चौधरन से बहुत डरता था। वह चौधरी को पूरा खाना नहीं देती थी। अक्सर मेहमान घर में आते हैं। एक दिन एक मेहमान उनके घर में आ गया। चौधरी ने सोचा कि आज तो मुझे अच्छा खाना मिलेगा, आज मेहमान के साथ बैठ कर खाना खायेंगे। चौधरी अच्छा खाना मांगता है, यह देख कर चौधरन की आंखें लाल हो गईं। जब चौधरी ने कहा कि मेहमान के साथ मुझे भी मिठाई दो, तो चौधरन ने उसको नीचे-नीचे डंडा दिखाया। चौधरी अकड़ गया। हमारे यहां आखिर में दूध दिया जाता है। चौधरी ने कहा कि मेहमान के साथ ही मुझे भी दूध दो।

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, can we discuss domestic problems here ?

MR. CHAIRMAN : Mr. Randhir Singh by the time you narrate the story, your time will be over.

श्री रणधीर सिंह : चेयरमैन साहब, मैं आपोजीशन की पोल की बात कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि चौधरन की तरह सरकार चौधरी किसान को ज्यादा देर तक डरा नहीं सकेगी। अगर चौधरन डंडा उठाती है, तो चौधरी भी लट्ठ उठाना जानता है। अब ये तिफल-तसल्लियां ज्यादा अरसे तक काम नहीं आयेंगी। अब सब्र का प्याला लबरेज़ हो गया है।

लोगों की हिमायत हासिल करने के लिए कांग्रेस के पास भी बहुत सी बातें हैं और दूसरों के पास भी। लेकिन एक कांग्रेसी होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि एक बात साफ हो गई है कि सारे देश में किसान कांग्रेस से दूर सरक रहा है और यह बड़ी खतरनाक बात है। हमें इस बात को कुबूल करना होगा। हरियाणा में 80 फ़ीसदी किसान कांग्रेस से दूर सरक गये हैं। पंजाब में भी 80 फ़ीसदी किसान कांग्रेस के खिलाफ़ हो गये हैं। यू० पी० में 80, 90 फ़ीसदी किसान कांग्रेस के खिलाफ़ हो गये हैं। यही हाल बिहार में और बंगाल में भी है। ये जितने

हमारे भाई बजर-बट्टू बैठे हुए हैं, ये सब किसान को बहका रहे हैं।

किसानों के कांग्रेस से दूर जाने पर मैं खुश नहीं हूँ, निराश हूं। लेकिन यह निराशा भी उम्मीद में तब्दील हो सकती है। किसान मालिक है इस देश का। इलैक्शन के मौके पर इनक्लाबी नारे लगाये जायें और किसान की हिमायत में स्पीचिज दी जायें, लेकिन इलैक्शन में किसान का वोट ले लिया— भैंस दूध निकाल लिया—और फिर किसान भाड़ में जाये, यह बात नहीं चलेगी।

मैं इन चार पांच मिनटों में कुछ बातें सरकार को कहना चाहता हूँ। अगर सरकार इन बातों को नहीं करेगी, तो सौ फ़ीसदी किसान कांग्रेस के खिलाफ़ होते दिखाई देते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस में मुझसे ज्यादा भी कोई हमदर्द और आदमी है। मैं साथ ही आपोज़ीशन को भी कहना चाहता हूँ कि जो खिचड़ी उसने पका रखी है, उससे भी काम नहीं चलेगा। किसान बहुत सयाना है। इस बार कई पार्टियों का दिमाग साफ हो गया है। पी० एस० पी० वाले बहुत नारे लगाते थे। एस० एस० पी० वाले भी बड़े नारे लगाते थे। और यह मेरे भाई चूहा पार्टी वाले, कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग जो हैं यह सिर्फ बंगाल के अन्दर हैं, उससे बाहर इनका नाम कहीं नजर नहीं आता।

तो एक तो बात मैं यह कहना चाहूँगा कि बहुत अरसे हो गये हैं, किसान की जायदाद पर अगर सीलिंग है, उसकी जमीन पर सीलिंग है तो यह जो शहरों के बड़े बड़े नुमाइन्दे बैठे हैं, कारखाने वाले और बड़े-बड़े पूंजीपति जिनके लिए बड़े-बड़े नारे लग रहे हैं, मैं चाहूँगा कि सरकार एक दम उन पर अमल करे और अर्बन प्रापर्टी पर भी सीलिंग लगाए। जितना रुपया इस तरह अर्बन प्रापर्टी पर सीलिंग लगाने से इन बड़े बड़े कारखाने वालों से और पूंजीपतियों की बड़ी बड़ी मिल्कियतों से इकट्ठा होता है वह देहात में खर्च किया जाय। एक बात तो यह की जाय।

दूसरी बात---किसान की जितनी पैदावार है उसकी कीमत 40 प्रतिशत गिरी है। लेकिन यह शहर के रहने वाले या दूसरे लोग जो सरमायापरस्त हैं उनके द्वारा जितनी चीजें पैदा की जाती हैं, जितनी गैर-किसान प्रोडक्शन है, लोहा है, कपड़ा है, चीनी है, सीमेंट है उनकी कीमतें आज आसमान को छू रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसान की चीजों की कीमत कम हो तो जो किसान के रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं उनकी कीमत भी कम होनी चाहिए। अगर उनकी कीमत ज्यादा है तो किसान की चीजों की कीमत भी ज्यादा होनी चाहिए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा, किसान आज यह महसूस करते हैं, सारे देश के किसान के साथ एक अत्याचार यह हो रहा है कि उसकी जो होल्डिंग है उसमें एक हिन्दू सकसेशन ऐक्ट लागू हो गया है और जो जमीन लड़की के नाम उसके खाविंद के घर से होनी चाहिए, उसके श्वसुर के घर से होनी चाहिए वह उसके बाप के घर से की जाती है। मैं इस बात के हक में हूं कि लड़की को हक मिले लेकिन उसके हसबैंड के घर से मिले, हसबैंड के घर से चाहे उसे रुपये में नौ आना मिले लेकिन यह नहीं कि बाप का भी हिस्सा ले लिया और इधर श्वसुर का भी हिस्सा ले लिया। बराबर की बात होनी चाहिए। मैं तो इस बात को कहना चाहता हूँ कि न सिर्फ हरयाना के, न सिर्फ पंजाब के बल्कि सारे देश के किसान इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उसकी जमीन को टुकड़े-टुकड़े किया जा रहा है और भाई और बहनों को लड़ाया जा रहा है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं...

MR. CHAIRMAN : I am sorry, the hon. Member's time is over. Mr. R.K. Birla.

SHRI RANDHIR SINGH : All right, Sir.

SHRI R.K. BIRLA (Jhunjhunu) : In his Address the respected President has mentioned about the agricultural and industrial progress of the country. He has also mentioned about public undertakings, Five-Year Plans, generation of electric power from atomic energy and so on and so forth. But no mention, whatsoever, has been made in his Address about a commodity which is used by each and everybody not only in our country but in the entire world, a commodity without which, I am sure, nobody in the world can exist, *i.e.*, salt. I would like to say that salt is very intimately connected with Mahatma Gandhi and our struggle for life.

The year, 1969, is Gandhi Centenary Year, which we are all celebrating in the most befitting manner one can think of. Gandhiji wanted salt, a gift from the blue seas surrounding our country, to be available to the people without any duty whatsoever, like the water that we drink and the air that we breathe. It was with this view that he considered the tax on salt, which was levied as far back as 1765 on both indigenous and imported salt, as a symbol of our servitude; hence, non-payment of salt duty became a symbol of our right for freedom. The famous Dandi March of Gandhiji kindled the fire of freedom in our hearts. The Working Committee of the Indian National Congress passed a Resolution on 2nd January, 1930, fixing Sunday, the 26th January, for a countrywide demonstration supporting the goal of complete Independence. The very first tool of this non-violent fight with the British was the adoption of the salt satyagraha. In spite of that, the salt tax continued to be levied by the then Government till we achieved Independence. Immediately after achieving Independence, the Finance Minister of independent Indian Government headed by the late Pandit Jawahar Lal Nehru perhaps Shri Chetty or Dr. Mathai, abolished the duty on salt as desired by the Father of the Nation. But I am sorry to say that a cess was imposed in place of the duty which took away the very sense of the abolition of the duty, contrary to the wishes of Gandhiji. It was stated that the cess was levied for two purposes. One was the payment of compensation to the Indian States under treaty obligations and the other was to meet the establishment charges of the salt department including the cost of watch and ward staff. I feel that levy of the cess for meeting the payment of compensation to the Indian States under the treaty obligation was not at all correct because such payment could also have been made from the funds which had been utilised for meeting other liabilities or payments to the Indian States. The surprising thing is that even after the merger of the States which was completed by the year 1949, the cess continued to be levied and it is being levied as of date, now. In any case the cess for this purpose should not have been allowed to be continued after the year 1949.

Regarding the establishment charges, I am sure my friends sitting to my left and right and also with me will entirely agree with me that this department has been functioning only to collect cess and had done nothing except that since its inception. No service worth the name has been done towards the development of the salt works or the welfare of people working in the salt department. During the past 22 years, if my information is correct, the Government of India had collected cess worth Rs 45 crores and it must have gone to the exchequer. The main purpose was to spend the money on the welfare of the workmen and the development of salt works. Our annual production of salt is about 5.5 million tons and the duty on it comes to about Rs. 2 crores at the rate of Rs. 3.50 per ton. Besides, there is a levy of one rupee per ton as royalty which goes to the States; it has nothing to do with the Central Government. Sixty per cent of the salt produced is consumed by human beings and 40 per cent is put to industrial use. The total cost of salt in our country varies between Rs. 8 and Rs. 10 per ton. It is thus very surprising indeed that a commodity which Gandhiji wanted to be freely made available to everybody attracts a cess of Rs. 3.50 per ton by the Centre and Re. 1/- per ton as royalty, thus making

a total of Rs. 4.50 which is fifty per cent of the total production cost. Both the industrial consumers and the general public have expressed their resentment over the levy of this cess. The Salt Experts Committee appointed by the Government of India had suggested that the Indian salt industry has not developed on scientific lines as it should have been and a lot more could be done to improve the quality and yield of salt. The Salt Department should render all technical help to the salt manufacturers out of the cess so collected, looking to the points which I made earlier, but I feel there is no justification at all for the Government to make a profit out of the cess and treat the same as revenue income going to the national exchequer. In conclusion, I would appeal to the Government through you and through this hon. House that the cess on salt should be totally abolished as a mark of respect to the Father of the Nation. In case this suggestion of mine does not find the approval of the Government, alternatively, the amount of the cess so collected should be utilised only for the purposes which I would mention below, and not be treated as revenue income. The purposes are : improving the working conditions of the workers of the salt works and providing facilities like approach roads, houses, medical aid, schools to the workmen's children and their families; providing maintenance allowance to the workers during the off-work period, since they are getting only Rs. 2.75 per day as their wages. I may mention here that Rs. 2.75 a day as wages for an industrial worker is perhaps the lowest in any industry, and therefore, they should be allowed to get something more during the time when they are off from the work. Their working period is only six months, because, the salt industry, as we all know, is a seasonal industry. Then, some money should be spent in carrying out the experiments for improving the salt works, the quality of the salt and mechanical harvesting. This is about salt which is very intimately connected with Mahatma Gandhi. I would say that the abolition of the cess at this time is the proper thing and I would request the Government through you and through this House once again that the abolition of the salt cess should be announced as soon as possible and definitely during this year when we are celebrating Gandhi Centenary.

Next, I would say something about the army to defend us when we are attacked by our neighbours. We all know that during the Chinese aggression of 1962, our soldiers were sent to the NEFA front only with half the clothing that they required. They were sent with two or three barrack blankets instead of six to seven barrack blankets which were necessary for the soldiers to work at a height of 10,000 ft. to 12,000 ft. I am sure that the attack from Pakistan and China cannot be totally ruled out. I therefore feel that we must equip ourselves so that in case when we are attacked, we have the power to meet them very well. For this, we require the clothings. I would submit that in the Army, in the Air Force or in the Navy, everybody, right from the soldier to the full General, requires woollen clothing right from head to toe. I know from experience what has happened during the Chinese aggression. Therefore, it is necessary that we must have proper types of raw material at our disposal, and that we have the necessary type of clothing immediately made available to us whenever we need it. For this, we require imported wool. I am sorry to say that India still has not been able to develop that type of wool which we need for meeting our requirements of defence as well as civilian requirements. Perhaps, I may inform the House that the USSR has been able to develop a sheep which is called the Russian Merino; it took them about 10 years to develop it. They have developed it just as the Australian Government has been able to do. I do not understand why the Government of India has not been able to develop that sheep up till now. I therefore request the Government that it is a very important thing which should be attended to. The Indian woollen industry needs about Rs. 32 crores worth of imported wool, and that type of Merino should be developed in our country, which should be called as Indian Merino.

Before I close, I would just say one more sentence and that is about controls. Enough has been said by my friend this side and that side. Somebody has said that

[Shri R. K. Birla]

controls are very necessary for the economy.

There should be no control whatsoever. I believe in prosperity through open competition. No country has ever flourished through controls, whether it is Russia, China or any East European country. But Japan and Germany, though they were defeated nations, progressed very rapidly because there was no control. Therefore, control of every type, whether on production, distribution in industry or agriculture or in anything, should be abolished. If at all control has to be kept, only birth control should be there, for which the Government should do their utmost and spend the maximum money, because this addition of 1 crore people every year—we are adding a Ceylon every year—must be stopped.

श्री महन्त दिग्विजयनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मुझे खेती की पैदावार के बारे में कुछ आवश्यक बातें आपसे कहनी हैं। खेती के लिए राष्ट्रपति जी के भाषण में यह कहा गया है कि खेती की पैदावार में एक मोड़ आया है, लेकिन जितने मोड़ की आवश्यकता है, उतना मोड़ अभी तक नहीं आ सका है। इसलिये मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा पहला सुझाव यह है कि जब तक हमें उचित्त मात्रा में पानी, सस्ती बिजली, अच्छे बीज, खाद और सस्ते बैल नहीं मिल सकेंगे तब तक खेती का उत्पादन जितना हम चाहते हैं, नहीं कर सकेंगे। हर एक चीज के लिए हमारे यहां कंट्रोल है, लेकिन जो राष्ट्रीय सम्पत्ति है, जैसे गाय, उसके स्लौटर को रोकने के लिए हम ने आज तक कोई कन्ट्रोल नहीं किया है। यदि यही स्थिति चलती रही तो कुछ दिनों के बाद हम उस स्थिति में पहुंच जायेंगे, जिससे भीख मांगते हुए हमें संसार के सामने आना पड़ेगा।

ट्रैक्टर ऐसी चीज नहीं है जो हर खेतीहर अपने इस्तेमाल में ला सकता है। ट्रैक्टर केवल वही लोग, जो बड़े बड़े फारमर्ज हैं, या जिनके पास बड़ी खेती हैं, वे ही काम में ला सकते हैं। ट्रैक्टर ऐसी चीज भी नहीं है जिसके पार्ट्स हर जगह आपको मिल सकें। पानी के बारे में मुझे यही कहना है कि हम जिस आंचल से आ रहे हैं, वहां सब-सायल वाटर बहुत ज्यादा है। पानी ऊपर ही मिल जाता है, जिससे नहरें बेकार सिद्ध हुई हैं, क्योंकि नहरों के दोनों ओर की भूमि उपज के लिए बेकार हो जाती है। इस लिए जब तक वहां नलकूपों की व्यवस्था नहीं होगी, खेती ठीक तरह से नहीं की जा सकती। इस लिए मेरा अनुरोध है कि वहां नलकूप ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड किये जांय।

हमने मोर को "राष्ट्रीय पक्षी" घोषित किया हुआ है, उसी तरीके गाय को, जिसे हम राष्ट्रीय सम्पत्ति कहते हैं, "राष्ट्रीय पशु" घोषित किया जाय, तब हम देश को बचा सकेंगे, अन्यथा नहीं।

परिवार नियोजन के बारे में मैं हमेशा कहता आया हूँ और आज इसके बारे में कुछ विशेष प्रार्थना मुझे आपसे करनी है। परिवार नियोजन केवल वन-वे-ट्रैफिक है, केवल हिन्दुओं के लिये ही लागू है। मुसलमान भाई चार शादियां कर सकते हैं, और इस तरह से वह साल में चार बच्चे पैदा कर सकते हैं, जबकि सरकारी हिन्दू कर्मचारी दो शादियां नहीं कर सकता, अगर वह दो शादी करे तो सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाय। वे तो एक-दो या तीन बच्चे बस। इससे ज्यादा पैदा नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब यह है कि मुसलमान जो चार शादियां कर सकता है, 10 वर्ष में 40 बच्चे पैदा करेगा। और हिन्दू एक दो तीन करके माइनारिटी में हो जायेंगे। मुसलमान और ईसाइयों की ओर से जो कन्वर्जन इस वक्त हो रहा है उन दोनों के मेजारिटी में हो जाने पर यह देश दूसरे के अधीन हो जायगा। हमने इस देश की रक्षा उस समय नहीं की जबकि 45 करोड़ हिन्दू पार्टीशन के समय इस देश में थे।

माइनारिटी में नौ करोड़ मुसलमान भाई थे। लेकिन उन्होंने इस देश का विभाजन करा लिया और हम इस देश को उस समय बचा नहीं सके। यदि हम माइनारिटी में रिड्यूस हो गए तो मैं पूछना चाहता हूं कि हम देश की रक्षा कैसे कर सकेंगे ?...(**व्यवधान**)... मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि परिवार नियोजन आवश्यक है तो वह सबके लिए होना चाहिए। न कि केवल हिन्दुओं पर ही उसको लागू किया जाय दूसरों पर नहीं। मेरे विचार से यह हिन्दुओं के साथ अन्याय है। हिन्दुओं के लिए इस प्रकार के जो कानून हैं, चाहे वह हिन्दू कोड बिल हो या हिन्दू रेलीजम ऐक्ट हो, वे सब कानून इस देश के लिए घातक होंगे। इस प्रकार से आप हिन्दुओं के मनोबल को घटा रहे हैं। वह हिन्दू जो कि इस देश की रीढ़ हैं उनको अगर आपने कमजोर किया तो यह देश कमजोर हो जायगा और गुलाम हो जायगा। इसलिए इस पर आपको विचार करना होगा। अंग्रेजों ने तो मुसलमान और हिन्दुओं को लड़ा कर इस देश के टुकड़े किए लेकिन आप तो हिन्दू हिन्दू को लड़ा कर देश के टुकड़े करने जा रहे हैं। आप कास्टीज्म के आधार पर टिकट देते हैं। चाहे कांग्रेस हो, बी० के० डी० हो या मजलिसे मुस्लिम हो, सब जगह कास्टीज्म के आधार पर टिकट बांटे जा रहे हैं। इसके कारण देश दूसरी तरफ जा रहा है।

गांधी जी यह कहा करते थे कि कास्टलेस सोसाइटी बनाएंगे लेकिन यहां तो कास्ट्स और भी मजबूत होती जा रही हैं। आप जब तक अपने दिल को अच्छी तरह से टटोलेंगे नहीं कि किस प्रकार से इस पर हम काबू पायें, आप इन समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे और न यह देश मजबूत हो सकेगा।

अब मैं जनसंख्या के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि सन् 1951 से 1961 तक कितने कितने मुसलमान और ईसाई इस देश में बढ़े हैं। हमको इस बात पर कोई एतराज नहीं है कि वह बढ़े हैं। वह जरूर बढ़ें। लेकिन जिस तरह से वे बढ़ रहे हैं उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि सन् 1971 का जो सेन्सस होगा उसमें हम और भी घट जाएंगे। सन् 1951 में 3, 54, 14, 284 मुसलमान थे और सन् 1961 में 4,69,29,557 हो गए। यानी 1 करोड़ 15 लाख 26 हजार 273 की बढ़ोत्तरी हुई। इसी प्रकार से दस सालों में ईसाई भाइयों में 24 लाख चार हजार की बढ़ोत्तरी हुई है। मैं इससे सशंकित नहीं हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि यह हुआ कैसे ? एक तो जो आपका परिवार नियोजन है वह इस में कुछ मदद कर रहा है। हिन्दुओं की तुलना में वे लोग अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ज्यादा बच्चे पैदा करके हिन्दुस्तान में ढकेल रहा है। आज आसाम में मुसलमान पाकिस्तान से चले आ रहे हैं और काश्मीर में भी बसाए जा रहे हैं। पाकिस्तान से ही वे लोग ढकेले जा रहे हैं ताकि इन जगहों पर उनका बहुमत हो जाय और हम अल्पमत में रह जायं। और फिर वह क्लेम कर सकें कि यह हमारी सम्पत्ति है। इस सम्बन्ध में हमको सतर्क होना चाहिए। इसके अलावा दक्षिण में एक हवा और चल रही है मोपिलिस्तान की। यह बहुत दिनों से चल रही है। लेकिन उसका सक्रिय रूप इस समय नम्बूद्रीपाद के समय में सामने आ रहा है। तो दक्षिण में तो यह स्थिति है और पूर्वी आसाम, पश्चिमी बंगाल और काश्मीर में मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं। इस प्रकार चारों तरफ से चाहे उसको लाल सेना कहिए या काली सेना कहिए वह हम को घेरती चली आ रही है। और हम उसी जगह पर हैं जहां पर थे। हम अपीजमेंट की पालिसी अभी भी अख्त्यार किए हुए हैं। उनको खुश रखकर उनके वोट हासिल करना चाहते हैं।

अब मैं नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसमें मुसलमानों की एकता तो जरूर हुई है।

[श्री महन्थ दिग्विजयनाथ]

मजलिसे मुस्लिम बन गई। लेकिन हमारा देश विभाजन की तरफ जा रहा है। इस कान्फरेंस का आबजेक्ट यह था :

"The object of this Conference was common citizenship, unity in diversity, freedom of religion, secularism, equality, justice, social, economic and political—"

इसका आउटकम क्या हुआ ? मजलिसे मुस्लिम पैदा हुई जो कि हरिजनों को हमसे अलग करना चाहती है। उसका नारा है, हरिजन मुस्लिम भाई-भाई, हिन्दू कौम कहां से आई ? आज हरिजनों के बारे में हम बहुत चर्चा सुन रहे हैं। हरिजन तो हमारे अंग हैं। हरिजन हिन्दू समाज के अभिन्न अंग हैं। अगर हिन्दू समाज से हरिजन अलग हो जाएंगे तो हिन्दू समाप्त हो जाएंगे। उनके साथ किसी तरह से भी अन्याय करना गलत चीज है।.. (**व्यवधान**)...हरिजनों के लिए इनके मनमें बड़ी ममता है। मुसलमानों को अलग रखकर देश के टुकड़े हुए और एक मुस्लिम स्टेट बन गई लेकिन हिन्दू स्टेट नहीं बनी। आज इस देश में जो हरिजन हैं वह हमारे अंग हैं। उनको अलग करने से इस देश को कमजोर करना होगा। इस तरह से वह इस देश के साथ गद्दारी करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से कहूंगा कि हरिजनों को वही स्थान मिलना चाहिए जो कि सवर्ण हिन्दुओं का है और हम लोग किसी प्रकार से भी उनको अलग नहीं करने देंगे। राष्ट्ररूपी शरीर को ब्राह्मण कहते हैं, क्षत्रिय और वैश्य कहते हैं और यह पांव शूद्र हैं। सब मिलकर हिन्दूरूपी यह शरीर बना है तो फिर हम उसके किसी एक अंग को काट कर कैसे अलग कर सकते हैं और बाकी शरीर का कैसे संरक्षण कर सकते हैं ? यह एक विचारणीय प्रश्न है।

नेशनल इंटीग्रेशन के सम्बन्ध में मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। इसमें सब लोग बुलाए गए थे। लेकिन हिन्दू सभा जो कि हिन्दुओं की एक रेप्रेजेन्टेटिव बाडी कही जाती है उस को इसलिए नहीं बुलाया गया क्यों कि उसका एक आदमी आपकी पार्लियामेंट में है। नेहरूजी ने जब पहली कान्फरेंस की थी उस समय श्री बिशन चन्द्र सेठ इसी सदन में थे। उनको स्पेशल इनविटेशन देकर बुलाया गया था। हिन्दू सभा ने जब तक रेप्रेजेन्टेशन किया तब तक देश के टुकड़े नहीं हुए, इस बात का इतिहास साक्षी है। सन् 30 में राउंड टेबल कान्फरेंस हुई थी। उस समय देश का विभाजन नहीं होने पाया था। जब देश के विभाजन की बात चली तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, जब क्रिप्स कमीशन और साइमन कमीशन आया तो हिन्दू महासभा को रेप्रेजेन्टेशन नहीं दिया। देश के हिन्दुओं का दुर्भाग्य 1945 में यह हुआ कि उस समय के निर्वाचन में हिन्दू महासभा का कोई प्रतिनिधि नहीं चुना गया। परिणाम स्वरूप मुसलमानों की ओर से मि० जिन्ना ने देश विभाजन योजना का प्रतिनिधित्व किया और कांग्रेस ने कहा कि हम हिन्दुओं के रेप्रेजेन्टेटिव हैं। उन्होंने जो कुछ कहा उसको सही मान लिया गया। आज आपके सामने फिर ऐसा ही वातावरण आ रहा है। अभी इन्दिराजी गोरखपुर में गई थीं। उन्होंने कहा कि यह पुरानी संस्था जरूर है लेकिन वहां जाकर यह क्या कर सकेंगे ? लेकिन हम कहते हैं कि हम अकेले ही सही लेकिन हिन्दुओं की तरफ से कुछ कहने के लिए तो हैं। आज दोनों तरफ के लोग मुसलमानों के लिए कहने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें कौन से ऐसे लोग हैं जो हिन्दुओं के लिए भी कुछ प्लीड कर सकते हैं ? अगर कोई संस्था है तो उससे डबल हिन्दू सभा है जिसका एक इतिहास है कि जिसको आप मिटा नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसे साथी जो देश को छिन्न भिन्न करने के लिए तैयार हैं, अपीजमेंट की पालिसी मुसलमानों को खुश करने के लिए चलाना चाहते हैं और वोट

कैचिंग मेथड के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। मिड टर्म पोल में क्या किया गया? पन्द्रह परसेंट मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन रक्खा गया था। इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि सेकुलरिज्म को उस रोज ही दफना दिया गया था जिस रोज इस देश का विभाजन हुआ था। टू नेशन थ्योरी के आधार पर जब इस देश के टुकड़े हुए उसी रोज सेकुलरिज्म को दफना दिया गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि हिन्दू इस देश में साम्प्रदायिक हैं तो फिर इस देश का राष्ट्रीय कौन है? मैं जानना चाहता हूँ कि हम किस देश के राष्ट्रीय हैं? हम वहीं पर माइग्रेट कर जायेंगे और अपने राष्ट्र को पनपायेंगे।

16 hours.

श्री रामगोपाल शालवाले (चान्दनी चौक): सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कुछ कहने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने खाद्य समस्या की चर्चा करते हुए दूध के उत्पादन का कोई जिक्र नहीं किया। इस देश के 50 करोड़ लोगों को आज दूध की आवश्यकता है। बिना दूध के देश के बच्चे और देश के नौजवान चल नहीं सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में दूध की समस्या की ओर कोई संकेत न करना एक बहुत कमी है। देश की दूध की समस्या का समाधान करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस देश में गोधन का संरक्षण व विकास किया जाय और गोधन की रक्षा की जाय। सारे देश में गोहत्या पर कानूनी पाबन्दी लगाई जाय।

मैं बतलाना चाहता हूं कि सन् 1966 में बड़ा भारी आन्दोलन इस दिल्ली नगर में चला और 7 नवम्बर को 10 लाख लोगों ने पार्लियामेंट पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। उसके बाद 8 महीने तक लगातार सत्याग्रह हुआ। 45 साल मुझे इसी दिल्ली में रहते हुए हो गये। मैंने गांधी जी के और अन्य संस्थाओं के बड़े-बड़े आन्दोलन देखे लेकिन गोरक्षा जैसा व्यापक आन्दोलन मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। उस समय इस आन्दोलन से घबड़ा कर हमारी केन्द्रीय सरकार ने गोरक्षा समिति का निर्माण कर दिया और जनता से यह वायदा किया कि तीन महीने के अन्दर सम्पूर्ण देश में गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया जायगा। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इतना समय बीत जाने के बाद उस कमेटी का प्रतिवेदन अभी तक आपके सामने और इस हाउस के सामने नहीं आया है।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उस कमेटी के तीन गैर सरकारी सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिये हैं और उनके त्यागपत्र देने के बाद 29 गैर सरकारी गवाहों ने अपनी गवाही देने से इंकार कर दिया है जिनमें श्री प्रताप सिंह शूर जी वल्लभदास, प्रधान आर्य सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा हैं, दूसरे द्वारकापीठ के जगद्गुरु श्री शंकराचार्य हैं और तीसरे हिन्दू महासभा के प्रधान श्री नित्य नारायण बनर्जी मुख्य हैं। ऐसी स्थिति में उस कमेटी के भीतर अगर कोई निर्णय होता है तो जनता उस निर्णय को कदापि कबूल नहीं करेगी।

इसीके साथ-साथ अगर इस देश के अन्दर गांधी जी, स्वामी दयानन्द और राम व कृष्ण की भावनाओं को लेकर 45 करोड़ लोगों की भावनाओं को लेकर गोहत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो मैं इस सदन के मार्फत सरकार को इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि देश में पुनः एक व्यापक व तीव्र आन्दोलन जारी हो जायगा।

जब राष्ट्रपति महोदय ने अपना कार्य-भार सम्भाला था तो मैं राष्ट्रपति जी से मिला था। मैं

[श्री रामगोपाल शालवाले]

उनके पास बादशाह बाबर की एक वसीयत लेकर गया था। राष्ट्रपति जी बोले कि उसमें क्या है तो मैंने उनको बतलाया था कि जब हुमायूं भारत के राजसिंहासन पर बैठने लगा तो उस के पिता बाबर ने उसके नाम यह वसीयत की थी और उस वसीयत में बाबर ने कहा था कि मेरे बेटे अगर तुम यह चाहते हो कि इस देश में मुगल शासन निष्कंटक रीति से और देर तक क़ायम रह सके तो तुम इस देश के बहुमत वर्ग की भावनाओं का आदर करते हुए इस गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगा देना। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार यदि चाहती है कि कांग्रेस का शासन देर तक बना रहे तो यहां के बहुमत को काबू में करने के लिए यहाँ के हिन्दुओं की भावनाओं का उसे आदर करना चाहिए और दूध का उत्पादन करने के लिए उसे गोहत्या पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में साम्प्रदायिकता के ऊपर कुछ थोड़ी सी चर्चा की है लेकिन उन्होंने साम्प्रदायिकता की कोई व्याख्या नहीं की है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि केरल और उत्तर प्रदेश में नये पाकिस्तान की तैयारियां हो रही हैं। आसाम में 7 लाख पाकिस्तानियों की घुसपैंठ हुई है और ऐसे 7 लाख व्यक्ति जिन्होंने कि आसाम के अन्दर इस तरह से प्रवेश कर लिया है मुझे बड़े दुःख के साथ यह चीज कहनी पड़ रही है कि इसमें एक केन्द्रीय मंत्री का नागरिकता दिलवाने में सहयोग रहा है और उनको वहां की नागरिकता दिलवा दी। यह एक बहुत भयंकर बात है जोकि आसाम के अन्दर की गई और पाकिस्तान के पैर आसाम के अन्दर आज इस तरीक़े पर मजबूत किये जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आसाम में प्रतिमास 1000 पाकिस्तानी बाक़ायदा प्रवेश कर रहे हैं और हमारी सरकार उनको रोकने के लिए सर्वथा असमर्थ है। यह देश के लिए एक बहुत विषम समस्या है।

इसके अतिरिक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट के 51 वकीलों ने एक प्रतिवेदन दिया है और उस प्रतिवेदन में उन्होंने कहा है कि मजलिसे मुशावरात और जमायत इस्लामी के एक नुमायन्दे के उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद उस का इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जलूस निकाला गया और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाये गये। मजलिसे मुशावरत और जमायत इस्लामी ने उत्तरप्रदेश को बांटने की भी तैयारियां की हैं और जिला बिजनौर के 32 लाख मुसलमानों के लिए नये पाकिस्तान के निर्माण करने की उन्होंने मांग की है।

काश्मीर की स्थिति बड़ी भयंकर है। काश्मीर में आज से दो साल पहले पांच अगस्त सन् 1967 को एक हिन्दू लड़की का अपहरण किया गया। उस अपहरण की गई लड़की का नाम परमेश्वरी हण्डू था। 42 बार अदालत में उस केस की पेशी हुई लेकिन एक बार भी उस लड़की को अदालत के सामने पेश नहीं किया गया जिसके कि बारे में केस था। यह सादिक सरकार की एक ख़ास चीज है जोकि मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। इस बारे में पंडितों के व्यापक आन्दोलन की कोई सुनवाई नहीं की गई। वहां पर कोशिश की गई कि काश्मीर में सादिक सरकार की जो साम्प्रदायिक नीति है उस का विश्लेषण किया जाय और प्रधान मंत्री जी ने कोहली कमीशन के नाम से इसके लिए एक कमीशन का निर्माण किया। उस कोहली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। 285 गवाहियां उसके सामने हुई हैं। मेरी भी एक गवाही हुई है। मैं आज कहना चाहता हूं कि उस कमीशन की रिपोर्ट को सरकार ने अब तक सदन में नहीं रक्खी हैं। उसे सरकार क्यों दबा रही है। मैं चाहूंगा कि कोहली कमीशन की रिपोर्ट सदन की टेबुल पर रक्खी जाय। जिस दिन यहां उस आयोग की रिपोर्ट आयेगी उस दिन पता चलेगा कि सादिक सरकार किस प्रकार साम्प्रदायिक नीति

बरत रही है और काश्मीर की घाटी में किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है ।

हालत यह है कि जम्मू के अन्दर राशन कम दिया जाता है जबकि श्रीनगर में राशन अधिक दिया जाता है । जम्मू में राशन की क़ीमत ज्यादा है जबकि श्रीनगर में उसी राशन की क़ीमत कम है । आखिर यह भेदभाव की नीति क्यों बर्ती जा रही है और सरकार उस भेदभाव की नीति को क्यों नहीं दूर करती ?

इसी तरह हम देखते हैं कि कांग्रेस सरकार की एक तरफा नीति के कारण इस सदन में हिन्दू कोड बिल स्वीकार किया गया । कुछ सदस्यों ने जब सरकार से पूछा कि कोई इंडियन पेनैल कोड या हिन्दुस्तानी कोड बिल क्यों नहीं बनाया जाता तो सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया कि मुसलमानों के धर्म में हमको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है । अब अगर मुसलमानों के धर्म में आप को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है तो इस तरह से हिन्दुओं के धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार आप को कहां से मिला है ?

चंडीगढ़ में महिला सम्मेलन के नाम से वहां पर मुसलमान देवियों ने बहु-विवाह की प्रथा को हटाने के लिए प्रस्ताव किया है । उन्होंने बहुपत्नीवाद का घोर विरोध करते हुए यह मांग की है यह प्रथा हटाई जानी चाहिए । हमारे भूतपूर्व विदेश मंत्री श्री चागला ने भी मुसलमान महिलाओं को इसके लिए प्रेरणा दी है कि वह पाकिस्तान, टर्की और अरब देशों से प्रेरणा लेते हुए बहुपत्नीवाद का अंत करायें और इसे कानूनी जुर्म करवायें । वह इस बुरी प्रथा को हटाने के लिए देश में आन्दोलन करें और उसके पक्ष में जनमत बनायें । देश में एक प्रकार की व्यवहार संहिता बनाई जानी चाहिए । हिन्दू कोड बिल के स्थान पर इंडियन पैनेल कोड या हिन्दुस्तानी कोड बिल बनाया जाय और मुसलमानों में जो चार-चार विवाह करने की खुली छूट दी गई है उसे समाप्त किया जाय ।

श्री ओंकारलाल बोहरा (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में जो अपना अभिभाषण दिया और जिन भावनाओं और विचारों का उसमें उन्होंने उल्लेख किया है उसका स्वागत करते हुए मैं आपके सामने बहुत संक्षेप में अपना विचार रखना चाहता हूं ।

देश ने आजादी के बाद काफ़ी प्रगति की है । शिक्षा का प्रसार व विस्तार हुआ है । काफी तादाद में नई, नई सड़कें बनी हैं और उत्पादन भी बढ़ा है लेकिन यह सोच करके कि बहुत कुछ हो गया है हम संतुष्ट होकर बैठ नहीं सकते हैं ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस आशावाद का उल्लेख है और जिन भावनाओं की उसमें उन्होंने चर्चा की है उनका स्वागत करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमने 20 वर्षों में वह प्रगति नहीं की है जिसकी कि अपेक्षा थी ।

यहां पर नौ दिन चले अढ़ाई कोस वाली कहावत ही चरितार्थ होती है । मैं कहना चाहता हूं कि जिस तेजी से जापान ने, जिस तेजी से जर्मनी ने, रूस ने और चीन ने अपने देश के अन्दर प्रगति की है और उत्पादन को बढ़ाया है, अपने देश के कल-कारखाने बढ़ाये, शिक्षा की व्यवस्था की, अपेक्षाकृत उतनी प्रगति हमारे यहां नहीं हुई है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम केवल अच्छी घोषणाओं और अच्छी बातों पर ही निर्भर नहीं रह सकेंगे । हमें निश्चित रूप से देश का एक चित्र सामने रखना है अगर हम इस देश में समाजवादी व्यवस्था चाहते हैं, इस देश के गरीबों, पीड़ित आदमियों को और इस देश के नीचे गिरे हुए लोगों को एक नये जीवन का संदेश देना चाहते हैं । आज उनके सामने कोई तस्वीर होनी चाहिए जिसमें कि वे भी आगे बढ़ें । इस दृष्टि से जितनी प्रगति होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई । अभी हमारे देश में बेकारी है, अशिक्षा है ।

[श्री ओंकार लाल बोहरा]

हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री, हमारे महान प्रधान मंत्री पंडित नेहरू ने एक नारा रखा था कि आराम हराम है, और हमारे देश के नौजवानों ने टेकनिकल क्षेत्र और सभी क्षेत्रों में बढ़ कर काम किया। लेकिन जब आज हजारों शिक्षित व्यक्ति, इंजीनिअर्स और टेकनीशियन्स अपना सर्टिफिकेट लेकर दरवाजे-दरवाजे जा कर घूमते हैं तो रोना आता हैं, दुःख और पीड़ा होती है। हमारे महान नेता ने जिस देश की तरुणाई को, देश की नई पीढ़ी को उद्बोधन दिया, आज उन्हीं को काम देने के लिए हम कुछ नहीं कर पाये हैं। जिन नवयुवकों को प्रेरणा देने की पंडित जी ने बहुत कोशिश की, आज उन्हीं युवकों और शिक्षित लोगों को देश का नव निर्माण करने का मौका नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि जितनी प्रगति होनी चाहिये थी उतनी हो नहीं रही है।

हम इस बूढ़े और बीमार देश को बूढ़े हाथों द्वारा कभी आगे नहीं ले जा सकते हैं। जब तक हमारे देश की समस्यायें जवान हैं, जब तक वह समस्यायें जवानों के हाथों में नहीं आयेंगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस लिए हम केवल इस बात की चर्चा न करें कि हमने प्रगति की है। यह भी देखें कि हमने कितनी प्रगति की है और किस दिशा में की है। यदि हम इसको देखेंगे तो पायेंगे कि हमने बहुत प्रगति नहीं की है।

मैं देख रहा हूं कि चौथे आम चुनाव के बाद देश में कुछ परिवर्तन आया है। इस देश के अन्दर राजनीतिक अस्थिरता आई है। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजनीतिक अस्थिरता हमारी नीतियों का परिणाम है। हम लोग देश की गरीबी को खत्म नहीं कर पाये हैं और न समाजवादी व्यवस्था ही ला पाये हैं। आज लोग साम्प्रदायिक झगड़े या जाति-पाँति के झगड़े पैदा कर रहे हैं, आज जो अनेक प्रकार के क्षेत्रीय असंतुलन के झगड़े पैदा किए गये हैं या पैदा किये जा रहे हैं, उनका सहारा लेकर, जाति का सहारा लेकर, किसी क्षेत्र का सहारा लेकर, लोग अपना नेतृत्व स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के अन्दर एक परिवर्तन आया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने जो अपना मत दिया है उसका स्वागत करते हुए भी मैं एक बात की चर्चा करना चाहता हूँ कि हमारे देश में गरीबी रह सकती है, हमारे देश में बेकारी रह सकती है, लेकिन हम अपने देश को स्वतंत्र, अखण्ड और सुरक्षित देखना चाहते हैं। इसलिए मैं उन भाईयों से कहना चाहता हूं, जो यह मानते हैं कि एक महान् देश है, यह पूरा देश एक है, जिसकी परम्परायें बड़ी अच्छी रही हैं, कि सदियों के बाद हम स्वतंत्र हुए हैं। हमको निश्चित रूप से इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारे किसी कार्य से हमारे देश को नुकसान न हो, हमारे राष्ट्र पर आंच न आये, हमारी सुरक्षा पर आंच न आये। हम देश के अन्दर समाजवाद लायें, लेकिन इस कास्ट पर नहीं कि दूसरे के गिरवी बन जायें।

अब मैं राजस्थान के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। आज वहां पर अकाल है। वर्षों पहले से राजस्थान के अन्दर राजस्थान नहर के निर्माण की मांग की गयी थी। लेकिन राजस्थान नहर के निर्माण के काम को योजना में नहीं रखा गया। अगर इस योजना पर अमल किया जाता तो राजस्थान नहर न केवल राजस्थान की बल्कि सारे देश की खाद्यान्न की समस्या को हल कर सकती थी। आज दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान राजस्थान का ही अंग नहीं है यह सारे देश का अंग है, यह सारे देश का रेगिस्तान है। लेकिन आज वहां पर पीने के पानी की कमी है। आज वहां पर तीन-तीन

सौ फीट गहरे कुएं खोदने पर भी पानी नहीं मिलता। आज हमने इसके लिये पैसा नहीं दिया, हमने राजस्थान नहर का निर्माण नहीं किया जिससे कि हम वहां की जमीन की सिंचाई कर सकें और अन्न उपजा सकें।

इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि इतना पिछड़ा होते हुए भी तेजी से राजस्थान का विकास नहीं हो रहा है, वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि हमने वहां के लिए कोई विशेष वित्तीय व्यवस्था नहीं की। जैसा मैंने सुबह कहा था, उसको फिर दोहराना चाहता हूं कि यदि हम देश के करोड़ों लोगों को उठाना चाहते हैं तो यह तभी हो सकता है जब पिछड़े राज्यों और पिछड़े क्षेत्रों को अधिक से अधिक वित्तीय सुविधायें दें, धन दें ताकि दूसरे क्षेत्रों के साथ वे अपना संतुलन कायम कर सकें।

अन्त में एक बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। दुर्भाग्य है कि मुझे समय बहुत देर से मिला है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस देश के संविधान ने हमारी राष्ट्र-भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार किया था। राष्ट्र भाषा हिन्दी को स्वीकार करने के साथ-साथ इस बात की सहिष्णुता भी उस समय प्रबल हुई थी कि पन्द्रह वर्ष में धीरे-धीरे हम हिन्दी को लायेंगे। मैं अपने डी० एम० के० के मित्र से सहमत हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से भाषा के सवाल को नहीं सोचना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि डी० एम० के० ने भाषा को एक राजनीतिक आधार बनाया है और उसको राजनीतिक आधार बना कर ही सरकार बनाकर बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक आधार पर हमें भाषा के सवाल को नहीं देखना है।

हिन्दी हमारे देश में, हमारे सचिवालय में और हमारे समस्त राज्यों में प्रगति करें, इसके लिये भी अभिभाषण में कोई विशेष उल्लेख नहीं है। मैं चाहूँगा कि हमारी केन्द्रीय सरकार तथा सरकारी अधिकारीगण हिन्दी के विकास के लिए कुछ कदम उठायें ताकि हमारी अपनी वाणी उभर सके और हमारे देश की वाणी जो सुप्त पड़ी है वह जागृत हो।

एक निवेदन और करना चाहता हूँ। इस हाउस में मजदूरों का रिप्रेजेन्टेशन होता है, किसानों का रिप्रेजेन्टेशन होता है, श्री रणधीर सिंह उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उद्योगपतियों का रिप्रेजेन्टेशन होता है, लेकिन 80 प्रतिशत आदमियों का, जो हल चलाते हैं, दूकान करते हैं, अपने छोटे-छोटे काम धन्धे करते हैं, कोई प्रतिनिधित्व यहां नहीं होता है। न तो यहां कोई उनकी सुरक्षा के लिए बोलता है, न इस सदन की तवज्जह उनकी तरफ जाती है। उनके वास्ते यहां कोई झगड़ा नहीं होता। छोटे दूकान्दारों, छोटे-छोटे काम करने वाले तम्बोली, नाई आदि, जो कि गांवों में अपना काम करते हैं, उनके ऊपर यहां पर समय नहीं दिया जाता, यह दुर्भाग्य की बात है। इस हाउस का समय जाता है राज्य-कर्मचारियों पर या बड़े बड़े उद्योगों में काम करने वालों की छोटी-छोटी बातों पर। इस समय जो 80 या 85 प्रतिशत समाज है उसके लिए हमें क्या करना है, इस पर कोई गम्भीरता से नहीं सोचता है।

इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण द्वारा जो दिशा हमारे सामने रक्खी है उसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और केन्द्रीय मंत्रियों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वह कुछ ऐसा करें जिससे नौ दिन चले अढ़ाई कोस वाली कहावत चरितार्थ न हो।

SHRI RAJARAM (Salem): Mr. Chairman, I thank you for the opportunity you have given me to participate in this discussion. An hon. Member from the opposite benches said just now that there was no representation for the petty shop-

[Shri Rajaram]

keepers in this House. Probably, there is no representation for them in the Congress Party. Our Party has got representatives from among the ordinary people who are having petty shops, etc. I wanted to convey this massage to him so that he may know the situation in the country.

In his Address, the President says that in Government's strategy of development, family planning programme continued to occupy pivotal importance. I am happy about the family planning programme catching up and becoming successful, as far as Tamil Nadu is concerned we had been given so many awards by the Central Government because of the success of our family planning programmes. In a way it is good; we receive awards and we are very happy to note that our people are taking to family planning in more numbers. My party also supports this programme. But at the same time, because of the family planning programmes our population had gone down in Tamil Nadu and because of that we had lost three representatives in this House. There is a proverb in Africa about the Europeans. That is : "Europeans giving the Africans a bible and taking away their land". So also, the Centre gives family planning awards to us and takes away three representatives from Tamil Nadu. If the Centre persists to favour States going against their family planning programmes—West Bengal did so and got more seats—the people of Tamil Nadu do not lack intelligence in knowing where their benefit lies.

They will also try to produce more children and they will thus make the entire family planning programme of yours collapse. So, I request the Central Government to bring in a good formula or a delimitation to bring more representatives to this House from Madras, because this is a democratic State and we do not want more awards but we want more representation in the Lok-Sabha from our State.

Apart from this, there is another aspect. The other day, myself and Mr. Govinda Menon participated in the function organised by the South Indian Welfare Association in Delhi. Mr. Govinda Menon, in addressing the gathering, said that Calcutta does not belong to the Bengalis alone but it is a national city; so also Bombay; it does not belong to Maharashtra alone but it is a national city; so also Madras; it does not belong to the Tamilians alone but it is a national city. This argument is very good as far as the Central Minister is concerned. He looks at it like that. But the face is, we face an acute shortage of water in Madras city. Our Central Ministers may describe Madras city as a national city. But when we are going with a begging bowl to another State for drinking water, then they are saying, "This river belongs to me. Do not tap this river. Do not come near or touch this place at all".

In this respect, I would like to make a request to the Central Government. The Central Government must come forward with a rule or something like that, in order to make all the rivers as national rivers, and to see that water is supplied to all the important cities of the country. Because, as it is, the cities are the central places of employment. People are coming from the villages to the urban areas to get salaries there. Industries are developing in and around the cities. So, if you do not supply even drinking water to the cities, what will be the fate of the national cities ? What is the meaning of national cities ? What is the meaning of national integration ? What is the meaning of all the big slogans you are using here without thinking of things which are essential to the State or the country ? In this respect, I want that all the rivers must come under the national purview and come under one control. If you do not give water for irrigation, at least give water for drinking purposes at least to the cities. That is my submission.

As far as my State is concerned, there is another big problem. Even now, our new Chief Minister, Shri Karunanidhi, has written a very big letter to the new Commerce Minister about it. It is the question of the textile mills of Coimbatore. Nearly 29 mills have closed in Coimbatore; nearly 30,000 people are unemployed there. There is a central organisation called the National Textile Corporation to take over some mills. It has got only

Rs. 1 crore, but it is not possible for them to help the mills with this.

Now, they have come to another conclusion. The State Government is ready to close the mills, and to abolish the sales-tax, the electricity revenue of something like that. So also the Chief Minister has made a request to the Central Government to abolish the excise duties on the yarn. Through this method, they wanted to open at least a few mills this year. Because of the closure of the textile mills, there is a very big problem in my State, and it is not possible for the State Government to control all these things, because the entire customs duty, the entire revenue, goes to the Centre. The States have no more power, but at the same time, the States people are being advised to control the entire situation.

So many Member's have participated in the debate on the President's Address and everyone has said something about Centre-State relations. As far as my party is concerned, we are also thinking about it. Not only the Democratic Party but also many eminent men who are outside the political field, also think like that· Even in October, 1968, inaugurating the Kashmir State People's Convention at Srinagar, Mr. Jayaprakash Narayan said that "there is an urgent need to review rhe Centre-State relationship from an entirely new angle". So also, Mr. Gajendragadkar, the former Chief Justice of India, said in a Tata Memorial Lecture at Bangalore :

> "Let the problem of Centre-State relations be dispassionately examined by constitutional lawyers and politicians and if necessary, let an attempt be made to make suitable amendments in the relevant provisions of the Constitution by the democratic process."

Our party's view is that the centre is concentrating too much power in its hands. leaving practically nothing to the States. This is not good for the country. The strength of the centre lies in the strength of the State and this could be achieved only if there is develution of powers now held by the Centre among the States. The Centre must devote more attention to defence. The strength of the Centre was understood from its abilty and capacity to resist aggression and not from the success it achieved in weakening the States and putting them down.

This is not only the view of DMK. At the time of the freedom struggle, the Congress Party talked about federal structure and autonomy for the provinces. Our leader, the late Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. Annadurai said :

> "Though India was administratively one, it was far from being emotionally integrated. We should learn a lesson from Qubec and try to cure our Constitution of the lacuna that had come up. The change that had been brought about in the country since the Constitution was drafted and new ideas that had developed should awaken us to face realities.
>
> Education was a State subject and still Centre had an Education Minister who sought to dictate to the States. Industries was a State subject but licensing being effected by the Centre and so States are powerless to act effectively."

We want a council to be formed as provided under article 263. Under this article, the President of the Union is authorised to esablish a Council by order if it appears to him at any time that the public interest woud be served by the establishment of such a Council to make among other things, recommendations for better coordination of policy and action. Where this coordination of policy and action does not exist, or is threatened with a breakdown, the needs of unity of action and preservation of the amity of of the country it self demand *that* suitable action should be taken to *place* Centre-State relations on an even keel. This is also dictated by commonsense. No one can deny that the inter-State and Centre-State relations are not what they should be.

In Tamil Nadu, we wanted a steel plant. In Andhra, they wanted a steel plant. In Mysore, they wanted a steel

[Shri Rajaram]
plant. The Centre was kind enough to satisfy one portion of the south by giving a Steel Minister to Mysore, instead of a steel plant ! Like this, the Centre is dodging the south. They must consider all these things and come to a proper conclusin about these things.

My party has had a very frinendly relationship with the Centre. We want it to continue this. The new ministry is having the same opinion. Our new Chief Minister, Mr. Karunanidhi said the same thing at Coimbatore on 23rd. That is not a big problem. But the Centre must give due respect to the States and redress the grievances of the States.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण अगले वर्ष के लिए सरकार के कार्यक्रमों की एक झलक होता है। उसी आधार पर यह निश्चय किया जाता है कि सरकार आगामी वर्षों में कौन से विशेष पग उठाने जा रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रपति के अभिभाषणों में देश की उलझी हुई समस्याओं के समाधान न देख कर यह आश्चर्य होता है कि आखिर यह सरकार विवादों को टालने वाली राजनीति कब तक इस देश में चालू रखना चाहती है।

अभी कुछ दिन पहले इस सदन में अविश्वास-प्रस्ताव पर बहस के दौरान शिव सेना की जो चर्चा आई थी, उसकी पृष्ठभूमि में भी इसी प्रकार का एक विवाद था जो वर्षों से चल रहा है। मेरा तात्पर्य मैसूर और महाराष्ट्र के सीमा-विवाद से है, जिसका समाधान महाजन कमीशन का प्रतिवेदन आने के पश्चात् भी अभी तक नहीं हो सका है। इसी प्रकार का एक दूसरा विवाद वह है जिसे कृष्णा गोदावरी जल विवाद कहा जाता है। इसी तरह का एक तीसरा विवाद नर्मदा नदी के पानी के प्रश्न पर मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में है। दुर्भाग्य यह है कि केन्द्र के वर्तमान नेता, जिनकी दृष्टि में सारा भारत एक होना चाहिए, वह जब अपने अपने राज्यों की सीमाओं में पहुंचते हैं, तो वे अपने आपको प्रान्तीय विवादों के साथ नत्थी कर लेते हैं। चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का एक विवाद चल रहा है। कुछ वर्ष पूर्व इस सम्बन्ध में यहां एक निर्णय लिया गया था। लेकिन अभी तक वह विवाद उलझा हुआ है और उसका कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। सभापति महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि विवादों को टालने वाली यह राजनीति इस देशकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेगी।

इस सम्बन्ध में मैं एक और भी उदाहरण देना चाहता हूं, जो कि इस सरकार के अनिश्चित मन का परिचायक है और वह है प्रधान मंत्री के निवास-स्थान का प्रश्न। कभी प्रधान मंत्री सोचती हैं कि हैदराबाद हाउस को प्रधान मंत्री का निवास-स्थान बनाया जायेगा। कभी कहा जाता है कि तीन-मूर्ति हाउस में जवाहरलाल जी के नाम पर जो संग्रहालय बना हुआ है, उसको शान्तिवन के पास ले जाया जायेगा और तीन-मूर्ति हाउस को प्रधान मंत्री का निवास-स्थान बना दिया जायेगा। कभी प्रधान मंत्री की तरफ से यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति भवन के क्षेत्र में प्रधान मंत्री के लिए एक नया निवास-स्थान बनाया जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश के हर विवाद और समस्या के सम्बन्ध में सरकार के इस प्रकार के अनिश्चित मन से किसी स्वस्थ और मजबूत सरकार की कल्पना नहीं होती है।

अभी गांधी-शताब्दी वर्ष के सम्बन्ध में सरकार की ओर से लेखकों का एक संकलन प्रकाशित हुआ है। उस किताब में कुछ विदेशी लेखकों के भी लेख हैं। श्री टायनबी ने अपने लेख में गांधी जी की तुलना करते हुए ईसा मसीह और मुहम्मद साहब की चर्चा की और यह भी लिखा कि मैं किन्हीं अर्थों

में गांधी जी को हजरत मुहम्मद साहब से भी ऊंचा समझता हूँ। यह किताब छप गई और लोगों के हाथों पहुंच गई। लेकिन कलकत्ता में कुछ लोगों ने जब उस बात को लेकर कुछ चर्चा की, तो अब उस किताब को फिर से बदला जा रहा है और उस लेख को हटा कर उस किताब को प्रकाशित किया जा रहा है। सरकार की यह अनिश्चित मन वाली नीति आगे चल कर सरकार को कभी बल नहीं दे सकेगी।

16.32 hrs.

(MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*)

जहां तक केन्द्र और राज्यों के सन्बन्धों का प्रश्न है, जिन राज्यों में गैर-कांग्रेसी मंत्रि-मंडल बने हैं, उनके और केन्द्रीय सरकार के बीच में कुछ खिचाव की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। कुछ दिनों पहले आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि पंजाब की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों पर अभियोग चलाये जा रहे थे, पंजाव सरकार उन्हें वापस ले लेगी। शायद बंगाल की सरकार भी निकट भविष्य में कुछ इसी प्रकार के विस्फोटक निर्णय ले। हो सकता है कि कुछ अन्य ग़ैर-कांग्रेसी राज्य सरकारों और केन्द्र के बीच में इसी प्रकार का खिचाव उत्पन्न हो। इस लिए आज आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्रीय सरकार को इस बारे में एक निश्चित नीति निर्धारित करनी चाहिए, ताकि हमारे देश की राजनीति में जो परिवर्तन हो रहा है, या हमारे देश की राजनीति जो करवट लेने जा रही है, उससे हमारे जनतंत्र पर और जनतंत्र की जड़ों पर, कोई आघात न हो।

जबसे मैं इस संसद् में आया हूँ, तबसे मेरा निश्चित मत यह रहा है कि शिव सेना, तेलंगाना, आसाम के पुनर्गठन, नदी-जल विवाद, पंजाब की समस्या और बंगाल जैसे सभी प्रश्नों का अगर कोई एक-मात्र उपाय है, तो वह यह है कि इस देश में एकात्मक शासन की स्थापना की जाये, यहां पर यूनिटरी फ़ार्म आफ़ गवर्नमैंट स्थापित की जाये। जब तक हम उस दिशा में कदम नहीं बढ़ायेंगे, तब तक हमारे देश में इस प्रकार के विवाद बने ही रहेंगे उनका समाधान नहीं हो पायेगा।

अभी कुछ दिनों पहले प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध में स्थायी शासन की चर्चा हुई। विभिन्न प्रदेशों में जो संविद की सरकारें बनी थीं, उनका जिस प्रकार पतन हुआ, उसको देखकर यह आशा थी कि इन मध्यावधि चुनावों में कांग्रेस शायद उन प्रदेशों में फिर से सत्तारूढ़ हो जाये। लेकिन हमने देखा कि जनता ने दो वर्ष पहले लिये गये अपने पुराने निर्णय को थोड़े-बहुत फेर-बदल के साथ ज्यों का त्यों कायम रखा और किसी भी राज्य में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। लेकिन स्थायी शासन देने का दावा करने वाले और स्थायी शासन का स्वप्न देखने वाले दल की स्थिति यह है कि उसके अपने घर से ही लोग निकल रहे हैं। आज उड़ीसा के शासन की बाग-डोर जिन लोगों के हाथ में है, वे कल तक कांग्रेस के ही अंग थे। मध्य प्रदेश की सरकार को आज जो लोग चला रहे हैं वे भी कल तक वे कांग्रेस में ही थे। लगभग हर एक राज्य में यही स्थिति है।

इसलिए मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि अब वह समय आ गया है कि वे हर एक प्रश्न पर अपनी पार्टी के बजाय देश को आगे रख कर विचार करें और उसी के अनुसार निर्णय लें। उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे यह कटु सत्य कहने की इजाजत दें कि जिन राज्यों में यह राजनैतिक अस्थिरता आई है, उनमें कांग्रेस ने कुछ व्यक्ति विशेषों को बचाने के लिए राज्य की पूरी राजनीति को खटाई में डाल दिया। बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आदि में एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए कांग्रेस ने पूरे राज्य की राज-नीति को अस्थिरता के द्वार पर लाकर खड़ा

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

कर दिया है। आज स्थिति यहां तक बिगड़ गई है कि चंडीगढ़ में जब हरियाणा एसेम्बली का अधिवेशन हुआ, तो सरकारी दल द्वारा अपने बहुमत को बनाये रखने के लिए कुछ सदस्यों को मुअत्तिल कर दिया गया और बड़ी भगदड़ में बजट को पास करा लिया गया। अगर इसी ढंग से सरकार को स्थायी बनाये रखना है, तो जनतंत्र के लिए यह बड़ा अभिशाप सिद्ध होगा। इन परिस्थितियों में आज सरकार को, और सरकार को चलाने वाले दल को भी, आत्म-निरीक्षण करना चाहिए।

मुझे यह देख कर बड़ा कष्ट हुआ कि पश्चिमी बंगाल में जो नई सरकार बनने जा रही है, उसने कहा है कि वहां के राज्यपाल, श्री धर्मवीर, को वापस बुला लिया जाये। मैंने समाचार पत्रों में यह भी पढ़ा है कि स्वयं श्री धर्मवीर ने भी यह इच्छा व्यक्त की है कि अब वह पश्चिमी बंगाल की राजनीति से और इस दिन-रात की परेशानी से अलग होना चाहते हैं। लेकिन इस बारे में मुझे सबसे बड़ी शिकायत प्रधान मंत्री से है। जब प्रधान मंत्री शान्ति-निकेतन विश्वविद्यालय में दीक्षान्त-भाषण देने के लिए गई तो उन से पूछा गया कि पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल को हटाने के सम्बन्ध में आप की क्या राय है। प्रधान मंत्री ने उत्तर दिया कि अभी तो किसी ने हमको इस बारे में लिखा ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि प्रधान मंत्री ने इस असंतोष को स्वयं आमंत्रित किया है। उनको उसी समय कहना चाहिए था कि राज्यपाल को हटाने या न हटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, उसके पद का एक विशेष महत्व और उसकी एक विशेष प्रतिष्ठा और गरिमा होती है। अगर केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों की मांग पर राज्यपालों को हटाना प्रारम्भ कर दिया, तो राज्यपाल राज्य सरकारों के डिपुटी सेक्रे-टरी मात्र बन कर रह जायेंगे और वे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा को कायम नहीं रख सकेंगे।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर श्री धर्मवीर स्वयं किसी कारण से अपने पद से हटना चाहते हैं, तो उनको वहां से इन परिस्थितियों में हटाया न जाये, बल्कि डिसमिस कर दिया जाये। उनको हटाया तब जाये, जब राष्ट्रपति सब परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए इसके लिए सहमत हों। लेकिन किसी राज्य सरकार के कहने पर वहां के राज्यपाल को हटाने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिमी बंगाल में किसी मजबूत व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की चर्चा की जाती है। माननीय सदस्य, श्री शिव नारायण, की भी चर्चा इस बारे में की जा रही है। लेकिन आज वह परिस्थिति अभी नहीं है, जब कि पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किसी दूसरे नाम की चर्चा की जाये।

यह गांधी-शताब्दी का साल है। कम से कम इस साल सरकार को गांधीजी के जीवन से सम्बन्धित दो प्रश्नों, मद्य-निषेध और राज-भाषा हिन्दी के प्रश्नों, के बारे में कोई स्थायी निर्णय लेना चाहिए। इन प्रश्नों को भी सरकार अपने अनिश्चित मन का शिकार बना कर हमेशा के लिए टाल कर न रखे। राज-भाषा (संशोधन) विधेयक और तत्सम्बन्धी प्रस्ताव के पास होने के बाद भी आज इस सदन में यह स्थिति है कि यहां पर जितने विधेयक आदि आते हैं वे सब अंग्रेजी में होते हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें सरकार को क्या आपत्ति है कि सब विधेयकों का अधिकृत मूल पाठ दोनों भाषाओं में हो। राजभाषा (संशोधन) विधेयक के स्वीकृत होने के बाद सरकार का यह अधूरा निर्णय कहां की समझदारी है?

कुछ मित्रों को आकाशवाणी से हिन्दी के समाचार बुलेटिन को पंद्रह मिनट पहले कर

देने के बारे में शिकायत है। अगर ऐसा करने से क्षेत्रीय भाषाओं के किसी कार्यक्रम में कोई कमी हुई हो, तो मैं स्वयं उस को पसन्द नहीं करूंगा और आकाशवाणी के अधिकारियों से कहूंगा कि उन्होंने ऐसा करके गलती की है। क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजी या हिन्दी के समाचार बुलिटनों को पंद्रह मिनट पहले या पीछे कर देने के प्रश्न को एक राजनैतिक हथियार बनाया जाये, यह कोई राजनैतिक बुद्धिमत्ता नहीं है।

सौभाग्य से शिक्षा मंत्री इस समय सदन में उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के डिग्री कालेज लगभग एक महीने से बन्द पड़े हैं। आज वहां पर परीक्षाओं का समय बिल्कुल निकट आ गया है। उत्तर प्रदेश के डिग्री कालेजों के अध्यापकों का एक शिष्ट-मंडल डा० राव से मिला था।

डा० राव ने उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार से जितना अधिक से अधिक हो सकेगा यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के सुझावों के आधार पर कहूंगा कि वे इसको स्वीकार करें। उत्तर प्रदेश के अभिभावक परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, पूरे प्रांत की विश्व-विद्यालय स्तर की शिक्षा एक महीने से ठप पड़ी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि डा० राव जो स्वयं एक शिक्षा शास्त्री हैं और जिनका शिक्षकों की समस्याओं से निकट का परिचय है, वह अपने प्रभाव का उपयोग करें और उत्तर प्रदेश की शिक्षकों की हड़ताल को समाप्त करा कर शिक्षकों की मांगों का उचित रूप से समाधान करें।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Dr. Rao.

SHRI RAJARAM : On what is he speaking ?

MR. DEPUTY-SPEAKER He is intervening in the debate.

SHRI RAJARAM : Is he speaking on transport or on education ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : He was provoked to intervene by Shastriji just now.

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V.K.R.V. RAO) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is with a certain amout of diffidence and hesitation that I am rising in my new seat as the Union Education Minister to iter-vene in this debate. I say "diffidence and hesitation" because it was one thing for me to be bothered about the problems of education, of youth unrest, of educated unemployment, of conditions and status of teachers and so on as a citizen and then as a member of the Cabinet not functioning in charge of the subject and it is quite a different thing, I find now, when I have got to be concerned with them functionally. When I look at the vastness of the area that I have to cover and the complexity of the problem in fact, if I may say so, the intractability of the problems that I have to deal with, I feel diffident to day, though normally I am very confident person and I would like to crave the indulgence of the House and seek their moral support, their understanding and their sympathy to help me in carrying through this very difficult assignment that has fallen to my lot. I am sure, the House will give me the co-operation and understanding that I need if I am to make any success of the job that I have undertaken.

The importance of education seems to have been underlined by a number of speakers in the course of the debate on the President's Address. I also find that a large number of amendments which have been moved or given notice of, also deal with one or the other aspect of the problems of education and young people. It is because I saw that there were so many amendments dealing with this subject and also because I found from the record of proceedings that a number of hon. Members had drawn attention to problems relating to education, that I thought it would be proper on my part to make a few remarks even though I certainly do not propose to proclaim any new policies or to make any bold premises.

[Dr. V. K. R. V. Rao]

First of all, I should like to welcome the general feeling of satisfaction that seems to have been expressed, both in this House and outside, on the redesignation of the Ministry of Education as the Ministry of Education and Youth Services. The object in making this redesignation is to underline the great importance which Government attaches to the problem of youth welfare, youth services and problems of student and youth ferment that has been plaguing the country now for some years. I am not yet in a position to give any statement of policy as to what we are going to do in regard to the setting up either of a department of Youth Services or the precise programme we shall try to undertake for the betterment of youth in this country. What I would like to do is to have discussions with Members of this hon. House, particularly my hon. friends who sit on the Opposition Benches. I also hope to have disscussions with Vice-Chancellors of universities, Principals of colleges, representatives or leaders of student organisations, not to discuss the causes of student unrest—I think, the malady is fairly well known and I do not think it is necessary to appoint a commission or a committee or call a big conference in order to find out why there is all this unrest in this country— but to find out what practical programmes could be undertaken to deal with this problem, even if we are able to deal with it only in a limited and a modest kind of way.

In the meanwhile, I should like to say just a few words on the problem as I see it now. You must not forget that we have a large number of students and when we send them to schools or colleges, as the case may be, certain physical requirements of education have got to be satisfied. There must be adequate provision for things like class rooms, playing fields for games, sports, etc. Students, when they go to college or school, as the case may be, should not feel all the time restrained and constrained and merely cooped up to listen to lectures. This is something which is very important. I am sure, if you go into the analysis of the various troubles that have taken place, you will find that institutions which have good physical facilities, which give opportunities to students to breathe fresh air, even physical freedom, are much better off than institutions which are overcrowded or are in overcrowded localities where the physical facilities are wanting, where there are no playing fields and hardly any games, sports or other activities. This is something which has got to be gone into. But I must warn the House that it is quite easy to make a diagnosis. The diagnosis has to be followed by prescription. Even the prescription, I do not think, is going to be difficult. The greater difficulty is to find the persons to dispense the prescription, to find resources for it and to see that the prescription which is given for the disease is going to be implemented.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): You are responsible for it.

DR. V. K. R. V. RAO: Well, I am quite prepared to accept the responsibility as a Member of the Government. But, I think, the honourable House must also accept the responsibility for this because they know, as I know, what the resources of this country are, what the total financial resources of the Central and State Governments are, what the level of taxation is, what the demands are which have been made on the Central and State Governments, what is the priority that is being assigned to education in the Central and State Budgets and Plans, etc. They are as much aware of this as I am. A number of my friends on the opposite side are also functioning as responsible Governments in some States. I am prepared to accept the responsibility as a member of Central Gevernment. But I think, the responsibility has to be shared also by my hon. friends on the opposite.

This is a problem which cannot be solved in a day. It has got to be identified in the first instance and then brought to the notice of each local authority. I would like to do so State by State and even city by city. I think that there should be an individual study of the institutions and the public must understand that there are so many schools and so many colleges which have no playing grounds, which have no common rooms, which have no canteens, which have no facilities for students or for scholars. I think, these things must be brought out in the open so that, one by

one, we try to see how with Government assistance and public support and other means we are able to solve it.

Then, there is another thing which also, in my opinion, is responsible for all the bad things that are happening, and that is about the academic requirements. For example, in many institutions the teacher-pupil ratio is not satisfactory. We also know that in many institutions the teachers are not in a position to give enough time to their students. They are very much absorbed, at the moment, by their own economic difficulties and by their own stresses and strains. We also know that, in many institutions, libraries are not sufficient and there are not enough reading rooms ; and so on. It is not only the physical side but also the academic side that is important. We have an enormous structure in terms of statistics. We are highly advanced in statistics. I can give you the number of colleges, the number of schools, the number of scholars and so on. But when you come down to what it means in academic terms, I am afraid, the academic content of the institutions that we have in certainly not all similar and in many institutions, even the required academic content, the essential academic facilities are also wanting. Again, what we can do is to identify these and all of us have to sit round and find out in what way we can remedy the situation.

Then, there are one or two things where, I think, we can do something. Those things which I mentioned involve, what I may call, 'finance and resources', where there are some limitations. But, I think, there are certain other fields where the financial and resource limitations do not operate to the same extent. One of these is to give the students a feeling of participation in the academic process. This is a subject on which there has been a great deal of discussion all over the world ; even in conservative countries like the United Kingdom, some forward steps have been taken for the purpose of getting some kind of student participation and student involvement in the academic process. This matter is also under discussion and examination in our own country, and I hope that something will emerge which will make the students feel that they are not merely to be ordered about or to be told what to do and what not to do and that they will also have a share in the academic process itself so that they will feel that they are partners rather than merely pupils. How precisely this should be done is an academic matter, and this matter has to be discussed by experts in consultation with, I hope, student representatives. I believe that the matter is under the active consideration of the University Grants Commission as well as of a number of other university bodies. Once we can get the students to participate in the academic process, then I have a feeling that even some of the other problems which I have mentioned may find themselves a little easier of solution.

The second thing which is very important and remedy for which rests on us is the example that the students get from non-students, the example that the young get from the non-young, the example that the people who do not have work get from those who have work and who are better-off in society. I think that there is no denying the fact that example plays an important part in setting the social milieu, in influencing conduct. All that I can say is that on all of us, whatever walk of life we may belong to, political, party, functional, occupational, income, caste, community or otherwise, has descended today a responsibility such as perhaps has not been with us for a long time in the past. How we function, how we behave, has a direct influence, not only on those with whom we behave but on the vast masses of the young people who, consciously or unconsciously, are influenced by our conduct and behaviour. So, the adult population also, if I may say so, has a responsibility in this matter of bringing about a termination to these difficulties in which we are finding ourselves now.

Another one where we can do something because it does not involve money is this. This is one of the things which I am going to do. I am going to make a rigorous classification of all those remedies which need money and resources and those which do not need money and resources so much as co-operation, motivation, participation,

[Dr. V. K. R. V. Rao]

discussion, dialogue and so on. I think, in many places, there are small grievances of students and no machinery exists for the ventilation of these grievances. This is recognised. We are all agreed that there should be student-teacher councils for the purpose of looking after these problems. But I am not sure how far every collegiate institution, how far every university, has set up bodies for the purpose of ventilating student-teacher grievances. This is a matter which we can take up.

Also, it is important that there should be somebody in the university and in the college who should be specially charged with the task of anticipating the troubles of the students before they emerge in vocal and articulate form and take on an unpleasant direction which afterwards we all try to deplore. A number of universities have appointed Deans of students, but I do not know what the colleges have done in the matter. Some colleges are as big as universities ; there are about 2,000 or 3,000 or 4,000 or 5,000 students. Some of the schools have about 2,000 to 3,000 students. This is a matter of student guidance, student counselling ; some machinery, for the purpose of going into the troubles and grievances of students and trying to see what can be done about them, has to be created. This can be done without a great deal of money.

I believe—I do not know; I may be an idealist—but I do believe that the young are idealistic in any country in the world. I believe that in our country, the young have a tradition of idealism. What is required is the key to open this closed door of idealism in our younger generation. This country is not wanting in opportunities for social work. There is no country in the world where there are so many opportunities for social work, where there are so many calls on the social conscience, where there is so much of distress, as this country has; and if only we could create the atmosphere, and the climate, these young people, once they answer the calls, will astonish all of us by the vigour and force with which they will divert and channelise their energy in terms of social work and in terms of fulfilling the urges of the social conscience. I have heard for example that at the time of the Bihar famine, quite a member of students and teachers went there and did excellent work; I am similarly told, that during the time of the Koyna earthquake, a large number of students went and did excellent work. Whenever a call is given, the students are ready to respond. We have got to create opportunities and give them the feeling that they are persons who are in charge of the social conscience of this country and that they have got to play their part. This can be done if we also join them—teachers, ministers, vice-chancellors, professors, principals; I have no doubt in my mind that it would be possible to stimulate the social conscience. We are trying to set up what is called the national service scheme and to introduce it in all the colleges. That may give us some kind of a machinery. I do not think that all these things can be done only at the governmental level or merely by setting up directorates in my ministry or anywhere else. In the last analysis, the climate has to be created. Projects undertaken should preferably be local projects of immediate importance to the students and parents concerned. In the course of the next few months, with the co-operation of all the persons here and outside, I hope to see if it would be possible to reawaken the social urges and the social concience among the young people of this country. This is the Gandhi centenary year. I do not want to take Gandhiji's name in vain. But I do think that Gandhi's name still has an appeal and that it may be possible to realise some of our ideals during the Gandhi Centenary year. This will not only be a tribute to the memory of Gandhiji but also help us in many ways. Later on, I should like to come before the House, after we have made our plans and have some concrete programmes to put forward regarding the youth services and make a statement as to what the youth service department or division is going to do. I want the support of this House to see that as much resources as possible are made available for this programme. It is not good merely to have ideas; we have ideas in plenty and what we need is action or implementation. Unfortunately implementation does require some

resources. Some resources have to be found and the necessary priorities have to be given if we seriously believe, as so many of us seem to do, that the problem of youth and student unrest is a problem of cardinal importance facing the country today.

There are two or three specific points raised in the House. My friend Mr. Banerjee referred to the seven thousand instructors under the national discipline scheme. I do not want to go into the details of that scheme. Mr. Banerjee, I am sorry to find, is not here; he made a number of remarks, not all of them accurate, but he dispayed considerable knowledge about files and information available in the Ministry. He is not here now; I have told him outside the House and I want to say this again that if he wants information, I am prepared to supply him all information; it is not necessary for him to get information through any other source. As far as this scheme is concerned, the decentralised scheme has not yet been brought into force, because the State Governments had been approached to take the instructions and the instructors had been asked whether they would go to the State Governments.

SHRI A. SREEDHARAN (Badagara): We are not prepared to take more liablities; we do not have money. So, the Kerala Government has refused.

I am quite aware that some States have not accepted it. I did not say that all the States have accepted. All that I said was—(*Interruption*)

17 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER Order, order.

DR. V.K.R.V. RAO: If the hon. Member will extend to me the same indulgence which he extended for the last 25 minutes, I shall be happy to place the facts before him. The position is this. There are about 7,000 instructors. They were all under a Central National Discipline Scheme. These people are all working in the States. Though it was a central scheme, it was paid for by the Centre and there was an organisational set-up, administrative set-up, at the Centre with regional units. In 1965, as a result of the Kunzru Committee report, it was decided to have one integrated system of physical education in the schools and it was decided to create what was called the National Fitness Corps. At that time it was decided the National Discipline Scheme should be decentralised. The discussion went on between the State Governments and the Central Government as to the terms and conditions on which the 7,000 people would be taken over by the States. This discussion is still going on, and the Centre has made some financial promise. The States are not satisfied with the financial inducement offered by the Centre. All the instructors have not expressed their opinion as to whether they would like to be transferred to the State Governments and the State Governments have not all agreed that they are prepared to take them over. The whole position is still in a very fluid state. But nobody has been thrown out of work.

As I am responsible as a Central Minister, I shall try my best to see that this problem is solved, as quickly as possible, and even if I find myself in difficulty, I am quite prepared to take the House into confidence because I know that the House will understand the facts and will give me the support which I need in dealing with this problem.

The other question to which reference has been made, to which reference has also been made by my friend Shri Prakash Vir Shastri, is the question of the Uttar Pradesh college teachers' strike. I met another delegation, of the Uttar Pradesh College Teachers a few minutes ago just before I came into the House. In the case of the Uttar Pradesh College teachers, there has been some difficulty about the implementation, by the Uttar Pradesh Government, of the proposals of the UGC Committee which were accepted by the Central Government and recommended to the State Governments and for which the Central Government is prepared to give 80 per cent of the difference between the additional cost incurred by the acceptance

[Dr. V. K. R. V. Rao]

of the scheme and the total cost. But as far as the UGC scheme is concerned, to the best of my knowledge from the recent communication I have received from the Government, it seems that the Uttar Pradesh Government are willing to accept what the UGC Committee have suggested. The only problem that remains is what is called the problem of service increment. But the demand by the Uttar Pradesh College Teachers exceeds, I am afraid the recommendations of the UGC Committee, and beyond the recommendations which were accepted and recommended to the State Government for implementation by the Centre. For example, they want an integrated pay-structure, dearness allowance at Central rates and one or two other things. I have told my friends, that it would be very difficult for me to take up these matters. As far as I am concerned, as a Central Minister, I would be prepared to try my best to see that the recommendations of the UGC Committee, accepted by the Central Government and recommended to the State Governments are implemented. I shall do my best to see that that is done.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : केन्द्रीय सरकार ने जो पैसा दिया था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वह पूरा पैसा भी टीचर्स को नहीं दिया, उसमें से भी कई लाख बचा लिए। इसलिए कम से कम इतना तो कीजिए कि जो पैसा टीचर्स के लिए आप दें वह तो उनको मिल जाया करे, उसमें तो कटौती न हो।

DR. V.K.R.V. RAO: I do not want to go into the details, but without accepting the validity of what he is saying, I can assure him that whatever money the Central Government gives for the purpose of improvement of the scales of pay of the college teachers will be spent only for that purpose and not for any other purpose.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi): The Uttar Pradesh College teachers want that whatever scheme of payment according to the UGC Committee has been accepted by the other States, should apply to Uttar Pradesh also.

DR. V.K.R.V. RAO: They want more than that.

SHRI BAL RAJ MADHOK: At least, what has been got in the case of the other States should be accepted in the case of Uttar Pradesh teachers also. At least this must be got implemented. (*Interruption*)

DR. V.K.R.V. RAO: I do not want to go into the details. I believe that is the position of the U. P. Government now.

SHRI SHEO NARAIN: It should be from Rs. 300 to Rs. 600, or running upto Rs. 800.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, काशी विद्यापीठ, वाराणसी को सरकार यहां से ग्रान्ट देती है लेकिन पिछले कई वर्षों से उसे पूरी ग्रान्ट का पैसा नहीं मिला है जिसके कारण वहां के अध्यापकों को तीन महीने तक हड़ताल करनी पड़ी। किसी तरीके से इधर उधर करके, उनको पैसा देकर हड़ताल को समाप्त किया गया लेकिन अब फिर वही मसला सामने आने वाला है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो ग्रान्ट काशी विद्यापीठ, वाराणसी को आप देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसे देने में आपको क्या कठिनाई है ?

दूसरी बात यह है कि जो फैसिलिटीज आप सेन्ट्रल एडमिनिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज को देते हैं, मंहगाई भत्ता या दूसरी सहूलियत, वह वहां के टीचर्स को क्यों नहीं दे रहे हैं ? इसके बारे में आपके सामने क्या कठिनाई है और उसको दूर करने के लिए आप क्या सोचते हैं ? पिछली बार इसी सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार उनके ऊपर विचार करेगी और उसको जल्दी से जल्दी लागू करने की कोशिश करेगी।

Dr. V. K. R. V. RAO: I will look into it. I got a telegram that there was a hunger strike. But later on I was told that the strike has been called off and

the matter has been settled. He has raised certain questions, which I shall look into.

श्री रामावतार शास्त्री : वहां के अध्यापकों का प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है और वह आपसे मिलना चाहता है ।

DR. V. K. R. V. RAO : I am always willing to see people. So far, I have not received any request. I am prepared to see them.

DR. SUSHILA NAYAR: So far as the UGC scales which you are prepared to concede and work for are concerned, may I know, from what date those scales will become applicable? It makes a lot of difference if they are given these scales from the date when the decision was taken or from a later date ? I hope the minister will give some indication about this.

Dr. V. K. R. V. RAO: I cannot give a precise answer. The Central Government communicated these recommendations some time in 1966. They said, they will be willing to pay 80 per cent of the difference, for a period of five years. I will find out from which date actually that will apply.

श्री कंवर लाल गुप्त : दिल्ली के टीचर्स का जो पे स्केल है उसका सीधा सम्बन्ध आपसे है और इस सदन में भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि जो रिवीजन पे स्केल्स का हुआ उसमें 15 लाख रुपया टीचर्स को और मिलेगा लेकिन अभी जो दिल्ली प्रशासन ने कल्कुलेट किया है उसके हिसाब से एक लाख का ही फायदा होता है। एजुकेशन मिनिस्टर ने दूसरा एश्योरेन्स यह दिया था कि हर एक टीचर को एक इंक्रीमेन्ट मिल जायेगा । मैं जानना चाहता हूँ कि :

इंक्रीमेन्ट के सम्बन्ध में फैसला कब तक हो जायेगा और 15 लाख रुपया ज्यादा देने के लिए कहा था, वह पूरा रुपया देंगे या एक लाख रुपया ही देंगे ?

दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली की और है । 6000 लड़के अभी पढ़ करके कालेज में ऐडमिशन चाहेंगे जबकि आपके पास जो कैपेसिटी है वह केवल 2500 की है । साढ़े तीन हजार लड़कों का कोई इंतजाम नहीं हुआ है । न दिल्ली युनिवर्सिटी उसको देख रही है और जहां तक दिल्ली प्रशासन का सम्बन्ध है उसने कहा है कि वह केवल दो नये कालिज खोलेगा तो क्या मंत्री महोदय इस बात की गारन्टी देंगे कि युनिवर्सिटी कंडिशंस के मुताबिक जो भी स्टुडेंट्स एलिजिबल होंगे उन सबको वह ऐडमिशन देंगे ? अगर यह बात होगी तब तो मंत्री महोदय जो कहते हैं वह अमल में आता है वरना इस तरह से भाषण देने और सरमंस प्रीच करने से कोई काम होने वाला नहीं है ।

DR.V.K.R.V. RAO : I am very grateful to the hon. Member for his reference to some of my previous services. Here I may say that I had the distinction and proud privilege of being the teacher of my hon. friend for some time and having been a teacher, I would not like to give sermons to a student. The first point which the hon. Member raised is about remuneration of Delhi teachers. I am afraid, I have no knowledge at all of this particular question. I will have to get the details. I may inform the hon. Member that after I became Minister, two deputations of Delhi school teachers came to see me. In the morning five people came to see me. One of them said that he was the Secretary of the Joint Council. Then, in the afternoon or evening, about 15 or 20 people came. They said they were from the Delhi Teachers' Association, representing 30,000 teachers of Delhi. They came with garlands. They were extremely happy that I, a teacher have, become Education Minister. I told them "I have no money; do not ask for anything that involves money." They did not say anything about money. We had a very nice chat. We discussed what should be done for education, social urges and so on and they departed. May be, after listening to my hon. friend, they may come to me again. I am only saying that, when they met me, they discussed moral strength, improvement of educational standards and allied topics only. Regarding the specific problem raised by the hon. Member I will

[Dr. V. K. R. V. Rao]

look into whatever assurances have been given and see what can be done.

Regarding the second question, ever since the days I was in the University of Delhi, I have known Shri Kanwar Lal Gupta. Long before he became a distinguished member of a distinguished political party, he has always been a champion of additional colleges for students. Every year, two or three months before the admission begins, Shri Kanwar Lal Gupta meets the Vice-Chancellor, whoever he is, and asks him about the admission of eligible students. I have great respect for the way in which he has championed the cause of the younger generation of students who seek admission in colleges. As regards the specific question whether I can give him an assurance that I am prepared to open new colleges, I am afraid I can give him no such specifiic assurance. I will have to find out what the position is. I will have to see whose constitutional responsibility it is. I will have to find out what the financial implications are and then I will have to talk to my colleague in the Ministry of Finance. After I have done all that, I shall be only too glad to give him the information, informally if he wants or, if he prefers, he can ask a question at the the appropriate time and I will give the information in the House.

SHRI BAL RAJ MADHOK : In Delhi we have an School of International Studies. A committee called Chenna Reddy Committee was appointed by the Government to go into its working and that committee has suggested that it requires certain improvement. What I would suggest is that till a full discussion of the report takes place let it not be implemented.

There is another institution for which also the Centre is responsible and that is Jamia Milia. Three students have been dismissed from that college for trivial reasons. They have filed writ petitions in the High Court and the High Court has upheld the objection. They have been dismissed from the college simply because of communal reasons and being a Central Institute I would like you to refer to that also. If this kind of thing can happen in an institution run in Delhi itself, under the very eyes and nose of the Central Government, what about other institutions ?

DR. V. K. R. V. RAO : I was going to say something about the School of International Studies. It was the next point in my list. I am aware that certain decisions have already been taken regarding the budget of the School of International Studies for next year. I have also come to understand that the recommendations of this Committee, which the hon. Member has referred to, have been accepted without prior discussion with the authorities of the School of International Studies. I have, therefore, asked my Ministry to arrange a meeting with the Chairman of the Governing Body and the people concerned in the School of International Studies in a day or two so that I can come to understand what their viewpoint is and I can try to see, to the extent I can, that their difficulties and their point of view are taken into consideration before the decision is finalised.

SHRI BAL RAJ MADHOK : May I know whether any Members of Parliament will be associated with such a discussion ?

DR. V. K. R. V. RAO : I am very sorry that this is not possible. It is purely and entirely an academic matter between the School of International Studies and the granting authority, which is normally the UGC but in this case it so happens that the maintenance grant is given by the Government of India.

17-15 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

Regarding the other question, I shall certainly look into it. But if I may make a personal appeal to my hon. friend, Shri Bal Raj Madhok, whom also I have known for many years as a fellow teacher in the Delhi University, any such reference he may kindly make to me personally rather than on the forum of Lok Sabha. In matters relating to communalism, this, that and so on—they are very delicate and sensitive—if he will write to me or tell me, I will assure him that I will get all the information that is required. But I beg of him not to bring such matters before the House.

Sir, I have finished all the points that I wanted to make. I want to end only by saying that, when I was a member of the Planning Commission I was dealing with education and at that time the Planning Commission, in the abortive or stillborn Draft Fourth Plan, of which I was a signatory, had allocated Rs. 1,210 crores for education out of a total outlay of Rs. 16,000 crores. I believe, the total outlay has not undergone much reduction in the revised or the new Fourth Plan. But I understand—I have not got any official intimation as such—that the allocation made to education is Rs. 809 crores as against Rs. 1,20 crores which was the amount agreed to by the previous Planning Commission. I would like to tell this House that if this House wants—and I am sure it does—apart from the House wanting—so do I; I have not come into this job merely to keep my seat warm—I am anxious to see that within the limitations of resources and other things, I do the best I can for the improvement of the educational system of this country at all levels. Something can be done even by sermons, something can be done by going round and involving people's commitment and so on. But I am afraid, money is an essential ingredient for success in these matters. I hope, when the occasion comes, I shall have the full support of the country in seeing to it that the proper priority is given to education in our national planning and the necessary resources are made available for the purpose.

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati) : Sir, just now we heard the hon. Education Minister. It was like a convocation address that he addressed to this House and he has tried to have our sympathy and co-operation.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : He has it .

SHRI DHIRESWAR KALITA : Of course, he has and he will get it. But though he ended with Gandhiji's centenary and all these things, he did not touch a single point about basic education or Gandhiji's ideas about basic education. In the National Integration Council in Kashmir this very question of the public schools, the Montessory or primary *pathshalas* and all these things was discussed. It is at the primary stage of education that disintegration begins. Class society begins from the very beginning of our school education. That must be abolished. That was the idea of Gandhiji. I do not know whether he is a follower of Gandhiji or not but his Government is a follower of Gandhiji Therefore this public school system must be abolished. This had provoked me to speak in this debate.

Secondly, I also received a letter from Shri Shankar Rao Deo to Members of Parliament which says :—

> "I would request you to bear in mind that British capital in India in mines, plantations, industries has multiplied nearly fourfold since our independence. It amounts to billions of rupees. All parties ought to forget their differences and combine peacefully to convert such vast concentration of private wealth into common wealth.
>
> "I would therefore, request you to work individually or through your party to see that Parliament enacts Trusteeship legislation during the Gandhi Centenary Year.
>
> Yours sincerely,
> Sd/-Shankarrao Deo"

This is a letter addressed to all Members of Parliament. During the last 20 years of our Independence, what is happening, what we have seen, is that the miseries of the people are growing. The unemployment is growing. The Birlas asset, the liquid capital, is growing. I think that is not due to a family friendship to Mrs. Indira Gandhi. In spite of that, the capitalist class is growing like anything. The British capital is growing, the foreign American capital is growing, in our country. May I ask why the hon. President who gave the Address to both Houses of Parliament has not mentioned a single word that, when we are independent today, we shall at least try humbly to liquidate British capital or curb British capital or curb foreign capital and curb monopolies ? Nothing of the sort. He has given indication of certain enactments which are

[Shri Dhireswar Kalita]

coming before Parliament. We have not seen any indication that this Government is going to bring a socialistic pattern of society which they always vouchsafe. They always say that they are going to build a socialistic pattern of society. Now they have happily even forgotten to mention the word "socialistic pattern". Why ? Why has the hon. President, the Government, forgotten that ? I do not know. Because kings are ruling in the Cabinet, the issue of privy purses and privileges is being pushed up. The All-India Congress Committee has accepted it. Times without number, in this House, they have said that they will abolish these privy purses and privileges. Mr. Govinda Menon has been speaking in meetings that there is no law which can debar the Government of India abolishing the privy purses and privileges. But Mr. Chavan is holding meeting with Maharaja Dhrangadhra and all other Maharajas. Uptill now nothing has come out. This is the socialistic pattern of society.

In the last 20 years, the people have become poorer and poorer. The unemployment is growing; the foreign capital is growing; the rajas and maharajas are having privy purses and privileges. Nothing of the sort is mentioned in the President's Address. Therefore, I oppose it.

Then, naturally, we have got our grievances against this Government. Yesterday, my hon. friend, Mr. Sheo Narain said about the Commonwealth meeting. The hon. President has forgotten to mention about our relationship with the British Commonwealth. Why are we in the British Commonwealth ? Our Prime Minister went to London last time, discussed the matters and talked with them. But not a single resolution could come on the Rhodesian issue. The Rhodesian issue was shelved. It was discussed but no resolution could come. About racialism, no resolution could come; about immigrants issue, no resolution could come. What came was only a photograph of Mrs. Indira Gandhi in the backrow Seat. Why are we in the British Commonwealth ? How has it benefited us ? In which way, economically, politically or otherwise, as a prestige, has it benefited us ? It is a shame to this Government that uptill now India is in the British Commonwealth. We must kick it out. We must come out from the British Commonwealth.

Regarding disintegration, many speeches have been made in the course of the debate on the no-confidence motion. The disintegrating outlook and fissiparous tendencies are there. Mr. Brahmananda Reddy says that his heart burns when he comes to know that the Damodar Valley Corporation is a Central project and Nagarjunasagar is a provincial project; he says that his heart burns. Mr. V. P. Naik of Maharashtra has been demanding of the Centre times without number that licences for more sugar-crushing factories should be given, but the Centre is rejecting. The Tamil Nadu Government are demanding licences for more sugar-crushing factories. But the magnates of sugar from North India are pressing hard; rather, through their behest, the Government is withholding them. Kerala also has its demands in regard to industry. Bengal and Assam also have got their demands. As you know, Sir, Assam is a backward State; it has full of resources; crude oil, coal and all other mineral resources are there, but I must say that, during the last 20 years, Assam has not been getting the proper treatment from the Government of India. In demanding a second refinery, a broad-gauge line and a second bridge on Brahmaputra, all parties, including the Government of Assam are united, but the Central Government is rejecting; I have raised these things times without number. Yesterday, Mr. Hem Barua, said that if the Centre did not give all these things, Assam would go out of India. In the present background of India, this is a very dangerous statement, a disruptive statement...

SHRI R. BARUA (Jorhat): I want to put the records straight. I am very sorry that such a statement was made on behalf of Assam by the hon. Member. I can assure you that all political parties, all the people of Assam, irrespective of their ethnic, social and political complexes, are not going to support such divisive attitude.

MR. SPEAKER: This is what Mr. Kalitha is also saying.

SHRI R. BARUA: He may have his own view, but Assam will not go out of India. (*Interruptions*)

SHRI DHIRESWAR KALITA: As I was saying, this is a chauvinistic, parochial, disruptive statement. Today Shiv Sena is creating havoc in Bombay. I do not know whether this is the policy of the PSP, because the hon. Member, Shri Nath Pai, took great pains to explain his position in the House when Mr. Fernandes attacked him about hobnobbing with Shiv Sena in Bombay. So, I think this is their policy. If, in the background of Shiv Sena activities, men like Shri Hem Barua make such irresponsible statements, I am afraid that it will not help the country in integration. We, the Members of Parliament, have sworn by the Constitution. Of course, Assam as a part of India, has some genuine grievances. Not only Assam, when Kerala Government was demanding rice, the Central Government rejected it. Does it mean that Kerala should go out of India? No. When Bengal was demanding that it should be allowed to purchase rice from Orissa, Central Government rejected it. Does it mean that Bengal should go out of India? No. We shall have our democratic movement, the united movement, and we shall snatch it from the unwilling hands of the Government.

If we cannot, we shall replace this Government; we shall have a better and different Government than this unwilling Government. This is a Government run under the dictates of capitalists, landlords, monopolists, kings and queens. We shall have to change this leadership; by changing this leadership we shall, all states remain in India, equally and freely developing as one group of people and we shall build a happy India. We shall also then replace this capitalist run Government by a true socialist pattern, democratic Government.

श्री शिवपूजन शास्त्री (विक्रमगंज) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं पक्ष तथा विपक्ष में तथा निर्दलीय माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं केवल तीन समस्याओं की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पहली समस्या तो देश की गरीबी के स्वरूप के बारे में है, दूसरी समस्या देश में योजना की है और तीसरी समस्या एक स्वस्थ राजनीतिक स्थिति की है ।

जहां तक गरीबी के इतिहास का सवाल है, दादा भाई नौरोजी ने 1870 में पहले पहल एक किताब लिखी थी पावर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया जिसमें उन्होंने दिखाया—और वह पहला प्रयत्न था इसको दिखाने का—कि इस मुल्क में एक आदमी की वर्ष भर में आय केवल तीस रुपये है, एक व्यक्ति की आमदनी एक रोज में उस समय केवल चार पैसे से भी कम थी । गांधी इर्विन पत्रव्यवहार में भी गांधी जी ने इर्विन को बताया था कि हमारा मुल्क कितना गरीब है और उसकी उन्होंने मिसाल पेश की कि 1931 में एक हिन्दुस्तानी की प्रतिदिन आमदनी सिर्फ छः पैसे की थी। अभी मैंने एक सवाल पूछा था वित्त मंत्री जी से कि देश की राष्ट्रीय आय क्या है, और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय कितनी पड़ती है । इसके जवाब में मुझे बताया गया है कि 313 रुपये है। इससे यह साबित होता है कि आज भी हिन्दुस्तान में एक आदमी की प्रतिदिन की आय एक रुपया से भी कम है। इससे आसानी से समझा जा सकता है कि एक रुपये में एक इंसान एक दिन में क्या खायेगा, कैसे जियेगा......

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (बलरामपुर): एक रुपया तो औसत है।

श्री शिवपूजन शास्त्री : अलग-अलग बांटें तो और कम है। यह गरीबी का स्वरूप है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जितनी जल्दी हो सके, जैसे हो सके, गरीबी को दूर करें। कोई भी व्यवस्था, कोई भी प्रबन्ध भला है या बुरा,

[श्री शिवपूजन शास्त्री]

उसकी कसौटी यही है कि वह व्यवस्था इस गरीबी को मिटाने में हमको कहां ले जा रही है। इस व्यवस्था को समझने के लिए हमको योजना को समझना जरूरी है।

यहां के समाज शास्त्री, यहां के अर्थ शास्त्री मानते हैं कि भारत का समाज अंध विश्वास, पाखंड और ढोंग में ग्रस्त है। समाज के हर इंसान में जब तक यह विश्वास पैदा नहीं किया जाता है कि तुम अपनी किस्मत के मालिक खुद हो, तुम अपनी मेहनत से अच्छी तरह से जी सकते हो अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो सहयोग से तुम्हें मदद मिल सकती है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है।

इस तरह की एक सामाजिक प्रवृत्ति, इस तरह का एक सामाजिक वातावरण पूरे देश में पैदा होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। अगर दोष ढूंढा जाये, तो दोष हम में भी हो सकता है, कांग्रेस में भी हो सकता है और अन्य दलों में भी हो सकता है। ये युग-युग से आती हुई हमारी रूढ़ियां, हमारा अन्ध-विश्वास और हमारा पाखंड इसके लिए जिम्मेदार है। उनको दूर करने के लिए जिस एक सामाजिक और दार्शनिक क्रान्ति की जरूरत थी, अभी वह देश में शुरू नहीं हुई। वह शुरू होना जरूरी है।

अगर देश में एक सामाजिक और बौद्धिक क्रान्ति हो जाये और हर इन्सान अपने को और दूसरे को भी इंसान समझे, तो जाति, प्रान्त और भाषा आदि के नाम ये जो लड़ाइयां इस मुल्क में हो रही हैं, वे नहीं होंगी। इस लिए दवा यही है कि हम अपने मुल्क में एक नई तहरीक, एक नया आन्दोलन, सबकी ओर से चलायें।

मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही इस के लिए जिम्मेदार है। जो रूढ़ियां हमारे देश में फैली हुई हैं, हमारे गांवों में और प्रान्तों में जो लड़ाई होती है, भाषा के नाम पर जो लड़ाई होती है, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, हम भी जिम्मेदार हैं और अन्य दल भी जिम्मेदार हैं। इस लिए हम सबको मिल कर यह सोचना पड़ेगा कि इस रूढ़ि को, इस गन्दी आदत को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। यहां मिलन की जरूरत है।

गरीबी के बारे में इस तरह का वातावरण तैयार करने के बाद योजनाओं के बारे में सबसे पहली गलती यह की गई कि इस सत्य से इन्कार किया गया कि भारतवर्ष एक कृषि-प्रधान देश है और भारत में आज सौ में से अस्सी, पचासी लोग कृषि पर जीवित हैं। इस लिए यहां पर सबसे बड़ा उद्योग, उद्योगों का भी उद्योग, जिन्हें बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं, उनका भी आधार कृषि है। इस लिए कृषि की तरक्की सबसे पहले होनी चाहिए थी।

पहली योजना में कृषि को थोड़ी प्रधानता दी गई। द्वितीय योजना में उसको बिल्कुल भुला दिया गया। अन्न संकट होने के बावजूद तीसरी योजना में उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब चौथी योजना में उस पर ध्यान देने की बात की जा रही है। मैं अपने गांव की एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। एक जगह एक परिवार को कृषि के लिए सारी सुविधायें मिलीं, तो एक बीघे में साठ मन धान पैदा किया गया। आज एक एकड़ में सौ मन धान पैदा किया जा सकता है। अगर हम सुविधायें दें, सिंचाई, खाद, कीट-नाशक दवा आदि दें, बढ़िया औजार उपलब्ध करें, तो हमारे यहां बहुत उपज हो सकती है, लेकिन मुसीबत यह है कि 32 करोड़ एकड़ जमीन जोत में है और अब तक सब मिलाकर अंग्रेजों के जमाने से लेकर कांग्रेस के जमाने तक, सिंचाई होती है सिर्फ 8 करोड़ एकड़ की। कब यह सरकार 32 करोड़ एकड़ की सिंचाई करेगी? इस दृष्टि से क्यों नहीं योजना बनाई जाती कि हमें पहले सिंचाई

करनी है, देश में अधिक से अधिक अन्न उपजाना है और दूसरों पर अपनी निर्भरता को खत्म करना है । इसके लिए हमको जितने रुपये की जरूरत है, वह हम को जुटाना चाहिए । रुपये के लिए साधन चाहिए ।

इस साल हम गांधी शताब्दी मना रहे हैं । इसलिए मैं याद करना चाहता हूँ विनोबा भावे को । उन्होंने ग्रामदान का एक आन्दोलन शुरू किया है मैं उसमें हिस्सा लेता रहा हूँ । बिहार में अठारह हजार गावों का ग्रामदान हुआ ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इतना सुन्दर भाषण हो रहा है, लेकिन सदन में कोरम नहीं है । कोई उसको सुनने वाला नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सुन्दर भाषण आप सुन रहे हैं न ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । कम से कम पचास सदस्य सदन में होने चाहिए ।

श्री शिव पूजन शास्त्री : माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि देश में पूंजी इकट्ठी करने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय विनोबा भावे जी ने बताया है । वह ग्रामदान के मार्फत कि हर गांव में बीघे में एक कट्ठा मन में एक सेर और जो सिर्फ आमदनी करते हैं, जिनके पास खेत नहीं हैं, वह सिर्फ एक दिन की आमदनी दे दें तो इस तरह से हर गांव में 2 हजार से 3 हजार की पूंजी, जो छोटा गांव है उसमें भी इकट्ठी हो सकती है और उस पूंजी के आधार पर हर साल उस गांव में ग्राम विकास का काम किया जा सकता है । इस तरह से पूंजी जुटाने का काम अपने मुल्क में किया जाय तो हम लोगों को कोई जरूरत नहीं होगी कि हम लोग विदेश पर हमेशा निर्भर करें और जब पूंजी हमको विदेश से मिले तब कोई विकास का कार्य करें । इस तरह से नीचे से योजना बनाने की परम्परा शुरू होनी चाहिए और ऊपर से जो योजना अब तक बनाते रहे हैं वह अध्याय समाप्त होना चाहिए ।

अब जो मध्यावधि चुनाव हुए उसके बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ । कोई भी जनतांत्रिक चुनाव सफल है या असफल है यह इस कसौटी पर जांचा जा सकता है कि विवेक के आधार पर मतदाताओं ने मत दिया या नहीं ? हमने उनकी भावनाएं जगाई, उन की जातीयता जगायी, उनका अन्धविश्वास जगाया, उनका पाखंड जगाया, उनकी गरीबी या उनकी मजबूरी से फायदा उठाया, उनको रुपया देकर उनके वोट खरीदे या उनमें जो भय की भावना है उससे फायदा उठाया, उनको डराकर धमका कर, वोट देने नहीं दिया और उनकी जगह पर दूसरे से वोट दिलवाया, मैंने किया या दूसरे ने किया, अगर इस तरह की कार्यवाहियां मुल्क में हुई हैं और इस आधार पर चुनाव लड़ा गया है तो यह चुनाव जनतंत्र की दृष्टि से सफल नहीं है । अगर आप इसकी समीक्षा करें तो आपको पता चलेगा कि 100 में से औसतन 40-50 या 60 मतदाता तो मत देने ही नहीं आये । उनका न आना किस बात का सुबूत है ? क्या इस बात का सुबूत नहीं है कि उनको जनतन्त्र में अविश्वास है, उनको यह विश्वास होता जा रहा है कि कोई हमारी भलाई नहीं करेगा, ये सब अपने-अपने लिये लड़ रहे हैं । अगर ऐसा विश्वास मतदाताओं के मन में पैदा हो रहा है तो यह जनतन्त्र के लिए खतरा है । किसी पार्टी का जीतना या हारना खतरा नहीं है मतदाताओं के मन में जनतन्त्र के प्रति अविश्वास पैदा होना बहुत खतरा है । इसलिये मैं इस माननीय सदन का ध्यान इस तरफ़ खींचना चाहता हूं और चाहता हूं कि हम सब मिलकर कोशिश करें कि इस तरह की कार्यवाहियां चुनावों में किसी की तरफ़ से न की जांय, तभी एक स्वस्थ जनतान्त्रिक वातावरण इस देश में तैयार हो सकता है ।

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Twenty-ninth Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : I beg to present the Twenty-ninth Report of the Business Advisory Committee.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

SHRI BISWANARAYAN SHASTRI : Mr. Speaker, Sir, I would like to speak a few words in support of the motion moved by Shrimati Sushila Rohatgi on the address delivered by the President to the joint session of the Houses. The President has rightly pin-pointed our attention to the variegated problems of the nation of which agriculture and industry are the main ones. Many things have been done in the field of agriculture and our agricultural production has reached an all-time record figure, but many more things have yet to be done.

Flood and drought created havoc in the past years. The worse type of floods visited last year Assam, West Bengal and Gujarat and drought prevailed in Rajasthan. As a result, our agricultural production was hampered and our country's economy has been ruined.

Flood is a perennial feature in Assam. In this connection, I would like to suggest that government should set up immediately the proposed Brahmputra Commission for thorough survey and proper investigation, which may on a later date be converted into a corporate body for taking measures to prevent floods in that State.

Even in the olden days the people of India used irrigation. In the fourth century A. D. Shavarasami, probably a person of the Godavari region, refers to extensive use of irrigation for paddy cultivation. It does not go to our credit that in the latter part of the 20th century we have no proper irrigation facilities. In the last session I put a question regarding irrigation facilities State-wise. After seeing that statement I am sorry to state that there is not a single inch of irrigation canal in the State of Assam whereas some other States have irrigation canals of 2,000 to 13,000 miles.

Then, manure is one of the important factors for increased agricultural production and the President has referred to the commissioning of a few fertilizer plants in the current year. But the fact remains that we are yet to import fertilisers from foreign countries by utilising our hard-earned foreign exchange. Emphasis should be shifted from importing fertilisers from foreign countries to import machinery for the installation of fertiliser plants in the land itself.

In this regard I would refer to agrarian reform. Agrarian reform remains by and large on paper. This is a socio-economic problem. This should be solved by peaceful methods ; otherwise, Naxalbari method will take its place.

Along with agriculture, industry is the important factor for the country's economy. In this respect more and more attention should be paid to agriculture-based industry and agriculture oriented industry. This has vast potentiality in the Indian background. If these industries are developed, it will reduce the gap between the urban economy and the rural economy. What is the ill of the society today ? It is that there is a big gap between the haves and the have-nots ; cities are going up and up with wealth whereas the rural population is living in abject poverty. This gap should be removed.

Regarding the public sector and the private sector industries, there is a great dispute. There is something wrong somewhere in the public sector industries. This wrong should be amended. According to figures Rs. 30,000 crores are invested in them. If the profit is 10 per cent annually, we should get Rs. 300 crores profit ; but instead we are losing Rs. 50 crores annually.

Appointment of general managers and managing directors should be made with an eye on their capability to run an industry, not from the purely administrative

point of view. The Indian Oil Corporation, its refinery section and the public sector refineries are placed under the charge of retired majors and generals. I wonder if military training has oil technology in its syllabus !

In respect of Location of industry I would also like to say that concentration of industry in a certain place has created regional imbalance in economic growth. The recent Telangana disturbance and other disturbances may be cited in this respect. There should not be regional imbalance. I would like to refer to Assam here. During the 21 years of independence except to the oil refinery at Gauhati and the Namrup fertiliser plant nothing has been given to Assam. If the people of a certain region feel that their region has been neglected and they are thrown to the wolves, it is not unlikely that they will become restive and the result is disturbance ? Government should keep this aspect in their view.

Even in respect of oil I would say that the price of oil in Assam is 10 per cent more than what it is in the rest of the country. For instance, the price of a litre of petrol in Assam is Rs. 1/10 whereas it is Re. 1 in Calcutta. Is there any place under the sun in this world that it costs higher where a thing is produced ? Such injustice should not be allowed to prevail.

I would like to refer to our foreign policy. Our foreign policy is of non-alignment. Non-alignment is good but friendlessness is unfortunate. We must have our friends, very dependable friends-friends who will not forsake us at the time of distress. We cannot ignore the lesson of history. Nazi Germany was a friend of Russia but that country was the first to attack Russia. After independence India cultivated fast friendship with Red China but that country was the first to attack independent India. Therefore, the lesson of history should be kept in mind.

Regarding national integration many things have been said. Ours is a multi-lingual country and India is a multi-racial nation. But, in spite of the fact, the concept of Indian nation was there. It is not the creation of the British imperialism. It was in our culture since very long ago.

I would like to ask one question. In the bygone days, when the people could not go out from their village, from their taluk, or when people of one region were stranger to other region, there was no regionalism as it is today. When there were big barriers between the communities, there was no communalism as it stands today. Why is there communalism and regionalism to such an extent today ? The reason is not far to seek of. It is the vested interests, the politicians, certain political parties, that keep it alive for their own interests. They exploit the religious sentiment of the people which is identified with communalism and the langauge sentiment which is identified with regionalism. These are the reasons which should be removed.

The Government have set up the National Integration Council. It has been doing good work. I would like to say that at least certain persons are invited to this Council and made the members of the Council not because of their broad vision of national integration but for the simple reason that they have completely identified themselves with certain regional interests and communal interests. It is such undue recognition which encourages the unscrupulous people to rise into prominence by adoption regionalism and communalism. Therefore, the question of national Integration should be viewed from a different angle.

In this respect, I would like to refer to our national heritage. In our heritage, there is clarity of ideals and clear conception about the mission of life. But now there is no clear conception. There is confusion everywhere, confusion in our thinking, contradiction in words and action and scepticism prevails. This has resulted into widespread violence.

The seers of India have said in *Visnupurana* :

[Shri Biswanarayan Shastri]

"उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् ।
वर्षं तत् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः ।।"

The people of India is one, that is, Bharatiya, that notion, that conception, should be kept in mind and that should be followed in our thought, in our words and in our deeds. I mean to say :

"कायेन मनसा वाचा ।"

Thank you.

Mr. SPEAKER: There are only two minutes more. Mr. Kachwai, you may take two minutes.

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में कुछ चीजों का उल्लेख नहीं किया गया है जैसे हरिजनों पर जो अत्याचार किया गया है उसका कोई जिक्र उसमें नहीं किया गया है और हालत यह है कि उनका विकास जिस गति से होना चाहिए वह उनका विकास व उद्धार नहीं हो रहा है—

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है कि सदन में इस समय कोरम नहीं है ।

MR. SPEAKER: Now the House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 A. M.

18 hours

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, February 26, 1969/Phalguna 7, 1890 (Saka)

Printed at : Navin Press, Delhi-6.